



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062021-227959
CG-DL-E-28062021-227959

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 28, 2021/आषाढ़ 7, 1943

No. 180]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 28, 2021/ASHADHA 7, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार और उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 28 जून, 2021

मामला सं. सीबीडी-04/2020

विषय: मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "7 एमएम डाया से अधिक के एल्युमीनियम वायर/वायर रॉड्स" के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी जांच।

फा. सं. 6/23/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (सब्सिडीयुक्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "सीबीडी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

- वेदांता लिमिटेड और भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (जिन्हें आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" अथवा "डीआई" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (सब्सिडीयुक्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे

"नियमावली" अथवा "सीवीडी नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार, मलेशिया (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "7 एमएम से अधिक एल्युमीनियम वायर/वायर रॉड्स" (जिसे आगे "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी जांच की शुरुआत के लिए घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र संयुक्त रूप से दायर किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा दायर प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत पर्याप्त आवेदन पत्र के आधार पर, आरोपित सब्सिडी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और सब्सिडीरोधी/प्रतिकारी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाती है और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 6 के अनुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 30 जून, 2020 की अधिसूचना सं. 6/3/2020-डीजीटीआर द्वारा एक सब्सिडीरोधी जांच शुरू की।

ख. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- (i) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6 के उप नियम (5) के अनुसार, जांच शुरू करने के लिए कार्रवाई से पूर्व वर्तमान आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- (ii) परामर्श 29 जून, 2020 को किया गया था और मलेशिया सरकार के अधिकारियों ने उसमें भाग लिया था। मलेशिया सरकार ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा कुछ कार्यक्रमों को न लेने और कुछ कार्यक्रमों की मौजूदगी अथवा लागू होने की स्थिति से इंकार किया था। तदनुसार, कार्यक्रम संख्या 14, 20 और 22 को जांच के क्षेत्र से बाहर किया गया था।
- (iii) प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 जून, 2020 की अधिसूचना जारी की।
- (iv) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग और आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गए पत्रों के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।
- (v) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 7(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध करायी। साथ ही, वैश्विक महामारी और वास्तविक रूप से पहुँच से बाहर होने के मद्देनजर सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे ई-मेल के द्वारा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ अपने अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर साझा करें।
- (vi) भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों को यह सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति भी संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पत्रों सहित उन्हें भेजी गई थी।
- (vii) प्राधिकारी ने विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में संगत तथ्य/सूचना मंगाने के लिए संबद्ध देश की सरकार को भी प्रश्नावली भेजी जहां सरकार द्वारा प्रतिकार योग्य लाभ प्रदान किया गया है। मलेशिया सरकार ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए जिनको भी ध्यान में रखा गया है।
- (viii) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार संगत सूचना मंगाने के लिए संबद्ध देश में ज्ञात निम्नलिखित उन उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी जिनके ब्यौरे आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे:

क. मैसर्स प्रेस मेटल सारावक एसडीएन. बीएचडी.

ख. मैसर्स प्रेस मेटल बिनतुलु एसडीएन. बीएचडी.

- (ix) संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:
- क. मैसर्स प्रेस मेटल बिनतुलु एसडीएन. बीएचडी. ("पीएमबीटीयू")
 - ख. मैसर्स प्रेस मेटल एल्युमीनियम रॉड्स एसडीएन. बीएचडी. ("पीएमएआर")
- (x) जांच की शुरुआत की अधिसूचना के अनुसरण में, संबद्ध देश से उपर्युक्त उत्पादकों/निर्यातकों के अलावा, मलेशिया सरकार ने भी प्रश्नावली के उत्तर दायर किए।
- (xi) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के उन निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशनों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे और उन्हें सलाह दी कि वे नियम 7(4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें:
- क. मैसर्स पॉलीकेब इंडिया प्रा. लि.
 - ख. मैसर्स प्रेम केबिल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - ग. मैसर्स इलेक्ट्रोलोड (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड
 - घ. मैसर्स केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - ङ. मैसर्स डायनमिक केबिल्स लिमिटेड
 - च. मैसर्स ओसवाल केबिल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - छ. मैसर्स अनविल केबिल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - ज. मैसर्स नेक्कोन पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड
 - झ. एल्युमीनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया
 - ञ. ऑल इंडिया नॉन-फेरस मेटल एक्जिम एसोसिएशन
 - ट. इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
- (xii) निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशनों ने वर्तमान जांच में अनुरोध अथवा प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:
- क. मैसर्स लुमिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - ख. मैसर्स ओसवाल केबिल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - ग. मैसर्स प्रेम केबिल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - घ. मैसर्स डायनमिक केबिल्स लिमिटेड
 - ङ. इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ("आईईईएमए")
- (xiii) जिन निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है अथवा इस जांच से संगत सूचना नहीं दी है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।
- (xiv) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- (xv) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। बाद में, कोविड-19 की वैश्विक महामारी को देखते हुए सार्वजनिक फाइल की हार्ड कॉपी पहुँच से बाहर होने के कारण सभी

हितबद्ध पक्षकारों से यह कहा गया था कि वे ई-मेल के द्वारा सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ अपने सभी अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर साझा करें।

- (xvi) वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2019 से दिसंबर, 2019 (09 माह) मानी गई है। तथापि, क्षति जांच अवधि में 2016-17, 2017-18, 2018-19 की अवधियां और जांच की अवधि शामिल होगी। आवेदकों द्वारा प्रस्तावित जांच की अवधि आयातों में वृद्धि, आयात कीमत में गिरावट और इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग पर परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर वर्तमान मामले में उपयुक्त मानी गई थी।
- (xvii) घरेलू उद्योग और उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन इस जांच के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।
- (xviii) क्षति रहित कीमत (एनआईपी) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर है। यह सुनिश्चित करने के लिए निकाली गई है कि क्या सब्सिडी मार्जिन से कम प्रतिकारी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (xix) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए लेन-देन वार आंकड़ों के संबंध में प्राप्त सूचना भारत में संबंधित उत्पाद के आयातों की मात्रा और मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाई गई है।
- (xx) नियमावली के नियम 7(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 24 मई, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से उनके विचार प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, उन सभी को लिखित अनुरोध दायर करने और उसके बाद प्रत्युत्तर, यदि कोई है, दायर करने का अवसर प्रदान किया गया था।
- (xxi) इस जांच प्रक्रिया के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध जहां संगत पाए गए, इन अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा हल कर दिए गए हैं।
- (xxii) जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन अंतिम जांच परिणामों में रिकार्ड किया है।
- (xxiii) नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के अनिवार्य तथ्य ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 18 जून, 2021 के प्रकटन विवरण द्वारा प्रकट किए गए थे और उन पर प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई प्राप्त टिप्पणियों को इन अंतिम जांच परिणामों में हल कर दिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर प्रकटन पश्चात अनुरोध उनके पूर्व अनुरोधों की केवल पुनरावृत्ति हैं। तथापि, संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन पश्चात अनुरोधों की इन अंतिम जांच परिणामों में जांच की जा रही है।
- (xxiv) इस अधिसूचना में *** गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- (xxv) संबद्ध जांच के लिए जांच की अवधि के दौरान प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.24 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद जांच की शुरुआत की सूचना में "7 एमएम डाया से अधिक के एल्युमीनियम वायर/वायर रॉड" के रूप में परिभाषित किया गया था। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में अलॉयड और नॉन-अलॉयड/वायर रॉड्स दोनों शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्री

एल्युमिना है। विचाराधीन उत्पाद एल्युमिना को पिघलाकर प्राप्त प्राथमिक एल्युमीनियम तत्व धातु की ढलाई पर उत्पादित और प्राप्त किया जाता है। वायर/वायर रॉड कचरे को पिघलाकर भी उत्पादित किए जा सकते हैं। कचरे के माध्यम से उत्पादित वायर रॉड विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर है।

5. विचाराधीन उत्पाद का प्राथमिक रूप से प्रयोग इलेक्ट्रिकल उद्योग, इस्पात उद्योग और अन्य में किया जाता है। यह उत्पाद सीमा शुल्क शीर्ष 76011040, 76012040, 76041010, 76042920, 76051100 और 76052100 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 76 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और इस जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- विचाराधीन उत्पाद में 7 एमएम से अधिक के क्रॉस सेक्शनल डायामीटर वाले कॉइल रूप में अलॉयड और नॉन-अलॉयड एल्युमीनियम वायर रॉड, 7 एमएम से अधिक के क्रॉस सेक्शनल डायामीटर वाले एल्युमीनियम वायर और 7 एमएम से अधिक के क्रॉस सेक्शनल डायामीटर वाले कॉइल रूप में एल्युमीनियम रॉड शामिल हैं।
 - विचाराधीन उत्पाद में कॉइल रूप में न होने वाले एल्युमीनियम वायर रॉड अर्थात् छड़/सीधे रूप में वायर रॉड, कॉइल रूप में न होने वाले एल्युमीनियम रॉड अर्थात् छड़/सीधे रूप में रॉड और 7 एमएम से कम के क्रॉस सेक्शनल डायामीटर वाले कॉइल रूप में एल्युमीनियम वायर शामिल नहीं हैं।
 - याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध सामानों में कोई अंतर नहीं है।
 - घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित उत्पाद की समान वस्तु है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- याचिका में विचाराधीन उत्पाद "एल्युमीनियम वायर रॉड" उल्लिखित है जो सीमा प्रशुल्क शीर्ष 7604 और 7601 के अंतर्गत वर्गीकृत है। परंतु जांच की शुरुआत की अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क शीर्ष 7605 के तहत "7 एमएम डायामेटर से अधिक के एल्युमीनियम वायर" जोड़ने के लिए परिवर्तित किया गया है।
 - संगत अध्यायों के अंतर्गत प्रशुल्क वर्गीकरण और परिभाषाएं यह दर्शाते हैं कि वे भिन्न-भिन्न उत्पाद हैं।
 - आवेदकों की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, घरेलू उद्योग केवल 9 एमएम से 12.5 एमएम डायामेटर तक के एल्युमीनियम वायर का उत्पादन करता है। अतः 9 एमएम से कम और 12.5 एमएम से अधिक के वायर को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए। भारत में विचाराधीन उत्पाद की आयात मात्रा में केवल 9 एमएम से 12.5 एमएम डायामेटर का एल्युमीनियम वायर भी शामिल किया जाना चाहिए। प्रचालन परिपाटियों की नियम पुस्तिका का पैरा 3.10 इसका समर्थन करता है। यह कई पाटनरोधी शुल्क जांचों में भी निरंतर पाया गया था।
 - कचरे के माध्यम से उत्पादित वायर रॉड विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखे जाने का इरादा था।
 - एल्युमीनियम वायर और एल्युमीनियम वायर रॉड इस अर्थ में दो भिन्न उत्पाद किस्में हैं कि छड़ और रॉड कॉइल में नहीं हैं जबकि वायर कॉइल में हैं, जैसा कि सीमा प्रशुल्क वर्गीकरणों से देखा जा सकता है।
 - एल्युमीनियम वायर और वायर रॉड उत्पादन प्रक्रिया, स्वरूप, लचीलेपन, अंतिम प्रयोगों, डायामीटर और लंबाई में भिन्न हैं और इस प्रकार तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से परस्पर परिवर्तनीय नहीं हैं।
 - एल्युमीनियम वायर केबिल और कंडक्टर्स के विनिर्माण के लिए उपयुक्त है जबकि वायर रॉड उपयुक्त नहीं है।

- (viii) विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से 7.6 एमएम से कम डायमीटर वाले एल्युमीनियम वायर अलग किए जाने चाहिए, जैसा कि याचिकाकर्ता ने उन्हें आयात आंकड़ों के विक्षेपण में अलग किया है।
- (ix) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित न किए गए उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए और पाटनरोधी जांचों में अपनाई गई परिपाटी प्रतिकारी शुल्क जांचों पर भी समान रूप से लागू है। ऑक्सो एल्कोहॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी का संदर्भ दिया जाता है जिसमें माननीय सेसटेट ने माना है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित न किए गए उत्पाद विचाराधीन उत्पाद नहीं हो सकते क्योंकि कोई क्षति नहीं हो सकती।
- (x) वायर रॉडों को शामिल करने के मामले में, विचाराधीन उत्पाद को दो भिन्न श्रेणियों में अलग-अलग किया जाना चाहिए और संशोधित आंकड़े मंगाए जाने चाहिए।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

8. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और घरेलू उद्योग द्वारा पेशकेश की गई समान वस्तु के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिये गये अनुरोधों को नोट किया है। किसी जांच में सबसे पहला कदम विचाराधीन उत्पाद की पहचान करना होता है। विचाराधीन उत्पाद आयात किया गया वह उत्पाद है जो कथित रूप से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों के आधार पर और आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं का आयात संबद्ध देश से केवल क्वाइल फॉर्म में किया गया है। तदनुसार प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "9 मिमि. से 13 मिमि. तक के व्यास वाले क्वायल रूप में एल्युमिनियम वायर/ क्वायल रूप में वायर रॉड" है। विचाराधीन उत्पाद में एलॉय किया गया और बिना एलॉय किये गये दोनों तार शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करने के लिए उपयोग किया गया प्रमुख कच्चा माल एल्यूमिना है। विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और उसे एल्यूमिना को गलाकर प्राप्त किया गया प्राथमिक एल्यूमिनियम गरम धातु को डालकर प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम तार का भी उत्पादन स्क्रैप को लगाकर किया जाता है। स्क्रैप के माध्यम से उत्पादन किया गया एल्यूमिनियम तार विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से परे है।
9. इस उत्पाद का वर्गीकरण सीमा प्रशुल्क शीर्ष 76011040, 76012040, 76041010, 76042920, 76051100 और 76052100 के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 के अध्याय 76 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया एल्यूमिनियम तार संबद्ध देश से उत्पाद किया गया एल्यूमिनियम तार का समान वस्तु है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादन किये गये संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयात किये गये संबद्ध वस्तु इन वस्तुओं के उत्पाद की विशेषताओं, निर्माण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और प्रशुल्क वर्गीकरण के मामले में सामूहिक रूप से और संचयी रूप से तुलनीय हैं। प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए विचाराधीन उत्पाद सब्सिडीरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देश से आयात किया गया संबद्ध विचाराधीन उत्पाद का समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

10. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - (i) आवेदकों का विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उत्पादन में "प्रमुख अनुपात" है और आधार की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं तथा नियमावली के अभिप्राय से "घरेलू उद्योग" है।
 - (ii) स्टर्लाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ("एसपीटीएल") ने संबद्ध देश अथवा किसी अन्य देश से जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

- (iii) आवेदक अन्य देशों से तथाकथित सब्सिडीयुक्त वस्तु अथवा समान वस्तु के निर्यातकों से संबद्ध नहीं है अथवा खुद आयातक है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

11. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे यह जांच करें कि क्या वेदांता लिमिटेड और बाल्को सीवीडी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग हैं।
- (ii) यदि विचाराधीन उत्पाद "7 एमएम डाया से अधिक के एल्युमीनियम वायर" है तो फिर वेदांता लिमिटेड और बाल्को के "घरेलू उद्योग" के रूप में आधार का नए सिरे से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- (iii) अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन का अस्पष्ट अनुमान अविश्वनीय है। प्राधिकारी को अन्य दो बड़े उत्पादकों से सूचना मंगानी चाहिए और यह जांच करनी चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग का हिस्सा 50 प्रतिशत (कुल उत्पादन से वेदांता की एसईजेड यूनिट को अलग करने के बाद) से अधिक है।
- (iv) प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे उन कारणों की जांच करें जिनके कारण हिंडाल्को और नाल्को, जो विचाराधीन उत्पाद के प्रमुख उत्पादक हैं, ने याचिका का समर्थन नहीं किया है।
- (v) यूएस-लैम्ब में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट में, रक्षोपाय करार के तहत "प्रमुख अनुपात" की आवश्यकता के घरेलू उद्योग के "प्रतिनिधित्व" की आवश्यकता स्पष्ट की गई थी। रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4(ग) के तहत घरेलू उद्योग एससीएम के अनुच्छेद 16.1 के तहत घरेलू उद्योग में प्रमुख है। अतः, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता सीवीडी जांचों में भी लागू है।
- (vi) भारत में प्रमुख उत्पादकों द्वारा भाग न लिए जाने से सीमलेस ट्यूबों, पाइपों और लोहे के खोखले प्रोफाइल, अलॉय अथवा गैर-अलॉय इस्पात के संबंध में पाटनरोधी शुल्क जांच रद्द हुई।
- (vii) वेदांता लिमिटेड एक आयातक अर्थात् एसपीटीएल से संबद्ध है। दूसरे देशों से वेदांता द्वारा आयातों, मलेशिया से एसपीटीएल द्वारा आयातों अथवा क्षति की अवधि में किसी अन्य देश से आयातों के संबंध में याचिका मौन है।
- (viii) याचिका में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या घरेलू उद्योग अथवा एसपीटीएल (वेदांता का संबद्ध आयातक) ने जांच की अवधि सहित क्षति जांच अवधि के दौरान किसी अन्य देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया। यदि आयात हैं तो ऐसे घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए। इसके संबंध में पूर्ण सूचना दी जानी चाहिए।
- (ix) याचिका में कुल उत्पादन अथवा याचिकाकर्ताओं का वास्तविक हिस्सा प्रकट नहीं किया गया है और न ही रेंज दी गई है।
- (x) एसपीटीएल द्वारा मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद के आयात से खरीद, तथाकथित रूप से सब्सिडीयुक्त सामानों के प्रयोग और बिक्री से लाभ लेकर तथाकथित सब्सिडियों के किन्हीं कुप्रभावों से घरेलू उद्योग का बचाव भी हो सकता है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

12. यह आवेदन पत्र वेदांता लिमिटेड और भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है (जिसे आगे "बाल्को" भी कहा गया है)।
13. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदकों के उत्पादन का कुल घरेलू उत्पादन में *** प्रतिशत हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, उपलब्ध सूचना के अनुसार यह नोट किया जाता है कि:
 - (क) आवेदकों ने संबद्ध देश अथवा अन्य किसी देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है।
 - (ख) आवेदक संबद्ध देश में अथवा किसी अन्य देश में संबद्ध सामानों के किसी उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध नहीं हैं।

(ग) आवेदक भारत में किसी ऐसे आयातक से संबद्ध नहीं हैं जिसने किसी देश से संबद्ध सामानों का आयात किया हो।

(घ) एसपीटीएल, वेदांता लिमिटेड से संबद्ध है, ने जांच की अवधि में किसी देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है।

14. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदकों के उत्पादन का समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है और आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग हैं। आवेदन पत्र नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।
15. इस दावे के संबंध में कि संबद्ध सामान के दो प्रमुख उत्पादकों, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि. और नेशनल एल्युमीनियम कं. लि. ने जांच में भाग नहीं लिया है और कोई सूचना नहीं दी है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी घरेलू उत्पादकों के लिए ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि वे किसी सब्सिडीरोधी जांच में घरेलू उद्योग के घटकों के रूप में भाग लें। नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार, जिन घरेलू उत्पादकों का कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है, उन्हें घरेलू उद्योग माना जा सकता है। वर्तमान मामले में, आवेदकों के उत्पादन का कुल घरेलू उत्पादन में *** प्रतिशत हिस्सा है और तदनुसार वे नियमावली के नियम 2(ख) के तहत प्रमुख अनुपात की अपेक्षा को पूरा करते हैं।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

16. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - (i) प्रयोक्ताओं द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर व्यापार सूचना के पूरे उल्लंघन में हैं क्योंकि सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध सूचना को रोकने के लिए कारण प्रकट किए अथवा उपयुक्त सार दिए बिना भी सूचना को गोपनीय होने का दावा किया गया है।
 - (ii) घरेलू उद्योग को प्राधिकारी द्वारा मांगी गई पूरक सूचना के संबंध में सूचित नहीं किया गया था। उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों को कमी वाले प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने और फिर बाद में कमियों को गोपनीय रूप से भरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह घरेलू उद्योग के हितों के प्रति पूर्वाग्रही होगा।
 - (iii) निर्यातकों द्वारा दायर पूरी पूरक सूचना रद्द की जानी चाहिए, यदि निर्यातक उसका अगोपनीय रूपांतर दायर न करना पसंद करे।
 - (iv) प्रेस मेटल बिनटुलु एसडीएन बीएचडी (पीएमबीटीयू) ने घरेलू स्रोतों और कार्यक्रम 23 से खरीदी गई कच्ची सामग्री के वितरण, मात्रा और मूल्य के चैनल के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। प्रेस मेटल एल्युमीनियम रॉड्स एसडीएन बीएचडी (पीएमएआर) ने कंपनी के स्वामित्व के इतिहास और वितरण के चैनल के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। प्रपत्र सी और पीएमएआर की उत्पादन प्रक्रिया के उत्तर व्यापार सूचना 10/2018 का उल्लंघन करते हैं।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

17. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - (i) घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचनाओं की अनदेखी की है और इतनी अत्यधिक गोपनीयता के लिए कोई अच्छा कारण दर्शाने में विफल रहे। एनआईपी और अंतिम एनआईपी की गणना जानबूझकर गोपनीय होने का दावा किया गया है क्योंकि आयात कीमत एनआईपी से अधिक है। अतः घरेलू उद्योग को आवश्यक सूचना सहित संशोधित याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, सीवीडी नियमावली के नियम 8 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना-

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे सभी अपने अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल करें क्योंकि चल रही वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल वास्तविक रूप से पहुँच में नहीं थी।

20. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की संगत मानी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी और तदनुसार उन्हें हल किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।

च. विविध अनुरोध**च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

21. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- (i) मलेशिया सरकार (जीओएम) द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर अपूर्ण और अपर्याप्त हैं तथा सहयोग के उस स्तर पर प्रश्न चिह्न लगता है जिसकी मलेशिया सरकार से आशा की जा सकती है। मलेशिया सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे पूरी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें और यदि नहीं करते हैं तो उत्तर को रद्द किया जाना चाहिए।
- (ii) मलेशिया सरकार ने केवल कार्यक्रम संख्या 5 (अग्रणी स्थिति), कार्यक्रम संख्या 8 (वर्धित पूंजी भत्ता), कार्यक्रम संख्या 11 (औद्योगिक भवन भत्ता), कार्यक्रम संख्या 12 (संयंत्रों और मशीनरी के लिए भत्ता), और कार्यक्रम संख्या 23 (भूमि और विद्युत के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक से कम) का ही उत्तर दिया है।

- (iii) मलेशिया सरकार ने विगत में प्राधिकारी द्वारा उस छूट के संबंध में दो निर्धारणों के बावजूद बिक्री कर पर छूट के लिए संगत अनुबंधों और मानक प्रश्नावली के उत्तर नहीं दिये हैं जिसमें उत्पादक को दो बार – खरीदी गई कच्ची सामग्री पर छूट और की गई बिक्री पर छूट का लाभ मिलता है तथा वर्तमान मामले में भी संगत है क्योंकि निर्यातक उत्पादकों ने इस कार्यक्रम से लाभ लिया है।
- (iv) मलेशिया सरकार का यह दायित्व है कि यदि कार्यक्रम गैर-प्रतिकारी भी है तो लागू किसी कार्यक्रम को वे प्रकट करें और प्रश्नावली का पूरी तरह से उत्तर दें।
- (v) मलेशिया सरकार ने उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों तक ही अपना उत्तर प्रतिबंधित किया है न कि संबद्ध सामानों के देशव्यापी उत्पादकों/निर्यातकों तक।
- (vi) प्राधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि मलेशिया सरकार और निर्यातकों द्वारा दी गई पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में सूचना पूरे उपयोगी जीवनकाल (एयूएल) अवधि के लिए है और क्या ऐसे कोई लाभ जांच की अवधि में भी जा रहे हैं। संयंत्र और मशीनरी के लिए 15 वर्षों के एयूएल पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II (धारा 123) के अनुसार विचार किया जाए।
- (vii) एयूएल अवधि के लिए सूचना कार्यक्रम संख्या 8 : वर्धित पूंजी भत्ता, कार्यक्रम संख्या 11: भत्ता औद्योगिक भवन/औद्योगिक भवन भत्ता (आईबीए), कार्यक्रम संख्या 12: संयंत्रों और मशीनरी के लिए भत्ता, कार्यक्रम संख्या 17: मशीनरी और उपस्करों पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट तथा कार्यक्रम संख्या 18: कच्ची सामग्री/संघटकों पर आयात शुल्क से छूट, के लिए मंगाई जानी चाहिए और ये आंकड़े न दिए जाने में किसी विफलता को असहयोगी माना जाना चाहिए।
- (viii) उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर अपर्याप्त हैं।
- (ix) लाभ की पर्याप्त मात्रा पिघलाने के स्तर पर प्राप्त की जाती है। पीएमएआर के पास पिघलाने के लिए एकीकृत संयंत्र नहीं है और इस प्रकार या तो पीएमबीटीयू से अथवा प्रेस मेटल सारावक एसडीएन. बीएचडी. (पीएमएस) से इनपुट खरीदता है। पीएमएस वर्तमान जांच में असहयोगी है और इसीलिए पीएमएआर के उत्तर भी रद्द किए जाने चाहिए।
- (x) पूरी एयूएल अवधि के दौरान पीएमबीटीयू द्वारा आयातित सभी मशीनरी और अन्य संघटकों पर शुल्क छूट की मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए और जांच की अवधि के दौरान प्राप्त किसी सब्सिडी की मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए।
- (xi) पीएमएआर ने प्रकट किया है कि वे 2014 में कार्यक्रम संख्या 17 (मशीनरी और उपस्करों पर आयात शुल्क और बिक्री कर पर छूट) के तहत लाभ के लिए अनुमोदित थे और 2015 में प्राप्त किए, जिससे वह जांच की अवधि तक बढ़ाई गई थी। प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह लाभ एक समूह कंपनी द्वारा ही प्रकट क्यों किया गया है। चूंकि पीएमएस ने भी लाभ प्राप्त किया होता, परन्तु सहयोग नहीं किया, अतः उपलब्ध तथ्य मात्रा निर्धारित करने के लिए लागू किए जाने चाहिए।
- (xii) न तो पीएमबीटीयू और न ही पीएमएआर ने आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा सूचीबद्ध कार्यक्रमों को छोड़कर, किसी कार्यक्रम के संबंध में, सूचना देने का दायित्व होने के बावजूद, सूचना दी है जिससे उनकी प्राधिकारी के साथ पूरी तरह से सहयोग न करने की इच्छा सामने आती है। हितबद्ध पक्षकारों ने तथ्यों को छिपाने का सहारा लिया है।
- (xiii) मलेशिया सरकार ने प्रश्नावली के उत्तर कंपनियों को वित्तीय अंशदान प्रदान करने वाली सरकारी संस्थाओं के कार्यचालन और उद्देश्यों के अनुबंधों के संबंध में सूचना नहीं दी है।
- (xiv) पीएमबीटीयू और पीएमएआर द्वारा कार्यक्रम संख्या 1, 3, 4, 10, 15-18 लेने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है। कार्यक्रम 1-4, 6-7, 9-10 और 13-22 के लिए मानक प्रश्नों के अनुबंधों का कोई उत्तर नहीं दिया गया है। कार्यक्रम 5 के लिए कोई आबंटन अनुबंध दिए गए हैं और एयूएल अवधि के लिए सूचना कार्यक्रम 8, 11 और 12 के लिए नहीं दी गई है।

- (xv) उपयोग में लाई गई कच्ची सामग्री प्रदर्श में उपलब्ध नहीं है। कार्यक्रम 1-7, 10 और 15 लेने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है। कार्यक्रम 8, 11 और 12 तथा कार्यक्रम 1-7, 9-10, 13-16 और 19-23 के लिए मानक प्रश्नों के अनुबंधों के लिए कोई उत्तर नहीं दिया गया है। कार्यक्रम 8, 11, 12 और 17 के लिए एयूएल अवधि के लिए सूचना नहीं दी गई है।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- क. प्राधिकारी ने किसी भी कार्यक्रम के लिए एयूएल अवधि के संबंध में कोई सूचना नहीं मांगी है।
- ख. एयूएल अवधि के लिए सूचना केवल उन कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित है, जिनके लिए एकबारगी लाभ प्राप्त किया जाता है और यह लाभ एयूएल अवधि में आबंटित किया जाना अपेक्षित होता है। एयूएल अवधि के संबंध में पीएमबीटीयू और पीएमएआर के प्रश्नावली के उत्तर में, जहां लागू हो, सूचना दी जाती है।
- ग. घरेलू उद्योग ने माना है कि एयूएल अवधि के लिए कार्यक्रमों के संबंध में सूचना नहीं दी जाती है, जब पीएमएआर और पीएमबीटीयू ने स्वीकार नहीं किया है कि उन्होंने लाभ प्राप्त किया है। घरेलू उद्योग ने यह नहीं दर्शाया है कि सब्सिडी कार्यक्रमों का प्रयोग न करने के संबंध में दावे के समर्थन में क्या साक्ष्य दिया जा सकता है। सभी मामलों में सब्सिडी कार्यक्रमों का प्रयोग न करने के संबंध में साक्ष्य देना संभव नहीं है।
- घ. पीएमएस विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण अथवा निर्यात में नहीं लगा हुआ है। पीएमबीटीयू और पीएमएआर विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण के लिए पीएमएस से किसी कच्ची सामग्री की खरीद नहीं करते हैं।
- ङ. पीएमएआर और पीएमबीटीयू ने एयूएल अवधि के दौरान पीएमबीटीयू और पीएमएआर द्वारा आयातित सभी मशीनों तथा संघटकों पर आयात शुल्क की छूट, यदि कोई है, के संबंध में सूचना दी है।
- च. मलेशिया सरकार ने प्रश्नावली के उत्तर में पूरी सूचना दी है। मलेशिया सरकार के प्रश्नावली के उत्तर में सूचना का अभाव संगत नहीं है क्योंकि पीएमएआर और पीएमबीटीयू ने कानूनी आधार और कार्यक्रम के तहत प्राप्त लाभ की राशि, यदि कोई है, के संबंध में भी पूरी सूचना दी है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

23. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के सभी तर्कों और प्रति-तर्कों को नोट किया है और किए गए अनुरोधों के सभी पहलुओं की जांच की है।

- क. जहां तक विशिष्ट सब्सिडी कार्यक्रमों से संबंधित दावे का संबंध है, प्राधिकारी ने प्रत्येक सब्सिडी कार्यक्रम की जांच करते समय जांच को नोट किया है।
- ख. जहां तक मलेशिया सरकार द्वारा सभी तथाकथित सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए अपर्याप्त सूचना से संबंधित दावे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मलेशिया सरकार ने मलेशिया से प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रयुक्त कार्यक्रमों के कानूनी आधार के संबंध में प्रश्नावली के उत्तर में सूचना दी है और उस पर प्रत्येक सब्सिडी कार्यक्रम की जांच करते समय विचार किया गया है। प्राधिकारी ने उन कार्यक्रमों के कानूनी आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना पर विश्वास किया है जिनके लिए मलेशिया सरकार द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी।
- ग. जहां तक एयूएल अवधि के लिए सूचना से संबंधित दावे का संबंध है, प्राधिकारी के पास संगत कार्यक्रमों के लिए एयूएल अवधि के लिए उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों से सूचना है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एयूएल अवधि के लिए सूचना कार्यक्रम संख्या 8 : वर्धित पूंजी भत्ता, कार्यक्रम संख्या 11: भत्ता औद्योगिक भवन/औद्योगिक भवन भत्ता (आईबीए), कार्यक्रम संख्या 12: संयंत्रों और मशीनरी के लिए भत्ता, कार्यक्रम संख्या 18: कच्ची सामग्री/संघटकों पर आयात शुल्क से छूट, के लिए अपेक्षित नहीं है क्योंकि ये कार्यक्रम प्रकृति में आवर्ती हैं।

- घ. जहां तक याचिका में आरोप न लगाए गए अन्य सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों से सूचना के अभाव से संबंधित दावे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने घरेलू उद्योग द्वारा अपने लिखित अनुरोध में दी गई सूचना के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा आरोपित अतिरिक्त सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच की है, यहां तक कि यद्यपि वह सूचना घरेलू उद्योग द्वारा देरी से दी गई थी और उसमें संगत कानूनी तथा तथ्यात्मक ब्यौरे नहीं थे। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में इन सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच करते समय अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना, डब्ल्यूटीओ एससीएम करार के प्रावधानों, अधिनियम और नियमावली को भी ध्यान में रखा है।
- ङ. जहां तक प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों के संबंधित पक्षकार (पीएमएस) के भाग न लेने से संबंधित दावे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीएमएस विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण में नहीं लगा हुआ है। साथ ही, यह नोट किया जाता है कि पीएमबीटीयू और पीएमएआर विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण के लिए पीएमएस से कोई कच्ची सामग्री नहीं खरीदते। अतः पीएमएस के लिए वर्तमान जांच में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर करने की कोई अपेक्षा नहीं है।

च. सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच

च.1 कार्यक्रम संख्या 1 – बाजार विकास अनुदान

24. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

- क. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि इस योजना का संचालन वित्त मंत्रालय, मलेशिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय और मलेशिया विदेश व्यापार विकास सहयोग द्वारा किया जाता है। इस योजना में निर्यात संवर्धनात्मक क्रियाकलापों, यथा – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में प्रतिभागिता के लिए मलेशियाई एसएमई को अनुदान दिया जाता है। एमडीजी कार्यक्रम के तहत किसी एसएमई के लिए अधिकतम अनुदान आरएम 200,000 है। इस योजना में तीन प्रकार की पात्र कंपनियों की पहचान की जाती है: (1) एसएमई को कम से कम 60 प्रतिशत मलेशियाई इक्विटी स्वामित्व के साथ कंपनी अधिनियम, 2016 के तहत निगमित होना चाहिए और मलेशिया में निर्मित उत्पादों का निर्यातक होना चाहिए; (2) व्यापार पंजीकरण अधिनियम (1956) के तहत निगमित व्यावसायिक सेवा प्रदाता होना चाहिए अथवा व्यावसायिक सेवा प्रदाताओं के लिए संबंधित सांविधिक निकायों के तहत पंजीकृत होना चाहिए, कम से कम 60 प्रतिशत मलेशियाई इक्विटी स्वामित्व होना चाहिए और मलेशियाई सेवाओं का निर्यातक होना चाहिए; और (3) व्यापार एवं उद्योग एसोसिएशनों को रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी अथवा संबद्ध व्यावसायिक प्राधिकरण में पंजीकृत होना चाहिए।
- ख. साक्ष्य और कानूनी आधार बाजार विकास अनुदान, 2020 तथा कंटीन्यूस कास्ट कॉपर वायर रॉडों के आयातों से संबंधित सब्सिडीरोधी जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश हैं।

25. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

- क. न तो पीएमएआर और न ही पीएमबीटीयू ने जांच की अवधि के दौरान कार्यक्रम संख्या 1 से लाभ लिया, उसका प्रयोग किया अथवा उससे लाभान्वित हुआ।
- ख. याचिकाकर्ताओं ने जांच की अवधि के दौरान पीएमएआर अथवा पीएमबीटीयू को प्रदत्त लाभ का कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

26. प्राधिकारी द्वारा जांच

- क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाजार विकास अनुदान (एमडीजी) का आशय निर्यात संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में एसएमई की प्रतिभागिता बढ़ाना है। एमडीजी एसएमई को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, व्यापार एवं निवेश मिशन/निर्यात संवर्धन मिशनों, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, विदेशों में सुपर मार्केट, हाईपर मार्केट अथवा रिटेल सेंटरों में मलेशिया निर्मित उत्पादों के लिए सूचियन शुल्क जैसे निर्यात संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में उनकी प्रतिभागिता के लिए आरएम 200,000 तक प्रतिपूर्ति योग्य अनुदान प्रदान करता है।
- ख. इस सब्सिडी कार्यक्रम में निधियों के सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और इससे प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान किया जाता है। यह सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यातों पर है।

- ग. पीएमएआर और पीएमबीटीयू, संबद्ध देश से दो प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों ने इस कार्यक्रम से लाभ नहीं लिया। इस प्रकार, प्राधिकारी मानते हैं कि पीएमएआर और पीएमबीटीयू के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ मलेशिया में संबद्ध उत्पाद के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा लिया जा सकता है। अतः, प्राधिकारी मानते हैं कि मलेशिया के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

च.2 कार्यक्रम सं. 2 – व्यापार/उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार

27. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

- क. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि यह अवार्ड उत्कृष्ट मलेशियाई कंपनियों को मान्यता देने तथा उत्पादों और दी गई सेवाओं में निरंतर सुधार प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग (एमआईटीआई) द्वारा संचालित किया जाता है। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत मलेशिया में निगमित होना चाहिए; निरंतर कम से कम तीन वर्षों के लिए प्रचालन में होना चाहिए; और पिछले तीन क्रमिक वित्तीय वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने चाहिए।

- ख. इस पुरस्कार में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के श्रेणीकरण के आधार पर अन्य लाभों के साथ नकद पुरस्कार, प्रशिक्षण कार्यक्रम, वित्तपोषण की स्थिति और डिजाइन क्रियाकलापों में पहुँच शामिल है।

28. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

- क. पीएमएआर और पीएमबीटीयू, संबद्ध देश से दो प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों ने जांच की अवधि के दौरान उद्योग उत्कृष्टता अवार्ड नहीं लिया, उसका प्रयोग नहीं किया अथवा उससे लाभ नहीं लिया।

- ख. याचिकाकर्ताओं ने जांच की अवधि के दौरान पीएमएआर अथवा पीएमबीटीयू को प्रदत्त लाभ का कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

29. प्राधिकारी द्वारा जांच

- क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार/उद्योग उत्कृष्टता अवार्ड एमआईटीआई द्वारा मलेशियाई कंपनियों को पेश किए गए उत्पादों/सेवाओं की गुणवत्ता में उनके सुधार को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। यह अवार्ड नकद पुरस्कार प्रशिक्षण, कार्यक्रमों, डिजाइन क्रियाकलापों में पहुँच आदि के रूप में है।

- ख. इस सब्सिडी कार्यक्रम में निधियों के सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और इससे प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान किया जाता है। यह सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उन कुछ उद्यमों तक सीमित है जो पात्रता मानदंड पूरा करते हैं।

- ग. पीएमएआर और पीएमबीटीयू, संबद्ध देश से दो प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों ने इस कार्यक्रम से लाभ नहीं लिया। इस प्रकार, प्राधिकारी मानते हैं कि पीएमएआर और पीएमबीटीयू के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ मलेशिया में संबद्ध उत्पाद के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा लिया जा सकता है। अतः, प्राधिकारी मानते हैं कि मलेशिया के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

च.3 कार्यक्रम सं. 3 – निर्यात ऋण पुनर्वित्तपोषण

30. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

- क. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि ईसीआर योजना का संचालन मलेशिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेंट्रल बैंक ऑफ मलेशिया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ मलेशिया, बरहाड द्वारा किया जाता है और इसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्यातकों को अल्पकालिक लदान पूर्व तथा पश्चात वित्तपोषण का प्रावधान है। विनिर्माण तथा/ अथवा व्यापार और सामानों के निर्यात में लगे मलेशियाई उद्यम निर्यात ऋण प्राप्त कर सकते हैं और निर्यातक अपने निर्यात आदेश के मूल्य का 95 प्रतिशत तक वित्तपोषण प्राप्त कर सकते हैं।

31. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

- क. न तो पीएमएआर और न ही पीएमबीटीयू ने इस कार्यक्रम को प्राप्त किया, उसका प्रयोग किया अथवा उससे लाभ लिया।
- ख. याचिकाकर्ताओं ने जांच की अवधि के दौरान पीएमएआर अथवा पीएमबीटीयू को प्रदत्त लाभ का कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

32. प्राधिकारी द्वारा जांच

- क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ मलेशिया (एक्जिम बैंक) द्वारा संचालित किया जाता है। निर्यात ऋण पुनर्वित्तपोषण कार्यक्रम में उत्पादों के निर्यात के वित्तपोषण के लिए उद्यम को ऋण का प्रावधान है। यह कार्यक्रम बैंक द्वारा जारी निर्यात ऋण पुनर्वित्तपोषण दिशानिर्देश से शासित होता है जिसमें कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए उत्पाद की पात्रता (उत्पादों की नकारात्मक सूची जिसका रख-रखाव बैंक द्वारा किया जाता है) सहित पात्रता मानदंडों का प्रावधान है। यह सब्सिडी कार्यक्रम किसी क्षेत्र विशेष तक प्रतिबंधित नहीं है और मलेशिया में निगमित सभी कंपनियों को उपलब्ध है।
- ख. एक्जिम बैंक एक सरकारी स्वामित्व वाला विकास वित्तीय संस्था है। यह पूर्णतः मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इनकारपोरेटेड (इंक.) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। वित्त मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के तहत एक एजेंसी के रूप में एक्जिम बैंक की अधिदेशित भूमिका सरकार द्वारा निर्धारित है। यह निर्यात ऋण बीमा सेवाएं, निर्यात वित्तपोषण बीमा, विदेश में निवेश बीमा और गारंटी सुविधाएं प्रदान करते हुए गैर-पारंपरिक बाजारों पर जोर दिए जाने के साथ सामानों के निर्यात और आयात, सेवाओं और विदेश में परियोजनाओं का वित्तपोषण और समर्थन करने के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान करने हेतु है।
- ग. प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि एक्जिम बैंक एक सार्वजनिक निकाय है क्योंकि यह सरकार के स्वामित्व में है और सरकारी कार्य करने के लिए सरकारी प्राधिकरण में निहित है। तदनुसार, एक्जिम बैंक द्वारा दिया गया ऋण किसी सरकारी निकाय द्वारा निधियों के सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान है। प्राप्तकर्ता को प्रदत्त लाभ एक्जिम बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज की राशि और तुलनीय वाणिज्यिक ऋण पर लगाए गए ब्याज की राशि के बीच के अंतर के रूप में है। यह कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह निर्यात के संबंध में है।
- घ. पीएमएआर और पीएमबीटीयू, संबद्ध देश से दो प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों ने इस कार्यक्रम से लाभ नहीं लिया। इस प्रकार, प्राधिकारी मानते हैं कि पीएमएआर और पीएमबीटीयू के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ मलेशिया में संबद्ध उत्पाद के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा लिया जा सकता है। अतः, प्राधिकारी मानते हैं कि मलेशिया के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

च.4 कार्यक्रम सं. 4 – क्रेता ऋण गारंटी**33. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

- क. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम के तहत विदेशी क्रेताओं की एक्जिम बैंक की बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय गारंटी द्वारा सहायता की जाती है जिसमें उधारदाता बैंक को देय तथा ब्याज राशि के पुनर्भुगतान की गारंटी दी जाती है। मलेशियाई निर्यातक नकद संविदा लेने के लिए विदेशी क्रेता की मदद कर सकते हैं जबकि विदेशी क्रेता के पास उधारदाता से प्रतिभूत वित्तपोषण के माध्यम से संविदा देने का समय है जिसका एक्जिम बैंक की गारंटी द्वारा समर्थन किया जाता है। दिया गया साक्ष्य एक्जिम बैंक द्वारा क्रेता ऋण बीमा है। इस कार्यक्रम के तहत ऋण राशि एक नकद संविदा के समर्थन में आरएम 2 मिलियन का न्यूनतम मूल्य होना चाहिए और पुनर्भुगतान की अवधि कम से कम 2 वर्ष और अधिकतम 15 वर्ष होनी चाहिए।

34. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

- क. न तो पीएमएआर और न ही पीएमबीटीयू ने इस कार्यक्रम को प्राप्त किया, उसका प्रयोग किया अथवा उससे लाभ लिया।

ख. याचिकाकर्ताओं ने जांच की अवधि के दौरान पीएमएआर अथवा पीएमबीटीयू को प्रदत्त लाभ का कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

35. प्राधिकारी द्वारा जांच

क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम एक्जिम बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। इस कार्यक्रम को शासित करने वाला कोई कानून अथवा कानूनी विनियम नहीं है।

ख. प्राधिकारी ने पहले ही निर्धारित किया है कि एक्जिम बैंक एक सार्वजनिक निकाय है। इस कार्यक्रम के तहत एक्जिम बैंक वित्तीय संस्थाओं को विदेशी क्रेताओं से होने वाली चूक के कारण अपने निर्यातकों (ग्राहकों) द्वारा भुगतान न किए जाने के जोखिम के विरुद्ध गारंटी प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में निधियों के संभावित सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। प्राप्तकर्ता को प्रदत्त लाभ (i) एक्जिम बैंक से गारंटी लेने के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा दिए गए शुल्क और उस शुल्क जो ऐसी गारंटी के लिए किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक को दिया गया होता, के बीच के अंतर और (ii) प्रश्रुत उधारदाता बैंक को ऋण पुनर्भुगतान (एक्जिम बैंक की गारंटी के कारण सामान्य वाणिज्यिक ब्याज दर से कम के कारण) और उस राशि जो उस गारंटी के अभाव में देय होती (सामान्य वाणिज्यिक ब्याज दर के आधार पर) के बीच के अंतर के समतुल्य है।

ग. पीएमएआर और पीएमबीटीयू, संबद्ध देश से दो प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों ने इस कार्यक्रम से लाभ नहीं लिया। इस प्रकार, प्राधिकारी मानते हैं कि पीएमएआर और पीएमबीटीयू के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ मलेशिया में संबद्ध उत्पाद के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा लिया जा सकता है। अतः, प्राधिकारी मानते हैं कि मलेशिया के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

च.5 कार्यक्रम संख्या 5 – अग्रणी स्तर

36. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

क. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि जिस कंपनी को अग्रणी स्तर प्रदान किया गया है, वह कारपोरेट आय कर से कर छूट लेगी। यह कार्यक्रम उन संवर्धित क्रियाकलापों/उत्पादों में निवेश प्रोत्साहित करता है जो मलेशिया के लिए राष्ट्रीय एवं सामरिक महत्व के हैं। यह विनिर्माण क्षेत्र में अनुमोदित संवर्धित उत्पादों/क्रियाकलापों के लिए स्थानीय और विदेशी दोनों निवेशकों के लिए लागू होता है। आय कर के भुगतान से पांच वर्ष की आंशिक छूट प्रदान की जाती है। कंपनी अपने उत्पादन के दिन से शुरू करके छूट अवधि में अपनी सांविधिक आय के 30 प्रतिशत पर कर देती है। खपाए न गए पूंजीगत भत्तों और अग्रणी अवधि के दौरान हुई संचित हानियों को अग्रणीत किया जा सकता है और कंपनी की अग्रणी पश्चात आय से घटाया जाता है। इस कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया है:

- i. निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986
- ii. निवेश संवर्धन (संवर्धित क्रियाकलाप और संवर्धित उत्पाद) आदेश, 2012
- iii. "कंटीन्यूस कास्ट कॉपर वायर रॉड" के आयातों से संबंधित सब्सिडीरोधी जांच।
- iv. जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद XVI:1 और सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपाय संबंधी करार - मलेशिया के अनुच्छेद 25 के अनुसरण में नई और पूरी अधिसूचना दिनांक 5 अक्टूबर, 2017 [डब्ल्यूटी/टीपीआर/एस/292]
- v. <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
- vi. <https://www.treasury.gov.my/index.php/en/tax/item/1160-promotion-of-investment-act-1986.html>
- vii. मलेशिया और यूएस-सर्टेन फ्रोजन वार्मवाटर श्रिम्प के माध्यम से यूएस एक्सट्रूडेड रबर
- viii. वार्षिक रिपोर्ट, प्रेस मेटल, अग्रणी स्तर, पृष्ठ 164

37. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

- क. अग्रणी स्तर वित्त मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्री द्वारा निर्धारित संवर्धित क्रियाकलाप में प्रतिभागिता के लिए और संवर्धित उत्पाद का उत्पादन करने की इच्छा वाली किसी कंपनी को प्रदान किया जा सकता है। संवर्धित उत्पादों और क्रियाकलापों में विनिर्माण, कृषि और सेवाओं सहित सभी क्षेत्र शामिल हैं। कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहन अग्रणी स्तर और निवेश कर भत्ता है। कंपनी दोनों में से कोई प्रोत्साहन ले सकती है क्योंकि ये प्रोत्साहन पारस्परिक रूप से विशिष्ट हैं।
- ख. एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2 में सब्सिडी की मौजूदगी के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ताओं ने एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2 और अन्य संगत प्रावधानों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा दिया गया साक्ष्य अग्रणी स्तर कार्यक्रम के असंगत भी है।
- ग. अग्रणी स्तर कार्यक्रम के तहत सहायता करों से छूट के रूप में है। यदि कोई कंपनी कर हानि की स्थिति में है तो हानियों को अग्रणीत किया जा सकता है।
- घ. अग्रणी स्तर कार्यक्रम किसी उद्यम अथवा उद्यम समूहों, अथवा किसी उद्योग अथवा उद्योग समूहों के लिए विशिष्ट नहीं है क्योंकि पात्र संवर्धित उत्पाद अथवा क्रियाकलाप विशिष्ट माने जाने के लिए अत्यधिक व्यापक, विविध, विस्तृत और फैले हुए हैं। अग्रणी स्तर कार्यक्रम भी मलेशिया के अंतर्गत किसी भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं।
- ङ. उद्योगों को उद्योग समूह माने जाने के लिए पर्याप्त रूप से समान उत्पादों का उत्पादन करना चाहिए (यूएस-सॉफ्टवुड लम्बर IV)। अग्रणी स्तर कार्यक्रम के लिए पात्र श्रेणियों, उद्योगों, क्षेत्रों, उत्पादों अथवा क्रियाकलापों की संख्या "उद्योग समूह" माने जाने के लिए अत्यधिक विविध हैं। उद्योगों को उत्पादन में लगे व्यक्तियों की सीमित संख्या के रूप में माने जाने के लिए कुछ उद्योगों के लिए निश्चित और विशिष्ट होना चाहिए।
- च. यदि सब्सिडी व्यापक रूप से उपलब्ध है और पूरी अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है तो वह विशिष्ट नहीं है (यूएस-अपलैंड कॉटन)।
- छ. पीएमएआर ने इस कार्यक्रम को नहीं लिया, इसका प्रयोग नहीं किया और इससे लाभ नहीं लिया। पीएमबीटीयू को 2013 में अग्रणी स्तर अवार्ड किया गया था, जिससे पीएमबीटीयू 1 जनवरी, 2013 से 31 दिसंबर, 2017 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए कर छूट के लिए हकदार हो गया। पहले पांच वर्ष की समाप्ति पर अतिरिक्त पांच वर्षों की छूट प्रदान की गई थी। दिसंबर, 2017 में पीएमबीटीयू ने 31 दिसंबर, 2022 तक पांच वर्ष बढ़ाए जाने के लिए आवेदन किया था।
- ज. अग्रणी स्तर कार्यक्रम पांच से 15 वर्ष की बीच कर राहत अवधि के लिए सांविधिक आय के 70 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच आय कर छूट प्रदान करता है।
- झ. सीवीडी नियमावली के नियम 11 में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह जांच करें कि क्या सब्सिडी वस्तु के विनिर्माण, उत्पादन अथवा निर्यात में लगे सीमित संख्या में व्यक्तियों को प्रदान की गई है। सीवीडी नियमावली के अनुबंध-II, पैरा (1)(क) और (ख) में प्रावधान है कि सब्सिडी किसी वस्तु के विनिर्माण अथवा उत्पादन में लगे सीमित संख्या में व्यक्तियों को प्रदान की जा रही सब्सिडी के रूप में मानी जाती है जब प्रदान करने वाला प्राधिकारी स्पष्ट रूप से कुछ उद्यमों को सब्सिडी के लिए सीमित करे अथवा वस्तुतः पहुँच सीमित करे।
- ञ. अग्रणी स्तर कंपनी पूर्णतः घरेलू, पूर्णतः निर्यात के लिए अथवा दोनों के संयोजन के लिए हो सकती है। यह विविध उद्योगों में फैले प्राथमिक, विनिर्माण अथवा सेवाओं में से किसी में प्रचालन करते हुए मलेशिया में किसी राज्य के अंतर्गत स्थित हो सकती है। वस्तुतः विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत अग्रणी स्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट के तहत सूचीबद्ध 13 विनिर्माण उद्योगों में से 11 को उपलब्ध है।

38. प्राधिकारी द्वारा जांच

- क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 की धारा 5 से 25 में अग्रणी स्तर कार्यक्रम का प्रावधान है। इस कार्यक्रम में आय कर से छूट के रूप में कर प्रोत्साहन का प्रावधान है। छूट की अवधि के दौरान हुई हानियों को कर योग्य आय/निवल लाभ ऑफसेट करने के लिए उसके बाद के वर्षों के लिए अग्रणीत किया जा सकता है। यह कार्यक्रम संवर्धित उत्पादों/क्रियाकलापों की पूर्व निर्धारित सूची के लिए उपलब्ध है।

- ख. इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व, जो अन्यथा देय है, के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह पात्रता सूची में उल्लिखित संवर्धित क्रियाकलाप/उत्पाद के लिए उपलब्ध है। पीएमबीटीयू द्वारा दायर प्रश्नावली का उत्तर यह दर्शाता है कि जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के तहत उनके द्वारा (100 प्रतिशत आय कर छूट) लाभ प्राप्त किया गया है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि पीएमबीटीयू और पीएमएआर के लिए इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। पीएमएआर ने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम को नहीं लिया है, इसका प्रयोग नहीं किया है अथवा इससे लाभ नहीं लिया है। इस प्रकार प्राधिकारी मानते हैं कि पीएमएआर के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि पीएमएआर को छोड़कर मलेशिया के सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

च.6 कार्यक्रम संख्या 6 – निवेश कर नीतियां/भत्ते

39. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

- क. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि जिस कंपनी को निवेश कर भत्ता (आईटीए) प्रदान किया गया है, वह प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए सांविधिक आय के विरुद्ध इस भत्ते को ऑफसेट करने की हकदार है। यह कार्यक्रम उस विनिर्माण क्षेत्र में संवर्धित क्रियाकलापों/उत्पादों में निवेश प्रदान करता है जो अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि में अंशदान कर सके। यह विनिर्माण क्षेत्र में अनुमोदित संवर्धित उत्पादों/क्रियाकलापों के लिए स्थानीय और विदेशी निवेशकों, दोनों के लिए लागू है। पहला अर्हक पूंजीगत व्यय करने की तारीख से पांच वर्षों के अंतर्गत किए गए अर्हक पूंजीगत व्यय पर 60 प्रतिशत का भत्ता दिया जाता है। कंपनी प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए अपनी सांविधिक आय के 70 प्रतिशत के विरुद्ध इस भत्ते को ऑफसेट कर सकती है। उसकी शेष सांविधिक आय पर विद्यमान कंपनी कर दर पर कर लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया है:

- i. निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986
- ii. जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद XVI:1 तथा सब्सिडी और प्रतिकारी उपाय संबंधी करार - मलेशिया के अनुच्छेद 25 के अनुसार नई और पूरी अधिसूचना दिनांक 5 अक्टूबर, 2017
- iii. <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
- iv. उन संवर्धित उत्पादों और क्रियाकलापों की सूची, जो निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 के तहत अग्रणी स्तर और निवेश कर भत्ता माने जाने के लिए पात्र हैं।

40. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

- क. न तो पीएमएआर और न ही पीएमबीटीयू ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया, उसका प्रयोग किया अथवा उससे लाभ प्राप्त किया।
- ख. याचिकाकर्ताओं ने जांच की अवधि के दौरान पीएमएआर अथवा पीएमबीटीयू को प्रदत्त लाभ का कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

41. प्राधिकारी द्वारा जांच

- क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 की धारा 26 से 29 में निवेश कर भत्ता कार्यक्रम का प्रावधान है। संवर्धित क्रियाकलापों तथा संवर्धित उत्पादों को पूंजीगत भत्ता प्रदान किया जाता है। मूल्यवर्धन और प्रौद्योगिकी अपेक्षाओं को भी पूरा किया जाना होता है। कुल पूंजीगत व्यय में से 60 प्रतिशत पूंजीगत व्यय भत्ते के रूप में प्रदान किया जाता है और पांच वर्षों के लिए सांविधिक आय के 70 प्रतिशत के विरुद्ध काटा जा सकता है। शेष आय पर सामान्य आय कर दर पर कर लगाया जा सकता है। यहां तक कि जो कंपनियां संवर्धित क्रियाकलाप, मूल्यवर्धन और प्रौद्योगिकी का स्तर पूरा करती हैं, उनके लिए भी मलेशियाई सरकार इस कार्यक्रम के तहत लाभ की मांग करने वाले आवेदक को रद्द करने का विवेकाधिकार रखती है।

- ख. इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उन कुछ उद्यमों के लिए सीमित है जो संवर्धित उत्पाद/क्रियाकलाप के मानदंड पूरा करते हैं और प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं। अग्रणी स्तर से आय कर छूट प्राप्त करने वाली कंपनी इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर सकती। पीएमएआर और पीएमबीटीयू, संबद्ध देश से दो प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों ने इस कार्यक्रम से लाभ नहीं लिया। इस प्रकार, प्राधिकारी मानते हैं कि पीएमएआर और पीएमबीटीयू के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने मलेशिया के सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अग्रणी स्तर कार्यक्रम पहले ही प्रतिकार कर दिया है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि मलेशिया के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

च.7 कार्यक्रम संख्या 7 – पुनर्निवेश भत्ता

42. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

- क. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम के तहत विनिर्माण क्रियाकलापों में उन विद्यमान कंपनियों को पुनर्निवेश भत्ता (आरए) दिया जाता है जो इस शर्त पर उसी उद्योग के अंतर्गत किसी भी संबंधित उत्पाद में अपने विद्यमान व्यापार के विस्तार, स्वचालन, आधुनिकीकरण अथवा विविधीकरण के प्रयोजन के लिए निवेश करती हैं कि वे कंपनियां निर्धारण वर्ष 2009 से प्रभावी कम से कम 36 माह के लिए प्रचालन में रही हैं।
- ख. मलेशिया में स्थित किसी कंपनी अथवा व्यक्ति को आरए प्रदान किया जाता है, यदि व्यापार कम से कम 36 माह के लिए प्रचालन में रहा है; अथवा कंपनी अथवा व्यक्ति ने निर्धारण वर्ष के लिए आधार अवधि में अर्हक परियोजना के प्रयोजन के लिए मलेशिया में प्रयुक्त किसी कारखाना, संयंत्र अथवा मशीनरी पर पूंजीगत व्यय किया है। आरए कंपनी द्वारा किए गए अर्हक पूंजीगत व्यय पर 60 प्रतिशत की दर पर दिया जाता है और निर्धारण वर्ष के लिए उसकी सांविधिक आय के 70 प्रतिशत के लिए ऑफसेट किया जा सकता है। उपयोग न किया गया कोई भत्ता पूरी तरह से उपयोग में लाए जाने तक परवर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जा सकता है। कोई कंपनी निर्धारण वर्ष के लिए अपनी सांविधिक आय के 100 प्रतिशत के लिए आरए ऑफसेट कर सकती है, यदि कंपनी वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्तर से अधिक उत्पादकता स्तर प्राप्त करती है। आरए प्रथम निवेश किए जाने के वर्ष से शुरू करके निरंतर 15 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाएगा।
- ग. कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया है:
- निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986
 - आय कर अधिनियम, 1967
 - "कंटीन्यूस कास्ट कॉपर वायर रॉड" के आयातों से संबंधित सब्सिडीरोधी जांच।
 - <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
 - वार्षिक रिपोर्ट, निवेश कर भत्ता, पृष्ठ 163

43. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

- क. न तो पीएमएआर और न ही पीएमबीटीयू ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया, उसका प्रयोग किया अथवा उससे लाभान्वित हुआ।
- ख. याचिकाकर्ताओं ने जांच की अवधि के दौरान पीएमएआर अथवा पीएमबीटीयू को प्रदत्त लाभ का कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

44. प्राधिकारी द्वारा जांच

- क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मलेशिया में स्थित कंपनी अथवा वहां के आवासी व्यक्ति को पुनर्निवेश भत्ता प्रदान किया जाता है, यदि कंपनी तीन वर्ष के लिए प्रचालन में है और उसने अर्हक परियोजना के लिए कारखाना संयंत्र और मशीनरी पर पूंजीगत व्यय किया है, ऐसे पूंजीगत व्यय के 60 प्रतिशत के लिए सांविधिक आय के 70 प्रतिशत से कटौती प्रदान की जाती है। पुनर्निवेश भत्ते का दावा उस निर्धारण वर्ष से आरंभ करके 15 वर्षों के लिए किया

जा सकता है, जिसमें दावा किया गया है। अंतर्देशीय राजस्व बोर्ड इस कार्यक्रम के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है।

- ख. इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व, जो अन्यथा देय है, के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और उससे लाभ प्रदान किया जाता है। यहां तक कि यद्यपि सब्सिडी कार्यक्रम संवर्धित क्रियाकलाप तक सीमित नहीं है, तथापि यह सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उस उद्यम के लिए उपलब्ध है जो कम से कम तीन वर्षों के लिए प्रचालन में रहा है और अर्हक परियोजना चला रहे हैं (विनिर्माण के संबंध में अपने विद्यमान व्यापार का विस्तार कर रहे हैं, आधुनिकीकरण कर रहे हैं अथवा स्वचालन कर रहे हैं)। प्राधिकारी ने कार्यक्रम संख्या 5 और 8 में सिफारिश की है कि भत्ते के माध्यम से सांविधिक आय से आय कर की छूट और कटौती प्रतिकार योग्य है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

च.8 कार्यक्रम संख्या 8 – वर्धित पूंजीगत भत्ता

45. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

- क. वर्धित पूंजीगत भत्ते (एसीए) में दो वर्षों के भीतर अर्थात् 20 प्रतिशत का आरंभिक भत्ता प्रथम वर्ष में और 40 प्रतिशत का वार्षिक भत्ता पूंजीगत व्यय को बढ़े खाते में डालने के लिए भत्तों का प्रावधान है। पुनर्निवेश भत्ते के लिए पात्रता 15 वर्ष की अवधि के बाद जो कंपनी संवर्धित उत्पादों के विनिर्माण में निवेश करती है, वह एसीए के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है। आवेदन पत्र एमआईडीए से यह प्रमाणित करते हुए कंपनियां संवर्धित क्रियाकलापों अथवा उत्पादों का विनिर्माण कर रही हैं, एक पत्र के साथ आईआरबी को प्रस्तुत किए जाने होते हैं।
- ख. इस कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया है:
- निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986
 - सार्वजनिक नियमावली संख्या 4/2013
 - "कंटीन्यूस कास्ट कॉपर वायर रॉड" के आयातों से संबंधित सब्सिडीरोधी जांच।
 - <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>

46. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

- क. एसीए में चार वर्षों के भीतर अर्थात् प्रथम वर्ष में 20 प्रतिशत के आरंभिक भत्ते और उसके बाद 20 प्रतिशत के वार्षिक भत्ते को पूंजीगत व्यय बढ़े खाते में डालने के लिए भत्तों का प्रावधान है। जो कंपनियां पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, वे सभी एसीए का दावा कर सकती हैं। यह कार्यक्रम सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध है और अंतर्देशीय राजस्व बोर्ड एसीए प्रदान करने में वस्तुपरक मानदंडों को लागू करता है। इस प्रकार, यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य सब्सिडी नहीं है, क्योंकि यह निर्यात शर्तों से संबद्ध नहीं है, विशिष्ट नहीं है और यह सामान्यतः उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, एसीए की राशि किसी कंपनी द्वारा दावा किए गए पूंजीगत भत्ते का भाग है।
- ख. भत्ते को अग्रेणीत किया जा सकता है। सामान्यतः एसीए के लिए पात्र होने हेतु किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना ही चाहिए:
- वे आधार अवधि के दौरान व्यापार कर रहे थे
 - उन्होंने आधार अवधि में अर्हक व्यय किया है
 - परिसंपत्ति का प्रयोग व्यापार के लिए किया गया था, और
 - आधार अवधि के अंत में वह परिसंपत्ति का स्वामी था और परिसंपत्ति प्रयोग में थी।
- ग. एसीए सहित पूंजीगत भत्तों का दावा करना संगत कर कानून के तहत अनिवार्य है।
- घ. इस कार्यक्रम में किसी मलेशियाई आवासी द्वारा (i) पीयू(ए)156/2018 की अनुसूची में सूचीबद्ध किसी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपस्कर की खरीद, और (ii) उस व्यापार के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त, पीयू(ए)274/2019 में

परिभाषित कस्टमाइज्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए विकास लागत के संबंध में उसके व्यापार से युक्त स्रोत से निर्धारण वर्ष के लिए आधार अवधि में किया गया पूंजीगत व्यय शामिल है।

ड. अनुमत कटौतियां वास्तविक व्यय से अधिक नहीं हैं। दावा करने का समय पूंजीगत भत्ते के सामान्य समय से तुलना करने पर बढ़ाया हुआ है। यह कर मूल्यहास का स्वरूप है।

47. प्राधिकारी द्वारा जांच

क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में पूंजीगत भत्ते अर्था पुनर्निवेश भत्ता अवधि के 15 वर्षों की समाप्ति के बाद संवर्धित क्रियाकलाप में सांविधिक आय से पूंजीगत व्यय की कटौती का प्रावधान है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में पांच वर्षों के भीतर पूंजीगत व्यय अर्थात प्रथम वर्ष में 20 प्रतिशत के आरंभिक भत्ते और उसके बाद 20 प्रतिशत के वार्षिक भत्ते को बट्टे खाते में डालने का प्रावधान है।

ख. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्धारित पूंजीगत व्यय के निमित्त खर्च करने वाले किसी उद्यम के लिए उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के तहत लाभ वर्धित दर पर व्यय घटाकर बचाए गए कर पर प्रोद्भूत व्याज की राशि के बराबर है। पीएमएआर और पीएमबीटीयू ने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम को प्राप्त किया है, उसका प्रयोग किया है और उससे लाभान्वित हुए हैं। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

च.9 कार्यक्रम संख्या 9 – समूह राहत

48. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

क. समूह राहत आय कर अधिनियम, 1967 की धारा 44क के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार निबंधनों और शर्तों के अधीन सभी स्थानीय निगमित आवासी कंपनियों के लिए उपलब्ध है। समूह राहत का प्रावधान समूह में कंपनी को निर्धारण वर्ष के लिए आधार अवधि में अपनी समायोजित हानि के अधिकतम 70 प्रतिशत को एक या दो संबद्ध कंपनियों (दावाकर्ता कंपनी के रूप में उल्लिखित) को उसी समूह के अंतर्गत अभ्यर्पित करने के लिए (अभ्यर्पणकर्ता कंपनी के रूप में उल्लिखित) अनुमति देता है। निर्धारण वर्ष 2009 से प्रभावी, समूह राहत उसी समूह के अंतर्गत अन्य कंपनी की आय के विरुद्ध ऑफसेट करने के लिए वर्तमान वर्ष की खपाई न गई हानियों को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया गया था।

ख. दावाकर्ता और अभ्यर्पणकर्ता कंपनियों प्रत्येक की आरएम 2.5 मिलियन से अधिक के साधारण शेयर की प्रदत्त पूंजी है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया है:

- धारा 44क, आय कर अधिनियम 1967
- निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986
- "कंटीन्यूअस कास्ट कॉपर वायर रॉड्स" के आयातों से संबंधित सब्सिडीरोधी जांच।

49. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

क. जांच की अवधि के दौरान, जांचाधीन किसी भी कंपनी ने समूह राहत कार्यक्रम के तहत आवेदन नहीं किया है, प्रोद्भूत नहीं किया है अथवा लाभ प्राप्त नहीं किया है।

ख. याचिकाकर्ताओं ने जांच की अवधि के दौरान पीएमएआर अथवा पीएमबीटीयू को प्रदत्त लाभ का कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

50. प्राधिकारी द्वारा जांच

क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम आय कर अधिनियम, 1967 की धारा 44क द्वारा शासित है। यह सब्सिडी कार्यक्रम समान समूहों के अंतर्गत एक या अधिक संबद्ध कंपनियों के लाभ के विरुद्ध किसी समूह में किसी कंपनी द्वारा की गई उसकी हानियों के 70 प्रतिशत से अनधिक को सेट ऑफ करने की अनुमति देता है। वे सभी कंपनियां जो पात्रता मानदंड पूरा करती हैं, उस समूह राहत का दावा कर सकती हैं।

- ख. इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व, जो अन्यथा देय है, के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह संबद्ध कंपनियों वाले उद्यम के लिए सीमित है। प्राधिकारी ने पहले ही निर्धारित किया है कि अग्रणी स्तर कार्यक्रम के तहत आय कर से 100% तक छूट प्रदान करने वाले सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के लिए कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

च.10 कार्यक्रम संख्या 10 – प्रशुल्क संबंधी प्रोत्साहन

51. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

- क. इस कार्यक्रम में कच्ची सामग्री/संघटकों पर आयात शुल्क से पूरी छूट का प्रावधान है, जिसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि परिष्कृत उत्पाद निर्यात के लिए हैं अथवा घरेलू बाजार के लिए हैं। छूट के लिए अर्हता हेतु, कच्ची सामग्री/संघटक स्थानीय रूप से उपलब्ध न हों और अनुमोदित विनिर्माता के परिसर (परिसरों) पर परिष्कृत उत्पाद के उत्पादन में सीधे ही प्रयुक्त होते हैं।
- ख. जहां परिष्कृत उत्पाद निर्यात बाजार के लिए हैं, वहां कच्ची सामग्री/संघटकों पर आयात शुल्क से पूरी छूट सामान्यतः दी जाती है, बशर्ते कच्ची सामग्री/संघटकों का उत्पादन स्थानीय रूप से न हो अथवा जहां वे स्थानीय रूप से उत्पादित किए जाते हैं, वहां स्वीकार्य गुणवत्ता और कीमत के न हों।
- ग. कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया है:
- सीमा शुल्क अधिनियम 1967 की धारा 14(2)
 - "कंटीन्यूअस कास्ट कॉपर वायर रॉड्स" के आयातों से संबंधित सब्सिडीरोधी जांच
 - मलेशियाई निवेश विकास प्राधिकरण, विनिर्माण उद्योग में प्रोत्साहन <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/> पर उपलब्ध है।

52. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

- क. जांच की अवधि के दौरान, जांचाधीन किसी भी कंपनी ने प्रशुल्क संबंधी प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत आवेदन नहीं किया है, प्रोद्भव नहीं किया है या लाभ प्राप्त नहीं किया है।
- ख. याचिकाकर्ताओं ने जांच की अवधि के दौरान पीएमएआर अथवा पीएमबीटीयू को प्रदत्त लाभ का कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

53. प्राधिकारी द्वारा जांच

- क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम का संचालन सीमा शुल्क महानिदेशक द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम में योग्य विनिर्माता को कच्ची सामग्री/संघटक पर आयात शुल्क की छूट का प्रावधान है। छूट तब दी जाती है जब कच्ची सामग्री/ संघटक स्थानीय रूप से उपलब्ध न हों और अनुमोदित विनिर्माता के परिसर (परिसरों) पर परिष्कृत उत्पादन के उत्पादन में सीधे ही प्रयुक्त किए जाते हैं।
- ख. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व, जो अन्यथा देय है, के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है। यह कार्यक्रम अनुमती योग्य शुल्क प्रेषण कार्यक्रम होने के योग्य नहीं है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के विनिर्माण क्रियाकलापों में प्रयुक्त कच्ची सामग्री के लिए आयात शुल्क से छूट का प्रावधान है, न कि केवल निर्यातित उत्पादों में प्रयुक्त कच्ची सामग्री के लिए, जैसा कि एससीएन करार की पादटिप्पणी 1 और सीमा शुल्क वर्गीकरण की धारा 9ख(ख) में दिया गया है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह उस उद्यम के लिए सीमित है जो उस कच्ची सामग्री का प्रयोग करता है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं। प्राधिकारी इस सब्सिडी कार्यक्रम को प्रतिकार के लिए मानते हैं।
- ग. पीएमएआर और पीएमबीटीयू, संबद्ध देश से दो प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों ने इस कार्यक्रम से लाभ नहीं लिया। इस प्रकार, प्राधिकारी मानते हैं कि पीएमएआर और पीएमबीटीयू के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क से छूट कार्यक्रम संख्या 18 के तहत प्रतिकार योग्य है। अतः, प्राधिकारी मानते हैं कि शेष श्रेणी के लिए

सब्सिडी मार्जिन निकालते समय इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

च.11 कार्यक्रम संख्या 11 – औद्योगिक भवन के लिए भत्ता/औद्योगिक भवन भत्ता (आईबीए)

54. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

- क. आईबीए उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसने ऐसे औद्योगिक भवन का निर्माण अथवा खरीद पर पूंजीगत व्यय किया हो जो उस व्यक्ति के व्यापार के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आईबीए सांविधिक आय निकालने के लिए समायोजित आय के विरुद्ध घटाया जाता है। आईबीए सामान्यतः सभी कंपनियों, आवासी और गैर-आवासी कंपनियों, दोनों के लिए उपलब्ध है; और पूर्ण स्वामित्व जैसे अनिगमित व्यापार के लिए उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के तहत आरंभिक भत्ता 10% है और भत्ता 3% है। व्यय को 30 वर्षों में बट्टे खाते में डाला जा सकता है।
- ख. आईबीए किसी ऐसे औद्योगिक भवन के निर्माण अथवा खरीद पर पूंजीगत व्यय करने वाली कंपनियों को प्रदान किया जाता है जिसका प्रयोग विनिर्माण, कृषि, खनन आदि सहित कंपनी द्वारा किए गए विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है।
- ग. याचिकाकर्ता द्वारा कार्यक्रम के साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित पर विश्वास किया जाता है:
- आय कर अधिनियम, 1967 की अनुसूची 3
 - "कंटीन्यूअस कास्ट कॉपर वायर रॉड्स" के आयातों से संबंधित सब्सिडीरोधी जांच
 - मलेशियाई निवेश विकास प्राधिकरण, विनिर्माण उद्योग में प्रोत्साहन, <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/> पर उपलब्ध है।
 - मलेशिया के अंतर्देशीय राजस्व बोर्ड, आईबीए का अर्हक व्यय एवं परिकलन, सार्वजनिक नियम संख्या 3/2018

55. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- क. आईबीए ऐसे किसी व्यक्ति को उपलब्ध है जिसने औद्योगिक भवन की खरीद अथवा निर्माण जिसका उपयोग उस व्यक्ति के व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, पर पूंजीगत व्यय किया है। आईबीए कर-ह्रास के रूप में एक-बारगी लाभ है।
- ख. आईबीए आयकर अधिनियम 1967 की अनुसूची 3 के अंतर्गत औद्योगिक भवन पर किए गए खर्च के लिए दी गई पूंजी छूट है। आईबीए आरंभिक छूट (आईए) और वास्तविक छूट (एए) अथवा औद्योगिक भवन के प्रत्येक प्रकार के लिए निर्धारित दर पर ही हुए है। सामान्य तौर पर, आईए के लिए दर अर्हक व्यापार व्यय (क्यूबीई) के 10 प्रतिशत पर दिया जाता है और यदि क्यूबीई का उल्लेख विशिष्ट रूप से एक अलग दर पर नहीं किया गया हो तब एए की दर क्यूबीई का 3 प्रतिशत है।
- ग. निर्यात आईबीए की अनुमति देने के लिए एक मानदंड नहीं है। भवन के उपयोग के बावजूद सभी भवनों को आईबीए की अनुमति दी जाती है। अतः आईबीए उन भवनों पर भी लागू नहीं है जिनका उपयोग निर्यात के लिए वस्तुओं के भंडारण अथवा आयात की गई वस्तुओं के लिए भंडारण के रूप में किया जाता है जिसका प्रसंस्करण किया जाना है और वितरण किया जाना है अथवा फिर से निर्यात किया जाना है।
- घ. वे सभी कंपनियां, जो पात्रता के मानदंड को पूरा करती हैं, कटौतियों का दावा कर सकती हैं। यह कार्यक्रम उन सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध है और अंतर्देशीय राजस्व बोर्ड आईबीए की अनुमति देने में वस्तुनिष्ठ मानदंड को लागू करता है। इस प्रकार, यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी नहीं होता है क्योंकि यह विशिष्ट नहीं है।
- ड. पीएमएआर ने उपयोग किया है और आईबीए से लाभ प्राप्त किया है। क्यूबीई व्यापार के उद्देश्यों से औद्योगिक भवन के रूप में उपयोग किए गए भवन के निर्माण/खरीद पर पीएमएआर द्वारा किया जाता है जिसमें उसे 30 वर्षों की अवधि के दौरान इसकी कर-योग्य आय को कम करने के लिए कटौती के रूप में आईबीए का दावा करने हेतु पात्र बनाया है।

- च. पीएमबीटीयू ने भी इसका उपयोग किया है और आईबीए से लाभ प्राप्त किया है। बीएमबीटीयू अपने व्यापार के उद्देश्य से औद्योगिक निर्माण के रूप में उपयोग किए गए भवन के निर्माण/खरीद पर पीएमबीटीयू द्वारा किया गया क्यूबीई के 100 प्रतिशत पर 30 वर्षों की अवधि के दौरान कर-योग्य आय को कम करने के लिए कटौती के रूप में आईबीए का दावा करने के लिए पात्र है।

56. प्राधिकारी द्वारा जांच

- क. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि औद्योगिक भवन छूट (आईबीए) उस कंपनी के लिए उपलब्ध है, जिसने उस कंपनी के व्यापार के उद्देश्य से उपयोग किए गए एक औद्योगिक भवन के निर्माण अथवा खरीद पर पूंजीगत व्यय किया है। आईबीए की कटौती सांविधिक आय तय करने के लिए समायोजित आय के विरुद्ध की जाती है।
- ख. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम कोई प्रतिसंतुलनकारणीय लाभ उपलब्ध नहीं कराता है क्योंकि यह सभी उपक्रमों को भवन पर ह्रास की सामान्य कटौती का प्रावधान करता है। इस कारण से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

च.12 कार्यक्रम 12 : संयंत्र और मशीनरी की छूट

57. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- क. पूंजी छूट(सीए) की मशीनरी अथवा संयंत्र पर अर्हक व्यय के लिए एक कटौती अर्थात् व्यापार के लिए निर्धारित परिसंपत्तियों के ह्रास और क्षरण के लिए राहत है। सीए केवल एक व्यापार स्रोत के संबंध में तथा उस व्यक्ति के संबंध में दिया जाता है जो अर्हक व्यय करता है और इस कारण से छूट का दावा करने के लिए पात्र है। सीए की गणना एक वर्ष के आकलन के लिए की जाती है और इसकी कटौती सांविधिक आय तय करने में व्यापार से समायोजित आय से की जाती है। आरंभिक छूट उस समय जब पूंजीगत व्यय किया जाता है, परिसंपत्ति की लागत के आधार पर 20 प्रतिशत की दर से की जाती है। वार्षिक छूट इस परिसंपत्ति की मूल लागत के आधार पर प्रत्येक वर्ष फ्लैट दर पर दी जाती है और तदनुसार, यह अलग-अलग होती है।
- ख. याचिकाकर्ताओं द्वारा जिस साक्ष्य पर विश्वास किया गया है उसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- आयकर अधिनियम 1967 की अनुसूची 3
 - “सतत कास्ट कॉपर वायर रोड्स” के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी जांच
- ग. लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता निम्नलिखित है:
- i. किसी व्यापार को आगे बढ़ाना
 - ii. संयंत्र और मशीनरी पर पूंजीगत व्यय करता है
 - iii. संयंत्र और मशीनरी का उस व्यापार में अवश्य उपयोग किया जाना चाहिए
 - iv. आधार अवधि के अंत में संयंत्र और मशीनरी का मालिक

58. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- क. न तो पीएमएआर और न ही पीएमबीटीयू ने इस कार्यक्रम के लिए आवेदन किया है, इसका उपयोग किया है अथवा इससे लाभ प्राप्त किया है।
- ख. आयकर अधिनियम के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी के लिए कोई छूट नहीं है। इसके बजाय, सीए के रूप में छूट आयकर अधिनियम की अनुसूची 3 के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी के लिए दी जाती है।
- ग. वे सभी कंपनियां जो पात्रता के मानदंड को पूरा करती हैं, सीए का दावा कर सकते हैं। सीए की गणना आकलन के वर्ष के लिए की जाती है और उसकी कटौती सांविधिक आय तय करने में व्यापार से

समायोजित आय से की जाती है। इसकी गणना छूट की निर्धारित दर के आधार पर स्ट्रेट-लाइन पद्धति पर की जाती है।

- घ. आईआरबी सीए की अनुमति देने में एक वस्तुनिष्ठ मानदंड लागू करता है। इस प्रकार, यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी नहीं होता है क्योंकि यह निर्यात की शर्तों के संबद्ध नहीं है और न ही यह विशिष्ट है और यह आमतौर पर उपलब्ध है।
- ड. पीएमएआर और पीएमबीटीयू ने संयंत्र और मशीनरी के लिए छूट/सीए के लिए इस कार्यक्रम का उपयोग किया था और इससे लाभ प्राप्त किया था। सीए एक प्रकार का कर-कटौती है (अर्थात् पीएमएआर और पीएमबीटीयू द्वारा अपनी कर-योग्य आय से किए गए अर्हक पूंजी व्यय की कटौती)। यह एकबारगी लाभ है।
- च. व्यापार के उद्देश्यों से जिसने इसे चार से आठ वर्षों के बीच की अवधि के दौरान कर-योग्य आय में कटौती करने के लिए कटौती के रूप में सीए का दावा करने के लिए पीएमएआर और पीएमबीटीयू के वास्ते पात्र बनाया, पूंजीगत व्यय पर पीएमएआर द्वारा किया गया अर्हक व्यय।

59. प्राधिकारी द्वारा जांच

- क. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मशीनरी अथवा संयंत्र पर अर्हक व्यय के लिए मशीनरी और संयंत्र के लिए छूट में कटौतियों का प्रावधान है। यह उस उपक्रम को दिया जाता है जो अर्हक व्यय करता है। इसकी गणना आकलन के वर्ष के लिए की जाती है और उसकी कटौती सांविधिक आय तय करने में व्यापार से समायोजित आय से की जाती है। इसकी गणना छूट की निर्धारित दर के आधार पर स्ट्रेट-लाइन पद्धति पर की जाती है।
- ख. उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों पीएमबीटीयू और पीएमएआर ने संयंत्र और मशीनरी पर छूट का दावा किया है।
- ग. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में किसी प्रतिसंतुलनकारणीय लाभ का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि इसमें सभी उपक्रमों को स्ट्रेट-लाइन पद्धति के अनुसार संयंत्र और मशीनरी पर ह्रास की सामान्य कटौती का प्रावधान है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

च.13 कार्यक्रम 13: निर्यातों के संवर्धन के लिए दोहरी कटौती

60. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- क. याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत, घरेलू स्तर पर स्थानीय ब्रांड उत्पादों का विज्ञापन देने पर किए गए खर्च की अनुमति दोहरी कटौती के लिए की जाती है (कुछ क्रियाकलापों पर किए गए खर्चों को कर-योग्य लाभ के विरुद्ध दो बार दिया जा सकता है)।
- ख. पात्र बनने के लिए स्थानीय ब्रांड को निम्नलिखित मानदंड अवश्य पूरा करना चाहिए:
 - i. कंपनी का स्वामित्व मलेशिया के ब्रांड नाम के पंजीकृत प्रोपेराइटर के द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक अवश्य होना चाहिए
 - ii. इस कटौती का दावा एक आकलन वर्ष में केवल एक कंपनी द्वारा ही किया जा सकता है
 - iii. ब्रांड नाम का स्वामित्व एक कंपनी के पास होना चाहिए जो कम से कम 70 प्रतिशत मलेशियाई के स्वामित्व के साथ स्थानीय रूप से निगमित हुआ हो
 - iv. ब्रांड नाम का पंजीकरण मलेशिया में अथवा विदेश में किया गया हो
 - v. ब्रांड नाम उत्पाद को निर्यात गुणवत्ता मानदंडों को अवश्य प्राप्त करना चाहिए
 - vi. विज्ञापन पर किया गया खर्च मलेशिया में ही हुआ होना चाहिए
 - vii. पेशेवर शुल्क पर किया गया खर्च मलेशिया में ही होना चाहिए

ग. इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ निर्यात विशिष्ट है, उसमें निर्माण करने वाले और कृषि से जुड़ी कंपनियों जो “संबंधित उत्पाद” का उत्पादन कर रहे हों “संबंधित क्रियाकलापों” में लगे हुए हों, को प्रोत्साहन उपलब्ध हो। कार्यक्रम के मौजूद रहने के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया है:

- निवेश संवर्धन अधिनियम 1986 की धारा 41
- आयकर (निर्यात का संवर्धन) का नियम 4(2)
- “सतत् कॉस्ट कॉपर वायर रोड्स” के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी जांच
- विश्व व्यापार संगठन की अधिसूचना- जी/एससीएम/एन/3/एमवाईएस/1986
- मलेशिया से यूएस कार्बन स्टील वायर रोड
- डब्ल्यूटी/टीपीआर/292

61. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

क. इस कार्यक्रम का सही कानूनी आधार निम्नलिखित है:

- आयकर(मलेशिया के ब्रांड नाम की वस्तुओं पर व्यय का विज्ञापन करने के लिए कटौती) नियमावली 2002, जिसे आयकर (मलेशिया के ब्रांड नाम की वस्तुओं पर विज्ञापन संबंधी व्यय के लिए कटौती) (संशोधन), नियमावली 2007 द्वारा किया गया है।
- आयकर अधिनियम 1967 की धारा 33 (संशोधित 1971)

ख. न तो पीएमएआर और न ही पीएमबीटीयू ने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम का लाभ उठाया है, इसका उपयोग किया है अथवा इससे उसे लाभ हुआ है।

ग. याचिकाकर्ताओं ने जांच की अवधि के दौरान पीएमएआर अथवा पीएमबीटीयू पर दिए गए लाभ का कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

62. प्राधिकारी द्वारा जांच

क. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम निवेश संवर्धन अधिनियम (पीआईए) 1986 (अधिनियम 327) की धारा 41 और आयकर (निर्यात का संवर्धन) नियमावली 1986 के नियम 4(2) के द्वारा शासित होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण, व्यापार और कृषि संबंधी क्रियाकलापों में शामिल उपक्रम को आय से दोहरी कटौती निर्यात के संवर्धन के लिए किए गए खर्च के लिए उपलब्ध है। निर्यात के लिए बढ़ती हुई मांग के वास्ते किसी कंपनी द्वारा किए गए खर्च की अनुमति दोहरी कटौती के लिए दी जाती है।

ख. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व, जो अन्यथा देय है, के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और उसके माध्यम से लाभ दिया जाता है।

ग. यह लाभ दोहरी कटौती के बाद भुगतान की गई आयकर की राशि और आयकर की वह राशि जो इस प्रकार की दोहरी कटौती न होने पर भुगतान योग्य हुई होती, के बीच अंतर है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात कार्य-निष्पादन पर निर्भर करता है और यह निर्यात संवर्धन क्रियाकलाप में शामिल उपक्रम तक सीमित है। पीएमएआर और पीएमबीटीयू जो संबद्ध देश के भाग लेने वाले दो उत्पादक/निर्यातक हैं, को इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। इस प्रकार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि पीएमएआर और पीएमबीटीयू के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने पहले ही इसका निर्धारण कर दिया है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क उस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध लगाया जाना चाहिए जो आयकर से छूट दे रहे हों। इस कारण से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस सब्सिडी कार्यक्रम के वास्ते कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

च.14 कार्यक्रम 14: ईस्ट कोस्ट इकॉनोमिक कारिडोर में निर्माण और निर्माण से संबंधित सेवाओं के लिए प्रोत्साहन

क. जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस में, जैसाकि उल्लेख किया गया है, कार्यक्रम सं. 14 इस जांच के क्षेत्र से बाहर किया गया है। तदनुसार, इस कार्यक्रम की जांच नहीं की जा रही है।

च.15 कार्यक्रम 15: आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर ड्राबैक**63. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

क. याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया कि आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर ड्राबैक, जिसका भुगतान किया गया है, का दावा किसी निर्माता द्वारा तभी किया जा सकता है यदि पाटर्स, कच्चा माल अथवा पैकेजिंग माल का उपयोग इन अधिनियमों में निर्धारित शर्तों के आधार पर एक वर्ष के भीतर निर्यात के लिए वस्तुओं के निर्माण में किया गया हो।

ख. याचिकाकर्ताओं द्वारा जिस कानूनी आधार पर विश्वास किया गया है, उसमें निम्नलिखित शामिल है:

- सीमाशुल्क अधिनियम 1967 की धारा 93, 95, 99
- बिक्री कर अधिनियम 1972 की धारा 29
- उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1976 की धारा 19 और 19 क
- “सतत कास्ट कॉपर वायर रोड्स” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी का जांच परिणाम

64. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

क. ने तो पीएमएआर और न ही पीएमबीटीयू ने इस कार्यक्रम का उपयोग किया है अथवा इस कार्यक्रम से उसे लाभ हुआ।

65. प्राधिकारी द्वारा जांच

क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम का संचालन रॉयल मलेशियन सीमा शुल्क विभाग द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम में इनपुट्स, जिसका उपयोग निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, पर लगाए गए आयात शुल्क के प्रतिदाय का प्रावधान है।

ख. पीएमएआर और पीएमबीटीयू, जो संबद्ध देश का भाग लेने वाले दो उत्पादक/निर्यातक हैं, को इस कार्यक्रम से लाभ नहीं मिला। इस प्रकार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि पीएमएआर और पीएमबीटीयू के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने इस तथ्य का निर्धारण किया है कि कच्चे माल पर आयात शुल्क से छूट कार्यक्रम सं. 18 के अंतर्गत प्रतिसंतुलनकारी है। इस प्रकार से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि शेष श्रेणी के लिए सब्सिडी मार्जिन तय करते समय इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

च.16 कार्यक्रम 16: निर्माण क्रियाकलापों को आउटसोर्स करने के लिए आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट**66. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

क. याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम में निर्माण क्रियाकलापों को आउटसोर्स करने के लिए कच्चे माल, संघटकों और/अथवा अर्द्ध-तैयार उत्पादों पर आयात शुल्क से छूट का मूल्यांकन करना शामिल है। यह कार्यक्रम व्यापार करने की लागत को कम करने और कम से कम 60 प्रतिशत मलेशियाई इक्विटी स्वामित्व के साथ मलेशियाई ब्रांड के मालिकों, जो कुछ लाभ के लिए निर्माण संबंधी क्रियाकलापों को आउटसोर्स करते हैं, के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करता है। तैयार उत्पादों के निर्माण में उपयोग किए गए कच्चे माल और संघटकों पर उनके संविदागत निर्मातों, जो स्थानीय तौर पर होते हैं/जो विदेश में स्थित हैं, के द्वारा आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट तथा विदेश स्थित उनके संविदागत निर्माताओं के अर्द्ध-तैयार उत्पादों पर बिक्री कर से छूट उपलब्ध है।

ख. याचिकाकर्ताओं ने “सतत कॉस्ट कॉपर वायर रोड्स” के आयातों के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम, 1967 की धारा 14(2) तथा सब्सिडीरोधी जांच पर विश्वास किया है।

67. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

क. न तो पीएमएआर और न ही पीएमबीटीयू ने इस कार्यक्रम का उपयोग किया है अथवा उसे इस कार्यक्रम से लाभ हुआ है।

68. प्राधिकारी द्वारा जांच

क. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम 1967 की धारा 14(2) इस कार्यक्रम के संचालन को स्थापित करता है। इस कार्यक्रम का संचालन मलेशियाई निवेश विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम में निर्माण क्रियाकलापों को आउटसोर्स करने के लिए कच्चे माल, संघटकों और/अथवा अर्ध-तैयार उत्पादों पर आयात शुल्क से छूट का प्रावधान है।

ख. पीएमएआर और पीएमबीटीयू, जो संबद्ध देश के भाग लेने वाले दो उत्पादक/निर्यातक हैं, को इस कार्यक्रम से लाभ नहीं मिला। इस प्रकार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि पीएमएआर और पीएमबीटीयू के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने इस तथ्य का निर्धारण किया है कि कच्चे माल पर आयात शुल्क से छूट कार्यक्रम सं. 18 के अंतर्गत प्रतिसंतुलनकारणीय है। इस प्रकार से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि शेष श्रेणी के लिए सब्सिडी मार्जिन तय करते समय इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

च.17 कार्यक्रम 17: मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट

69. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

क. इस कार्यक्रम में योग्य निर्माता को मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क से छूट का मूल्यांकन करना शामिल है। इस छूट के लिए योग्य होने के वास्ते, मशीनरी और उपकरण नये होने चाहिए, उपयोग नहीं किया हुआ होना चाहिए और प्रत्यक्ष तौर पर इसका उपयोग अनुमोदित निर्माता के परिसर में तैयार उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया में किया जाना चाहिए। उन मामलों में, जहां आयात की गई मशीनरी और उपकरण कर-योग्य हैं, परंतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हों, आयात शुल्क और बिक्री-कर पर पूरी छूट दी जाती है। स्थानीय स्तर पर खरीदी गई मशीनरी और उपकरण के लिए, पूरी छूट बिक्री-कर पर दी जाती है। याचिकाकर्ताओं ने सीमा शुल्क (छूट) आदेश 2017 पर विश्वास किया।

70. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

क. पीएमएआर द्वारा उपयोग किए गए कच्चे माल के आयात पर अंतिम शुल्क छूट का अनुमोदन अप्रैल, 2016 में किया गया था और यह 3 वर्षों के लिए मार्च, 2019 तक वैध था। इस छूट के अलावा, पीएमएआर ने जांच की अवधि के दौरान सहित इस कार्यक्रम का लाभ नहीं उठाया, उपयोग नहीं किया और इससे उसे लाभ नहीं हुआ।

ख. पीएमबीटीयू को इस कार्यक्रम से लाभ नहीं मिला था।

71. प्राधिकारी द्वारा जांच

क. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम को सीमा शुल्क (छूट) आदेश 2017 के द्वारा स्थापित किया जाता है। इसमें योग्य निर्माता को नए और उपयोग न किए गए मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क से छूट का प्रावधान है। जांच की अवधि के दौरान बिक्री कर से कोई छूट नहीं दी गई है क्योंकि बिक्री कर अधिनियम 1972 [अधिनियम 64] वस्तु एवं सेवा-कर अधिनियम 2014 [अधिनियम 762] के अधिनियमन जिसे 1 जुलाई, 2014 से लागू किया गया है, के साथ निरस्त कर दिया गया था। इस कार्यक्रम का संचालन मलेशिया निवेश विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

- ख. उत्तर देने वाले उत्पादक/निर्यातक पीएमएआर ने उन पूंजीगत वस्तुओं का ब्यौरा दिया है जिन पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ एयूएल अवधि के दौरान लिया गया है। इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व, जो अन्य प्रकार से देय है, के रूप में वित्तीय अंश दान का प्रावधान है और उसके माध्यम से लाभ दिया गया है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह कुछ उपक्रमों तक सीमित है जो नई मशीनरी और उपकरण का आयात निर्माण क्रियाकलाप के लिए करते हैं। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पीएमएआर के वास्ते इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। उत्तर देने वाले उत्पादक/निर्यातक पीएमबीटीयू को एयूएल अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

च.18 कार्यक्रम 18: कच्चे माल/संघटकों पर आयात शुल्क से छूट

72. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- क. इस कार्यक्रम के अंतर्गत जहां तैयार उत्पाद निर्यात बाजार के लिए है, कच्चे माल/संघटकों पर आयात शुल्क से पूरी छूट सामान्य तौर पर दी जाती है, बशर्ते, कच्चे माल/संघटकों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर नहीं किया जाता हो अथवा जहां उनका उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जाता हो, परंतु वे स्वीकार किए जाने योग्य कीमत और गुणवत्ता का नहीं हो। जहां तैयार उत्पाद घरेलू बाजार के लिए हो, कच्चे माल/संघटकों जिसका उत्पादन स्थानीय स्तर पर नहीं किया जाता हो, पर आयात शुल्क से पूरी छूट पर विचार किया जा सकता है। यदि शुल्क योग्य कच्चे माल/संघटकों से बनाया गया तैयार उत्पाद किसी आयात शुल्क के अध्यधीन नहीं हो, तब पूरी छूट पर भी विचार किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने इस कार्यक्रम के लिए कानूनी आधार के रूप में सीमा शुल्क अधिनियम 1947 की धारा 14(2) पर विश्वास किया।

73. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- क. यह कार्यक्रम सीमा शुल्क और बिक्री कर के भुगतान से छूट है। पीएमएआर द्वारा आयात किए गए कच्चे माल शून्य दर वाला आयात था और इस कारण से पीएमएआर से यह अपेक्षित नहीं था कि वह शुल्क से छूट के लिए आवेदन करे। पीएमएआर ने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम को लागू नहीं किया, इसका उपयोग नहीं किया अथवा इससे लाभ नहीं उठाया। पीएमबीटीयू ने इस कार्यक्रम से उपयोग अथवा लाभ के लिए आवेदन नहीं किया।

74. प्राधिकारी द्वारा जांच

- क. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम को सीमा शुल्क अधिनियम 1967 की धारा 14(2) द्वारा स्थापित किया जाता है। इस कार्यक्रम में कच्चे माल/संघटकों, जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होते हैं, पर योग्य निर्माता को आयात शुल्क से छूट का प्रावधान है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ भाग लेने वाले उत्पादकों पीएमएआर और पीएमबीटीयू द्वारा नहीं उठाया गया है। इस कारण से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि पीएमएआर और पीएमबीटीयू के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।
- ख. इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व, जो अन्य प्रकार से देय है, के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और उसके माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उस उपक्रम तक सीमित है, जो उन कच्चे मालों का उपयोग करते हैं जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं।
- ग. इस कारण से, प्राधिकारी संबद्ध देशों से सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाना सही मानते हैं।

च.19 कार्यक्रम 19: निर्यातों के संवर्धन के लिए दोहरी कटौती

- क. प्राधिकारी द्वारा पहले ही जांच किए जा चुकी कार्यक्रम सं. 13 के समान है।

च.20 कार्यक्रम 20: निर्यात कार्गो के संवर्धन के लिए दोहरी कटौती

क. जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस में, जैसा उल्लेख किया गया है, कार्यक्रम सं. 20 इस जांच के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। तदनुसार इस कार्यक्रम की जांच नहीं की जा रही है।

च.21 कार्यक्रम 21: बड़े हुए निर्यातों के लिए छूट**75. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

क. याचिकाकर्ता ये अनुरोध करते हैं कि यह कार्यक्रम आयकर अधिनियम 1967 की धारा 154(1) और आयकर (बड़े हुए निर्यातों के लिए छूट) नियमावली 1999 के नियम 3 और आयकर (बड़े हुए निर्यातों के लिए छूट) (संशोधन) नियमावली 2003, जिसके द्वारा कोई भी निर्यातक बड़े हुए निर्यातों के लिए कर-योग्य आय से 70 प्रतिशत कर कटौती का लाभ उठा सकता है, के अंतर्गत कंपनियों को दी गई कर-प्रोत्साहन के रूप में है।

ख. इस छूट का निर्धारण नीचे दिए गए अनुसार किया जाएगा:

निर्मित उत्पाद

- i. कंपनी के निर्मित उत्पादों के बड़े हुए निर्यातों का मूल्य का 10 प्रतिशत, जहां किए गए उत्पादों ने वर्धित मूल्य का कम से कम 30 प्रतिशत प्राप्त किया;
- ii. निर्मित उत्पादों के बड़े हुए निर्यातों का मूल्य का 15 प्रतिशत, जहां निर्यात किए गए उत्पादों ने वर्धित मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्त कर लिया।

कृषि संबंधी उत्पाद

- i. कंपनी द्वारा कृषि से संबंधित उत्पाद के बड़े हुए निर्यातों के मूल्यों का 10 प्रतिशत

76. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

क. किसी भी प्रतिवादियों ने, न तो इस कार्यक्रम का उपयोग किया है अथवा उसे इस कार्यक्रम से लाभ हुआ है। आयकर (छूट) (सं.6) आदेश 2019, यह अधिदेश देता है कि अर्हता प्राप्त कंपनी के पास मलेशिया के नागरिक के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर कम से कम 5 प्रतिशत धारित होना चाहिए। पीएमबीटीयू जो एक कंपनी है और न कि एक व्यक्ति है के द्वारा पीएमएआर धारित किया जाता है।

77. प्राधिकारी द्वारा जांच

- क. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एक स्थानिक निर्माण कंपनी अथवा किसी से जुड़ी कंपनी, जो निर्मित उत्पादों अथवा कृषि से संबंधित उत्पाद का निर्यात करती है, को बड़े हुए निर्यात के लिए छूट दी जानी है। यह छूट कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों के बड़े हुए निर्यातों के मूल्य का 10 प्रतिशत अथवा 15 प्रतिशत के समतुल्य है। सांविधिक व्यापार आय के 70 प्रतिशत के विरुद्ध छूट दी जाएगी।
- ख. इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व, जो अन्य प्रकार से देय हो, के रूप में वित्तीय अंश दान का प्रावधान है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात कार्य-निष्पादन पर निर्भर है। प्राधिकारी ने पहले ही इस तथ्य का निर्धारण किया है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क आयकर से छूट देने वाले सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध लगाया जाना चाहिए। इस कारण से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

च.22 कार्यक्रम 22: फ्री ट्रेड जोन में निर्यातकों के लिए कर से छूट

78. जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस में, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि कार्यक्रम सं. 22 को इस जांच के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। तदनुसार, इस कार्यक्रम पर वर्तमान मामले में विचार नहीं किया जा रहा है।

च.23 कार्यक्रम 23: भूमि और बिजली के लिए उचित से कम पारिश्रमिक**79. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

- क. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि इस समूह ने उचित से कम पारिश्रमिक पर एक दीर्घावधि विद्युत खरीद करार किया। स्मैल्टर्स जो कोयला से उत्पन्न आग अथवा गैस से उत्पन्न आग के आधार पर चलने वाले विद्युत संयंत्रों पर निर्भर हैं, के विपरीत, यह समूह कोयल और गैस की कीमत में उतार-चढ़ाव के अध्यधीन नहीं है। कोई भी कंपनी सारावक में आधारित निर्माण परियोजनाओं के लिए विशेष अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का लाभ उठा सकती है। औद्योगिक विकास मंत्रालय को आवेदन प्रस्तुत कर इस प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाया जा सकता है।
- ख. याचिकाकर्ताओं ने इस कार्यक्रम के साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित पर विश्वास किया है:
- सवारक सरकार, निवेश प्रोत्साहन राशि निम्नलिखित पर उपलब्ध है:
https://www.sarawak.gov.my/web/home/article_view/214/229/
 - एमआईडी द्वारा सवारक औद्योगिक संपदा विकास
https://www.sarawak.gov.my/web/home/article_view/213/228/
 - वार्षिक रिपोर्ट, पृष्ठ सं.9 निम्नलिखित पर उपलब्ध है
http://disclosure.bursamalaysia.com/FileAccess/apbursaweb/download?id=193979&name=EA_DS_ATTACHMENTS
 - न्यूज रिपोर्ट निम्नलिखित पर उपलब्ध है:
<https://www.nst.com.my/business/2019/07/508803/press-metal-secures-more-power-expansion>
- ग. पीएमबीटीयू सामालाजु औद्योगिक पार्क में है। सारावक के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, वे उद्योग जो उस क्षेत्र में स्थित हैं, को भूमि के प्रीमियम के लिए 30 प्रतिशत छूट मिलती है, यदि उस परियोजना को पूरा कर लिया जाता है और क्रियाकलाप भूमि के हस्तांतरण की तिथि से 36 महीने के भीतर शुरू हुआ हो।

80. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- क. सारावक में थोक बिजली की बिक्री के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। सारावक एनर्जी बर्हाड (एसईबी) बिजली की बिक्री इच्छुक क्रेता, इच्छुक विक्रेता के आधार पर स्वतंत्र वाणिज्यिक समझौते के माध्यम से करता है। संबंधित ठेका "बिजली खरीद करार" (पीपीए) के रूप में जाना जाता है। सारावक में थोक प्रयोक्ताओं को बिजली की बिक्री मलेशियाई कानून के द्वारा शासित संविदागत आधार पर किया जाता है।
- ख. एसईबी एक निगम है जिसे निदेशकों के एक स्वतंत्र बोर्ड द्वारा शासित किया जाता है और विशेषज्ञ स्टाफ के द्वारा पेशेगत रूप से प्रबंधित किया जाता है। प्रबंधन को यह अधिदेश है कि वे एल्युमिनियम सहित परंतु एल्युमिनियम तक सीमित नहीं विद्युत गहन उद्योगों से थोक बिजली ग्राहकों के साथ पीपीए के संबंध में समझौता करें। थोक बिजली की मांग प्रकार के तौर पर एसईबी की आपूर्ति करने की क्षमता से अधिक है और बिजली का आबंटन उन ग्राहकों को किया जाता है जो एसईबी को सबसे अधिक वाणिज्यिक और रणनीतिक लाभ प्रदान करते हैं।
- ग. एसईबी ने सारावक में अन्य के साथ-साथ, जापान, कोरिया, चीन, आस्ट्रेलिया, भारत जैसे संभावित विदेशी ग्राहकों के साथ पीपीए समझौता भी किया है और उसके साथ विविध उद्योगों (जिसमें एल्युमिनियम, फेरो-अलॉय, पोलिसिलिकान, कॉपर फिल्म आदि शामिल हैं) तथा इंडोनेशियाई कालीमंटन, ब्रुनेई और सबाह जैसे पड़ोसी क्षेत्रों को विद्युत का निर्यात करने के लिए पीपीए करार किया है।

घ. पूरे मलेशिया में विद्युत प्रदाता निम्नलिखित हैं:

राज्य	एकमात्र विद्युत प्रदाता
प्रायद्वीपीय मलेशिया (11 राज्य)	टेनागा नेशनल बर्हाड (टीएनबी)
सबाह राज्य (पूर्वी मलेशिया में स्थित)	सबाह विद्युत एसडीएन. बीएचडी
सारावक राज्य (पूर्वी मलेशिया में स्थित)	सारावक एनर्जी बर्हाड (एसईबी)

ड. एसईबी सारावक में एकमात्र बिजली आपूर्तिकर्ता है और कथित सब्सिडी किसी भी व्यक्ति, जिसे सारावक के पूरे राज्य में 5 मेगावाट से अधिक बिजली लोड की आवश्यकता है, के लिए उपलब्ध है। पीपीए से निम्नलिखित शर्तों की समीक्षा यह दर्शाती है कि उचित पारिश्रमिक से कम पर बिजली का कोई प्रावधान नहीं है।

- पीएमबीटीयू ने खपत के पूर्व निर्धारित स्तर पर एसईबी से बिजली की खरीद करने के लिए 25 वर्षों की दीर्घ अवधि प्रतिबद्धता के लिए संविदा की;
- बिजली की खरीद की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ “लें अथवा भुगतान करें” शर्त शामिल है जहां पीएमबीटीयू पर यह दायित्व है कि वह प्रतिबद्ध खपत-स्तर का 90 प्रतिशत की खपत करे अथवा उसके लिए भुगतान करें (यदि खपत नहीं भी की गई हो);
- एसईबी के पास लंदन मेटल एक्सचेंज में प्रकाशित एल्युमिनियम की कीमत के अध्यक्षीन क्मोडिटी कीमत समायोजन उपबंध के द्वारा शुल्क में वृद्धि करने का अधिकार है;
- एसईबी का इसके प्रशुल्क में वार्षिक आधार पर 1.5 प्रतिशत तक वृद्धि करने के लिए एसईबी को सक्षम बनाने के लिए वृद्धि संबंधी उपबंध है। वास्तव में इसका उपयोग भी किया गया है;
- पीएमबीटीयू प्रतिबद्ध स्तर से खपत के अधिक होने की स्थिति में एसईबी से कोई भी छूट प्राप्त करने का हकदार नहीं है;
- एसईबी द्वारा किए गए बिजली आउटेज की स्थिति में, पीएमबीटीयू के पास एसईबी से परि-समाप्त क्षति का दावा करने का अधिकार है;
- पीएमबीटीयू ने एसईबी के सब-स्टेशन से अंतिम माइल कनेक्शन के लिए पीएमबीटीयू के परिसरों से बाहर लगभग 7 किलोमीटर का टॉवर और विद्युत पारसन लाइन का निर्माण करने की लागत का वहन किया है।
- समाप्त होने की स्थिति में, दोषी पक्षकार को अन्य पक्षकार को परिसमाप्त हर्जाना का भुगतान करना पड़ेगा।

च. मलेशिया की सरकार द्वारा किसी क्षेत्र अथवा उद्योग के लिए निर्धारित बिजली का कोई अधिमान्य दर नहीं है।

छ. पीएमएआर को उचित पारिश्रमिक से कम पर बिजली की आपूर्ति के आरोप के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि बिजली की आपूर्ति के लिए टीएनबी के साथ पीएमएआर द्वारा कोई पृथक करार नहीं है। खपत के आधार पर टीएनबी द्वारा औद्योगिक इकाईयों के लिए निर्धारित बिजली शुल्क पीएमएआर पर लागू है।

ज. एलटीएआर पर भूमि के प्रावधान के लिए सारावक सरकार का कोई पृथक कार्यक्रम नहीं है। पीएमबीटीयू सारावक क्षेत्र में स्थित है। चूंकि पीएमबीटीयू ने भूमि पर भवन का निर्माण पूरा कर लिया और 5 वर्ष के भीतर अनुमोदित औद्योगिक क्रियाकलाप का प्रचालन शुरू कर दिया, पीएमबीटीयू भूमि के प्रीमियम की चौथी और पांचवीं किश्तों के प्रतिदाय/माफी के लिए पात्र हो गया।

झ. एलटीएआर पर भूमि का प्रावधान विशिष्ट नहीं है क्योंकि यह कुछ उपक्रम तक चिन्हित नहीं है और पात्रता एच्छिक नहीं है। पात्रता वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित है जो प्रयोग में तटस्थ और क्षैतिज है।

- ज. भूमि प्रीमियम पर कथित छूट सारावक में औद्योगिक भूमि के सभी पट्टेदारों पर लागू है बशर्ते कि एलएसडीएस द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर भवनों का निर्माण अथवा प्रचालन की शुरुआत जैसे मानदंड पूरे किए जाते हों।
- ट. पीएमबीटीयू ने 2011 से 2017 तक सारावक राज्य के अंतर्गत भूमि और सर्वेक्षण विभाग सारावक (एलएसडीएस) के साथ राज्य की भूमि का अनंतिम पट्टे के लिए एक करार किया है। इस प्रकार की छूट एलएसडीएस द्वारा निर्धारित वस्तुनिष्ठ मानदंडों को पूरा किए जाने पर औद्योगिक भूमि के सभी पट्टेदारों पर लागू है।
- ठ. एलटीएआर पर भूमि के प्रावधान पर कोई आरोप पीएमएआर पर भी लागू नहीं होता है। पीएमएआर ने निजी कंपनियों और न कि सरकारी कंपनियों अथवा सरकार से जुड़ी/संबद्ध कंपनियों से भूमि की खरीद की।

81. प्राधिकारी द्वारा जांच

- क. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उचित पारिश्रमिक से कम पर बिजली के प्रावधान और उचित पारिश्रमिक से कम पर भूमि के प्रावधान के आरोप की जांच पृथक् रूप से की जानी अपेक्षित है।

एलटीएआर पर बिजली का प्रावधान

- ख. सारावक एनर्जी बर्हाड (एसईबी) सारावक के राज्य में एक ऊर्जा विकास कंपनी है। यह कंपनी पब्लिक लिमिटेड देयता कंपनी है। कंपनी का नियंत्रक शेयर-होल्डर राज्य वित्त सचिव, सारावक है, जो सारावक के राज्य वित्त सचिव (निगमन) अध्यादेश के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निगम है। एसईबी सारावक में एकमात्र बिजली आपूर्तिकर्ता है। एसईबी 5 मेगावाट से अधिक बिजली लोड आवश्यकता के साथ सारावक में कंपनियों के साथ बिजली खरीद करार (पीपीए) करता है। अलग-अलग रियायती शुल्क दरों के बारे में 5 मेगावाट से अधिक की लोड आवश्यकता वाली कंपनियों के लिए किया जाता है।
- ग. एसईबी राज्य वित्त सचिव के माध्यम से सारावक राज्य सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और यह सारावक में कंपनियों को बिजली उपलब्ध कराती है। एसईबी एक सार्वजनिक निकाय है क्योंकि इसका स्वामित्व सरकार के पास है और सरकारी कार्य करने के लिए सरकारी प्राधिकारी को अधिकार प्राप्त है।
- घ. पीएमबीटीयू और एसईबी (अथवा इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के बीच पीपीए की समीक्षा पर यह नोट किया गया है कि पीपीए के अंतर्गत वसूले जाने वाले शुल्क निम्नलिखित कारणों से बाजार द्वारा प्रभावित नहीं होती है:
 - i. मानक औद्योगिक शुल्क दरों का निर्धारण एसईबी द्वारा उन कंपनियों के लिए किया जाता है , जिसकी खपत आवश्यकता 5 मेगावाट तक होती है। लेकिन 5 मेगावाट से अधिक की लोड आवश्यकता वाली कंपनियों के लिए, एसईबी (अथवा इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) बहुत कम शुल्क पर प्रत्येक ऐसी कंपनी के साथ एक अलग पीपीए करती है।
 - ii. पीपीए के अंतर्गत शुल्क-दर के निर्धारण के लिए कोई परिभाषित दिशा-निर्देश नहीं है और एसईबी (अथवा इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के साथ पीपीए करने वाली विभिन्न कंपनियों को दी गई दरों में कोई एकरूपता नहीं है।
 - iii. पीएमबीटीयू और एसईबी (अथवा इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के बीच किए गए पीपीए में, एक पूर्व परिभाषित/निर्धारित वार्षिक वृद्धि उपबंध है। लेकिन यह वार्षिक वृद्धि इनपुट कीमतों और/अथवा मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव से जुड़ा हुआ नहीं है और उसके माध्यम से इसका आश यह होता है कि पीपीए के अंतर्गत प्रशुल्क दरें बाजार से प्रभावित नहीं हैं और सब्सिडी देने का कारक ऐसे शुल्क में निहित नहीं है।
 - iv. मलेशिया सरकार ने या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा एसईबी (अथवा इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के माध्यम से यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि

एसईबी (अथवा इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा वसूली जाने वाली कीमतें पीपीए के अधीन पारिश्रमिक अर्थात् खर्च की गई पूर्ण लागत की वसूली की अनुमति देना है।

- ड. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आशियान और ईस्ट एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ई आर आई ए) अनुसंधान परियोजना रिपोर्ट 2015 जिसका शीर्षक “मलेशिया में उर्जा सब्सिडी समाप्त करने का आर्थिक प्रभाव” है, में विशेष रूप से विद्युत की आपूर्ति में मलेशिया में उर्जा सब्सिडी की मौजूदगी को नोट किया है। रिपोर्ट यह नोट किया है कि उर्जा की मांग व्यापक तौर पर स्थायी आर्थिक विकास और बिजली पर उर्जा सब्सिडी नीति के कारण जानबूझकर कम उर्जा कीमतों से प्रभावित होती है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि बिजली और परिवहन ईंधन सब्सिडी का हिस्सा वर्तमान में कम हो रहा है, 2010 में मलेशिया में उर्जा सब्सिडी कुल सकल घरेलू उत्पाद का 4.1 प्रतिशत था, जिसमें प्रति व्यक्ति सब्सिडी 200 यूएस डॉलर था (आई ई ए 2015)।
- च. एमएमएआर सारावक में स्थित नहीं है और इसने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम का उपयोग नहीं किया है अथवा इससे लाभ नहीं उठाया है। पीएमएआर ने बिजली की आपूर्ति के लिए टीएनबी के साथ एक पृथक करार/पीपीए नहीं किया है। सभी उद्योगों के लिए निर्धारित बिजली शुल्क पीएमएआर पर लागू है। इस प्रकार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि पीएमएआर के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि पीएमएआर को छोड़कर मलेशिया के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने अधिकतम और सामान्य दोनों बिजली कर शुल्क जिसे तुलनीय बैंच मार्क प्रशुल्क दर के बारे में निर्णय लेते समय एस ई बी वेबसाइट पर दिया गया है, पर विचार किया है। यह नोट किया जाता है कि पी एम बी टी यू ने अपनी कुल खपत में बिजली के सामान्य खपत के सही हिस्से का उल्लेख नहीं किया है। प्राधिकारी ने इस तथ्य पर विचार करते हुए बैंच मार्क दर का निर्धारण किया है कि पी एम बी टी यू द्वारा खपत की गई बिजली की एक तिहाई सामान्य घंटों के दौरान और शेष दो तिहाई खपत अधिकतम मांग के घंटों के दौरान होता है।

एलटीएआर पर भूमि का प्रावधान

- छ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्धारण पट्टा, प्रीमियम का भुगतान, भूमि के उपयोग की शर्तों आदि सहित सारावक में भूमि का हस्तांतरण सारावक राज्य सरकार के अनन्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। सारावक में भूमि पर शर्तें और प्रतिबंध सारावक की भूमि और सर्वेक्षण विभाग (एलएसडीएस) द्वारा लगाया जाता है। एलएसडीएस निर्धारित समय-सीमा के भीतर क्रियाकलापों की शुरुआत अथवा भवन/सुविधाओं/कारखानों के निर्माण जैसे भूमि पट्टे में निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा करते हुए किसी पट्टेदार पर भुगतान की गई प्रीमियम के प्रतिदाय अथवा भुगतान योग्य प्रीमियम की माफी के द्वारा भूमि के प्रीमियम पर छूट प्रदान करता है।
- ज. सारावक की राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम की माफी उचित पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं अथवा सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से वित्तीय अंशदान के बराबर होता है। लाभ की राशि प्रीमियम की किश्त की माफी/छूट के बाद वास्तव में भुगतान की गई भूमि का प्रीमियम और कंपनी द्वारा भुगतान योग्य भूमि के प्रीमियम के बीच अंतर के बराबर है।
- झ. पीएमबीटीयू द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रश्नावली का उत्तर यह दर्शाता है कि पीएमबीटीयू को इस कार्यक्रम से लाभ मिला। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पीएमबीटीयू के लिए इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। पीएमएआर ने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम का लाभ नहीं उठाया है, इसका उपयोग नहीं किया है अथवा इसे लाभ नहीं हुआ है। इस प्रकार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि पीएमएआर के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि पीएमएआर को छोड़कर मलेशिया के सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

छ. जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा दावा किये गये अतिरिक्त सब्सिडी कार्यक्रम**छ. 1. कच्चे माल एल्यूमीनियम हाइड्रोआक्साइड अथवा एल्यूमिना पर बिक्री कर से छूट****82. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध**

- क. बिक्री कर सामान्य तौर पर मलेशिया से आयात की गई वस्तुओं पर 10 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है। मलेशिया में 2018 में बिक्री कर की लेवी से एल्यूमीनियम हाइड्रोआक्साइड अथवा एल्यूमिना से छूट देते हुए आदेश जारी किया गया था।
- ख. चूंकि एल्यूमीनियम हाइड्रोआक्साइड अथवा एल्यूमिना विचाराधीन उत्पाद के लिए इनपुट्स हैं, अतः लाभ को प्रतिसंतुलित किया जाना अपेक्षित है। इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन मलेशिया में बिक्री कर के भुगतान के बिना एल्यूमिना का आयात करने के बाद किया जाता है।
- ग. याचिकाकर्ता को अन्य इनपुट्स के बारे में पता नहीं है जिनका आयात इस योजना अथवा किसी अन्य योजना जहां समान लाभ प्राप्त किया गया है, के अंतर्गत प्रेस मेटल ग्रुप द्वारा किया गया है।

83. मलेशिया सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

- क. बिक्री कर आदेश 2018 में एल्यूमिना और एल्यूमीनियम हाइड्रोआक्साइड पर 0 प्रतिशत बिक्री कर निर्धारित है। बिक्री कर इन उत्पादों पर एक अप्रत्यक्ष कर है। उत्पादों पर बिक्री कर की दरों के बारे में निर्णय मलेशिया सरकार द्वारा लिया जाता है।
- ख. 0 प्रतिशत बिक्री कर की दर किसी कंपनी अथवा प्रतिष्ठान के लिए विशिष्ट नहीं हैं बल्कि अपने आप इन उत्पादों पर है। इन कच्चे मालों की खरीद करने वाले सभी प्रतिष्ठान 0 प्रतिशत दर के अध्ययाधीन होंगे। उत्पादों पर दर की दरों के बारे में निर्णय लेना सभी देशों में सरकारों की अंतर्निहित और संप्रभु कार्य है। एस सी एम करार के अंतर्गत ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि सभी उत्पादों पर समान दरों पर एक रूप से कर लगाया जाये और यदि किसी उत्पाद पर अन्य उत्पादों की तुलना में कम कर लगाया जाता है तब यह कमतर कर के अध्ययाधीन वस्तुओं की खरीद करने वाले उपक्रम के लिए सब्सिडी होने के बराबर है। इसे एस सी एम करार के अनुच्छेद 2.2 में भी माना गया है।

84. प्राधिकारी द्वारा जांच

- क. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एल्यूमिना और एल्यूमीनियम हाइड्रोआक्साइड पर बिक्री कर की दर का निर्धारण बिक्री कर आदेश 2018 के माध्यम से 0 प्रतिशत किया गया है। सभी प्रतिष्ठानों के लिए मलेशिया में इन उत्पादों पर वही दर लागू है। मलेशिया की सरकार द्वारा निर्धारित बिक्री कर की दर सामान्य तौर पर उन सभी प्रतिष्ठानों जिन्हें एल्यूमिना और एल्यूमीनियम हाइड्रोआक्साइड की आवश्यकता होती है पर लागू है। आयात अथवा उत्पाद की खरीद पर सरकार द्वारा निर्धारित कर की दरें सब्सिडी नहीं होती हैं क्योंकि एस सी एम करार के अनुच्छेद 2.2 में इस बात का विशिष्ट रूप से प्रावधान है कि सरकार के सभी स्तरों जिन्हें वैसा करने का अधिकार प्राप्त है, द्वारा सामान्य तौर पर लागू कर की दरों का निर्धारण अथवा उनमें परिवर्तन को एक विशिष्ट सब्सिडी के रूप में नहीं माना जायेगा। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि मलेशिया से उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

छ. 2 राज्य के स्वामित्व वाले बिजली आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त प्राकृतिक गैस का लाभ**85. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध**

- क. टेनागा नेशनल बरहाड (टी एन बी) प्रायद्वीपीय मलेशिया में बिजली का एकमात्र आपूर्तिकर्ता है और यह पी एम ए आर को बिजली उपलब्ध कराता है। टी एन बी के पूर्ण स्वामित्व वाली 8 विद्युत संयंत्र अधिकांश स्वामित्व वाले; 2 संयंत्र और कम स्वामित्व वाला 1 विद्युत संयंत्र है जो गैस पर कार्य कर रहा है। एस ई बी जो पी एम बी टी यू को बिजली उपलब्ध कराता है के भी पास 3 विद्युत संयंत्र हैं जो गैस पर कार्य कर रहे हैं। इस कारण से दोनों निर्यातक सब्सिडी प्राप्त प्राकृतिक गैस के लाभार्थी हैं।

ख. प्राकृतिक गैस जो मलेशिया में विद्युत का प्राथमिक स्रोत है, की कीमतों का विनियमन सांविधिक रूप से बिजली क्षेत्र के लिए किया जाता है। इस प्रकार विद्युत उचित पारिश्रमिक से कम पर निर्यातकों को उपलब्ध है। इस कारण से यह कार्यक्रम परित्यक्त जो अन्य प्रकार से देय है, के रूप में वित्तीय अंशदान उपलब्ध कराता है और लाभ दिया जाता है।

86. मलेशिया सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

क. घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका में टी एन बी द्वारा आपूर्ति की गई बिजली के लिए सब्सिडी का कोई आरोप नहीं था। ऐसी नई सब्सिडी आरोपों पर कोई जांच शुरू नहीं की जा सकती है।

ख. टी एन बी के लिए, केवल 31 प्रतिशत बिजली का उत्पादन प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हुए किया जाता है। बिजली की आपूर्ति के लिये टी एन बी के साथ पी एम ए आर द्वारा कोई अलग करार नहीं है।

ग. यदि मलेशिया में गैस की कीमतों को सब्सिडी दिया गया हुआ मान भी लिया जाता है तब याचिकाकर्ताओं ने निर्यातकों को इस प्रकार की सब्सिडी प्राप्त कीमतों के लाभ दिया जाना गलत तरीके से माना गया है। यूएस – सॉफ्टवूड लंबर में विश्व व्यापार संगठन की अपील की निकाय ने यह टिप्पणी की थी कि जब प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने वाले कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता कच्चे माल की आपूर्ति एक अन्य असंबंधित प्रतिष्ठान को करता है तब कच्चे माल के असंबंधित क्रेता के पक्ष में सब्सिडी का लाभ देना पास-थ्रू विश्लेषण किये बिना नहीं माना जा सकता है। टी एन बी और एस ई बी निर्यातकों से संबंधित नहीं हैं और निर्यातकों को लाभ दिये जाने का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

87. प्राधिकारी द्वारा जांच

क. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि टी एन बी प्रायद्वीपीय मलेशिया में एकमात्र बिजली प्रदाता है। बिजली का उत्पादन टी एन बी द्वारा प्राकृतिक गैस और अन्य स्रोतों जिसमें हाइड्रो पावर, कोयला आदि शामिल है, के माध्यम से किया जाता है। टी एन बी द्वारा उत्पादन की गई अधिकांश बिजली इन अन्य स्रोतों और न कि प्राकृतिक गैस के माध्यम से की जाती है। पी एम ए आर प्रायद्वीपीय मलेशिया में स्थित है और इसे टी एन बी से बिजली प्राप्त हुई।

ख. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उचित पारिश्रमिक से कम पर बिजली के प्रावधान के सब्सिडी कार्यक्रम की जांच प्राधिकारी द्वारा की गई है। प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी देना और मलेशिया में बिजली आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सब्सिडी प्राप्त प्राकृतिक गैस की खरीद जांच के अधीन सब्सिडी कार्यक्रम नहीं है। यदि इन प्रतिष्ठानों द्वारा प्राप्त की गई प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी दी भी जाती है तब आगे बिना किसी साक्ष्य के बिजली प्राप्त करने वाले प्रतिष्ठानों को लाभ दिये जाने का कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने सब्सिडी के संबंध में नये आरोप बहुत देर से लगाये हैं और इसके साथ ही पर्याप्त सूचना इस आरोप का समर्थन करने के लिए उपलब्ध नहीं करायी गई है कि तेनागा नेशनल बरहाड (टी एन बी) द्वारा सब्सिडी प्राप्त प्राकृतिक गैस का लाभ जांच की अवधि के दौरान टी एन बी से बिजली की खरीद करने वाले प्रतिष्ठानों को दिया गया है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि मलेशिया के उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

छ. 3 चीन जन. गण. की सरकार से प्राप्त किया गया कार्बन एनोड पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी

88. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

क. प्रेस मेटल ग्रुप ने सनस्टॉन डेवलपमेंट कं. लिमि. के साथ चीन में एक संयुक्त उद्यम अर्थात् शानडॉंग सनस्टॉन एंड पी एम बी लिमि. कं. (सनस्टॉन) स्थापित की। सनस्टॉन प्री-वेकड कार्बन एनोड के उत्पादन में लगाया हुआ है जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए एक प्राथमिक कच्चा माल है। प्रेस मेटल के कार्बन एनोड के लिए 50 प्रतिशत आवश्यकता सनस्टॉन से आयातों के माध्यम से पूरी की जाती है।

ख. सनस्टॉन ने 8,645,896,50 यूआन तक चीन जन. गण. की सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सब्सिडी का लाभ उठाया है। इन सब्सिडी ने सनस्टॉन को सब्सिडी प्राप्त दर पर कार्बन एनोड का उत्पादन करने में सक्षम बनाया जिसका लाभ विचाराधीन उत्पादन को हुआ है।

89. मलेशिया सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया अनुरोध

- क. नये सब्सिडी आरोपों की जांच प्राधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती है। पी एम ए आर विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए कार्बन एनोड का उपयोग नहीं करता है।
- ख. चीन जन. गण. की सरकार से सनस्टॉन द्वारा प्राप्त की गई सब्सिडी, यदि कोई हो, मलेशिया सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकारों, जो भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करने और उसका उत्पादन करने वाले देश में सरकार है, द्वारा सब्सिडी नहीं है।
- ग. जब चीन जन. गण. को जांच के अधीन एक देश के रूप में शामिल नहीं भी किया गया हो तब सनस्टॉन के पक्ष में सब्सिडी दिये जाने का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और प्रश्नावली का कोई भी उत्तर चीन जन. गण. की सरकार को जारी नहीं किया गया था।

90. प्राधिकारी द्वारा जांच

- क. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल कार्बन एनोड को सब्सिडी दिये जाने का आरोप चीन जन. गण. में उत्पादकों/ निर्यातकों तथा चीन जन. गण. की सरकार के विरुद्ध है। हालांकि, इस दावे की पुष्टि करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि मलेशिया के उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

मलेशिया के उत्पादक/ निर्यातक**प्रेस मेटल एल्यूमिनियम रॉड्स एसडीएन बीएचडी ("पी एम ए आर") (उत्पादक/ निर्यातक) और प्रेस मेटल बिंतूलू एसडीएन बीएचडी ("पी एम बी टी यू") (उत्पादक/ निर्यातक)**

91. पी एम ए आर पर 100 प्रतिशत स्वामित्व पी एम बी टी यू के पास है। पी एम ए आर मलेशिया और भारत सहित अन्य देशों में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करता है और बिक्री करता है। पी एम बी टी यू प्रेस मेटल एल्यूमिनियम होलिंग बरहाड और बंगा राया एल्यूमिनियम एसडीएन बीएचडी में कम शेयर होल्डर है। पी एम बी टी यू मलेशिया में और भारत सहित अन्य देशों संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री करता है।
92. प्राधिकारी ने प्रेस मेटल एल्यूमिनियम रॉड्स एसडीएन बीएचडी और प्रेस मेटल बिंतूलू एसडीएन बीएचडी द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन किया है और कार्यक्रम संख्या 5, 8, 17 और 23 के लिए सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण किया है जिसके लिये जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त किया गया था और उसमें वृद्धि हुई थी। प्राधिकारी ने यह निर्धारण किया कि सब्सिडी कार्यक्रम 5, 8 और 17 के फलस्वरूप परित्यक्त राजस्व जो अन्य प्रकार से देय था, के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान करना पड़ा और उसके माध्यम से लाभ दिया गया था। प्राधिकारी ने यह निर्धारण किया कि सब्सिडी कार्यक्रम 23 के फलस्वरूप सार्वजनिक निकाय द्वारा उचित से उचित पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं अथवा सेवाओं के प्रावधान के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान करना पड़ा और उसके माध्यम से लाभ दिया गया था।
93. नीचे दी गई तालिका में सब्सिडी कार्यक्रमों का नाम और सदृश्य सब्सिडी मार्जिन दिया गया है।

पी एम ए आर

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण/ टिप्पणी	सब्सिडी मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन रेंज %
कार्यक्रम सं. 5	बढ़ी हुई पूंजी छूट	कर योग्य आय से पूंजी व्यय की बढ़ी हुई कटौती	***%	0-10%
कार्यक्रम सं. 17	मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट	मशीनरी और उपकरण के आयात पर सीमा शुल्क और बिक्री पर छूट	***%	0-10%
कुल			***%	0-10%

पी एम बी टी यू

कार्यक्रम सं.	अनुदान कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण/ टिप्पणी	सब्सिडी मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन रेंज %
कार्यक्रम सं. 5	बढ़ी हुई पूंजी छूट	कर योग्य आय से पूंजी व्यय की बढ़ी हुई कटौती	***%	0-10%
कार्यक्रम सं. 8	पायोनियर दर्जा	आयकर से छूट	***%	0-10%
कार्यक्रम सं. 23	उचित पारिश्रमिक से कम पर भूमि का प्रावधान	भूमि प्रीमियम पर छूट	***%	0-10%
कार्यक्रम सं. 23	उचित पारिश्रमिक से कम पर बिजली का प्रावधान	सार्वजनिक निकाय से कमतर दर पर बिजली की खरीद	***%	0-10%
कुल			***%	5-15%

94. पी एम ए आर और पी एम बी टी यू के लिये निर्धारित सब्सिडी मार्जिन वास्तविक और न्यूनतम स्तर से ऊपर है। पी एम ए आर और पी एम बी टी यू के लिये भारत औसत सब्सिडी मार्जिन नीचे दिये गये अनुसार है :

विवरण	मार्जिन	रेंज
पी एम बी टी यू	***%	5-15%
पी एम ए आर	***%	0-10%
भारत औसत	***%	0-10%

95. सभी अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्धारित सब्सिडी मार्जिन नीचे दिये गये अनुसार है :

मलेशिया के सभी अन्य उत्पादक/ निर्यातक

कार्यक्रम सं.	अनुदान कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण/ टिप्पणी	सब्सिडी मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन रेंज %
कार्यक्रम सं. 1	बाजार विकास अनुदान	निर्यात संवर्धनात्मक में भागीदारी के लिए एस एम ई को अनुदान	***	0-10%
कार्यक्रम सं. 2	व्यापार/ उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार	उत्पादों/ दी गई सेवाओं की गुणवत्ता में एम आई टी आई द्वारा मलेशियाई कंपनियों को उनके सुधार की पहचान करने के लिए अनुदान	***	0-10%
कार्यक्रम सं. 3	निर्यात ऋण पुनःवित्तपोषण	एक्जिम बैंक उत्पादों के निर्यात के लिए वित्त प्रदान करने वाले वास्ते उपक्रम को ऋण उपलब्ध करता है	***	0-10%
कार्यक्रम सं. 4	क्रेता ऋण गारंटी	एक्जिम बैंक वित्तीय संस्थाओं को उनके निर्यातकों द्वारा भुगतान नहीं किये जाने के जोखिम के विरुद्ध गारंटी उपलब्ध कराता है	***	0-10%

कार्यक्रम सं.	अनुदान कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण/ टिप्पणी	सब्सिडी मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन रेंज %
कार्यक्रम सं. 5	बढ़ी हुई पूंजी छूट	कर योग्य आय से पूंजी व्यय की बढ़ी हुई कटौती	***	0-10%
कार्यक्रम सं. 8	पायनियर दर्जा	आयकर से छूट	***	0-10%
कार्यक्रम सं. 17	मशीनरी और आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट	मशीनरी और उपकरण के आयात पर सीमा शुल्क और बिक्री कर पर छूट	***	0-10
कार्यक्रम सं. 18	कच्चे माल/ संघटकों पर आयात शुल्क से छूट	कच्चे माल के आयात पर सीमा शुल्क और बिक्री कर से छूट	***	0-10
कार्यक्रम सं. 23	उचित पारिश्रमिक से कम पर भूमि का प्रावधान	भूमि प्रीमियम पर छूट	***	0-10%
कार्यक्रम सं. 23	उचित पारिश्रमिक से कम पर बिजली का प्रावधान	सार्वजनिक निकाय से कमतर दर पर बिजली की खरीद	***	5-15%
कुल			***	10-20%

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

ज. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किया अनुरोध

96. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध नीचे दिये गये अनुसार हैं :

- क. घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से सब्सिडी प्राप्त आयातों की मौजूदगी के कारण क्षति हुई है।
- ख. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में मांग में गिरावट के बावजूद स्वतंत्र और सापेक्ष दोनों रूप में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।
- ग. आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा है और वे कम होनी हैं।
- घ. क्षमता के उपयोग में 2017-18 के बाद गिरावट आई है तथा जांच की अवधि में यह न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया।
- ङ. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में 2018-19 में और आगे जांच की अवधि में गिरावट आई है। यद्यपि मांग में 5 प्रतिशत तक गिरावट आई, घरेलू उद्योग की बिक्री में 14 प्रतिशत तक गिरावट आई।
- च. संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई।
- छ. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानि, नकद हानि और नकारात्मक निवेश पर लाभ का सामना करना पड़ा है।
- ज. घरेलू उद्योग के पास माल सूची में क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि होती रही है।
- झ. कर्मचारियों की संख्या और भुगतान की गई मजदूरी में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई हालांकि प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई।
- ञ. वृद्धि जांच की अवधि में क्षति संबंधी प्रायः सभी मानदंडों में नकारात्मक रही है।
- ट. सब्सिडी प्राप्त आयातों के द्वारा हो रहे कीमत पर दबाव ने या तो घरेलू उद्योग को लागतों में वृद्धि की सीमा तक अपनी कीमतों में वृद्धि करने से रोका या इसे लागतों में गिरावट से आगे कीमतों को कम करने के लिए मजबूर किया।

- ठ. संबद्ध देश से सब्सिडी प्राप्त आयातों का कीमत ह्रास और न्यूनीकरण प्रभाव के फलस्वरूप घरेलू उद्योग के लाभों में बहुत अधिक गिरावट आई है।
- ड. लाभों, लगाई गई पूंजी पर लाभ और नकद लाभ में गिरावट प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी प्राप्त आयातों का परिणाम है।
- ढ. आयातों में वृद्धि के फलस्वरूप घरेलू बिक्रियों में गिरावट आई और जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई।
- ण. निर्यात घरेलू उद्योग की कुल बिक्री का *** प्रतिशत है। अतः निर्यात में गिरावट उत्पादन और क्षमता के उपयोग के गिरावट का एक कारण नहीं हो सकता है।
- त. घरेलू उद्योग एल एम ई आधारित कीमतें भी देता है।
- थ. यह अनुरोध किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत इलेक्ट्रिकल कंडेक्टर का निर्माण करने वालों द्वारा खपत की जाती है। केंद्र और राज्य विद्युत बोर्ड इन अंतिम कंडेक्टरों की खरीद अपने पारेषण लाइन की आवश्यकताओं के लिये करता है। घरेलू उद्योग के ग्राहक व्यापक तौर पर भारतीय उद्योग द्वारा कच्चे माल (विचाराधीन उत्पाद) की औसत कीमत के आधार पर अपनी कीमतों को निर्धारित करते हैं। इस कारण से, प्रयोक्ताओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ज. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

97. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध नीचे दिये गये हैं :

- क. वर्तमान जांच में जांच की अवधि अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 अर्थात् 9 महीने है, जो उपयुक्त नहीं है। प्राधिकारी की कार्यपद्धति कुछ असामान्यता जो छोटी अवधि के दौरान हो सकती है, पर विश्वास करने के जोखिम से बचने के लिए जांच की अवधि के रूप में छोटी अवधि का चयन नहीं करने की रही है। इस कारण से जांच की अवधि 12 महीने अथवा उससे अधिक होनी चाहिए।
- ख. यदि 12 महीने की पूरी अवधि पर विचार वर्तमान जांच में जांच की अवधि के रूप में किया गया होता तब जांच की अवधि में आयातों में वृद्धि का आकलन यह दर्शाया होता कि क्षति की जांच की अवधि के दौरान आयातों में कोई सतत् वृद्धि नहीं हुई है।
- ग. मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर 0 प्रतिशत सीमा शुल्क लग रहा है जबकि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू सीमा शुल्क की एम एफ एन दर 7.5 प्रतिशत है। मलेशिया से पी यू सी के आयातों में वृद्धि का कारण अन्य देशों की तुलना में और न कि कथित सब्सिडी दिये जाने के कारण 0 प्रतिशत तक सीमा शुल्क में कटौती का लाभ है।
- घ. आवेदकों द्वारा विश्वास किये गये आयात आंकड़े वार्षिकीकृत जांच की अवधि संबंधी आंकड़े पर निर्भरता के कारण सही नहीं है। डी जी एफ टी के डाटाबेस से उपलब्ध पी यू सी का वास्तविक आयात आंकड़ा 2019-20 में कमतर आयातों को दर्शाता है।
- ड. भारत में पी यू सी का कुल आयात जांच की अवधि के दौरान कुल भारतीय उत्पादन का केवल *** प्रतिशत है। मलेशिया से पी यू सी की आयात मात्रा इतनी कम है कि यह घरेलू उद्योग पर मात्रा संबंधी कोई प्रभाव पैदा नहीं कर सकता है।
- च. मलेशिया से पी यू सी के आयातों के लिए कीमत में कटौती जांच की अवधि सहित पिछले 3 वर्षों के लिए नकारात्मक रही है। मलेशिया से निर्यात एल एम ई कीमतों और न कि कृत्रिम रूप से सब्सिडी प्राप्त कीमतों पर आधारित है। कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण जिसका सामना घरेलू उद्योग द्वारा मलेशिया से पी यू सी के आयातों के कारण करना पड़ रहा है, का कोई साक्ष्य नहीं है।
- छ. घरेलू उद्योग की निवल वृद्धि कीमत और बिक्री की लागत की प्रवृत्ति पी यू सी के आयातों के कारण किसी सतत् कीमत प्रभाव को नहीं दर्शाती है।

- ज. जांच की अवधि के दौरान घरेलू बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री की लागत में समानुपातिक गिरावट के साथ आयातों से कीमत पर दबाव का कारण नहीं हो सकता है क्योंकि घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत में भी उसी अवधि के दौरान समानुपातिक रूप से गिरावट आई है।
- झ. घरेलू उद्योग के आयातों और कार्यनिष्पादन संबंधी मानदंडों के बीच कारणात्मक संबंध दर्शाने के लिए घरेलू उद्योग को हुआ अर्जित लाभ/ हानि तथा आयात कीमत के बीच कुछ सह-संबंध होना चाहिए।
- ञ. घरेलू उद्योग के आयातों और कार्यनिष्पादन के बीच लाभ के मामले में कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि जांच की अवधि सहित पिछले 3 वर्षों से कीमत में नकारात्मक कटौती के साथ हानि में वृद्धि हुई है। अतः लाभ में गिरावट के लिये आयात जिम्मेदार नहीं है।
- ट. आयात 2016-17 में बहुत कम था और घरेलू उद्योग को उस अवधि के दौरान फिर भी हानि हुई थी। इस प्रकार आयातों की मात्रा और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई स्पष्ट सह-संबंध नहीं है।
- ठ. घरेलू उद्योग ने भारत में अपने संबंधित पक्षकारों को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री भी की है। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा संबंधित पक्षकारों को की गई बिक्री की जांच पृथक् रूप से करें।
- ड. घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में गिरावट यदि कोई हो, के लिए प्रत्यक्ष रूप से विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट को जिम्मेदार माना जा सकता है।
- ढ. अन्य देशों से प्रति इकाई आयात कीमत वर्ष 2017-18, 2018-19 और जांच की अवधि के दौरान मलेशिया से आयात कीमत की तुलना में बहुत कम थी, प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या क्षति दो अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ आपस में प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है।
- ण. यह तथ्य की हिंडालकों और नालको जैसे बड़े उत्पादकों ने भाग नहीं लिया है, दृढ़ता से यह संकेत देता है कि इन प्रतिष्ठानों ने वर्तमान जांच में जान बूझकर शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इन अन्य प्रतिष्ठानों को बिलकुल ही कोई क्षति नहीं हो रही होगी अथवा क्षति कोई हो संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य कारकों के कारण हुई है।
- त. समान वस्तु को छोड़कर उत्पादकों के संबंध में क्षति संबंधी सूचना को शामिल करने में घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही वास्तविक क्षति को गलत तरीके से पेश करने का जोखिम है।
- थ. निर्यात बिक्री में गिरावट याचिकाकर्ता के उत्पादन और क्षमता के उपयोग में गिरावट के लिए एक प्रमुख कारक है।
- द. परिवर्तनीय कीमत निर्धारण नीति जिसे मलेशिया से निर्यातकों सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया, प्रयोक्ताओं के लिए वाणिज्यिक रूप से अधिक आकर्षक और अधिमन्य है। यही कारण है कि पी यू सी के प्रयोक्ताओं जिन्हें एल एम ई स्पॉट कीमतों से संबद्ध कीमतें नहीं दी जाती हैं, घरेलू उद्योग से खरीद के बजाय संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात करना पसंद करते हैं।
- ध. भारत में एल्यूमिना के आयात पर मूल सीमा शुल्क 10 प्रतिशत है और अन्य कच्चे माल के लिए बी सी डी 7.5 प्रतिशत है। हालांकि, मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर बी सी डी 0 प्रतिशत है। इसके परिणामस्वरूप इससे एक इंवरटिड शुल्क ढांचा बनता है।
- न. प्राधिकारी को इस तथ्य का सत्यापन करना चाहिए कि क्या इस संघ के भीतर "मालटेन एल्यूमिनियम मेटल" और/ अथवा "एल्यूमिनियम इनगोत्स" सहित वेदांता द्वारा एल्यूमिनियम उत्पादों की आंतरिक खरीद स्वतंत्र रूप से हुई है और अन्य गैर पी यू सी क्षेत्र से पी यू सी क्षेत्र तक क्षति का कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।

ज. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

98. हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किये गये उपर्युक्त अनुरोधों के आलोक में, प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किया गया विश्लेषण वास्तव में घरेलू उद्योग और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों पर विचार करता है।
99. सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 13 में क्षति के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांतों की चर्चा की गई है जिसे नीचे दिये गये अनुसार प्रावधान है :

13. क्षति का निर्धारण -

- (1) उल्लिखित देशों से आयातों के मामले में, निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे यह निष्कर्ष देंगे कि भारत में इस प्रकार की वस्तु के आयात से भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति होती है अथवा क्षति होने का खतरा उत्पन्न होता है अथवा वास्तविक रूप से भारत में किसी उद्योग की स्थापना को बाधा पहुंच रही है।
- (2) केवल उस स्थिति को छोड़कर जब क्षति का जांच परिणाम उप-नियम (3) के अंतर्गत किया जाता हो, निर्दिष्ट प्राधिकारी क्षति, क्षति के खतरे, किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक रूप से बाधा और सब्सिडीयुक्त आयात तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण अन्य बातों के साथ साथ इस नियमावली के अनुबंधा निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखकर करेंगे।
- (3) आपवादिक मामलों में निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह जांच परिणाम हो सकता है कि क्या क्षति की मौजूदगी वहां भी भी जहां घरेलू उद्योग को बहुत अधिक मात्रा में क्षति नहीं हुई है यदि -
 - (i) सब्सिडीयुक्त आयातों का अलग किये गये बाजार में संकेंद्रण है, और
 - (ii) सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण इस प्रकार के बाजार में प्रायः सभी उत्पादन के उत्पादकों को क्षति हो रही है।

ज. 3.1. सब्सिडी प्राप्त आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव**i. मांग का आकलन**

100. भारत में संबंधित उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को सभी भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और अन्य सभी देशों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे दिये गये अनुसार है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वार्षिकीकृत	वास्तविक
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	105	86	86
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	101	89	89
संबद्ध देशों - मलेशिया से आयात	मी. ट.	18,813	37,772	65,904	72,983	54,737
अन्य देशों से आयात	मी. ट.	15,623	26,913	27,274	3,419	2,564
कुल भारतीय मांग	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	111	112	95	95

101. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के लिये भारत में मांग में 2018-19 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि के दौरान (वार्षिकीकृत) गिरावट आई है।

ज. 3.2. संबद्ध देश से आयात की मात्रा और आयातों का हिस्सा

102. संबद्ध आयातों की मात्रा के संबंध में, इस पर विचार किया जाना अपेक्षित है कि क्या सब्सिडी प्राप्त आयातों में या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। आयातों के संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वार्षिकीकृत	वास्तविक
संबंध देश – मलेशिया	मी. ट.	18,813	37,772	65,904	72,983	54,737
अन्य देश	मी. ट.	15,623	26,913	27,274	3,419	2,564
कुल आयात की मात्रा	मी. ट.	34,436	64,685	93,178	76,402	57,301
निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध देश से आयात						
उत्पादन	%	3.09	5.82	10.47	13.47	13.47
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	188	339	436	436
खपत	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	181	312	411	411
कुल आयात	%	55	58	71	96	96

103. यह देखा गया है कि :

- क. मांग में गिरावट के बावजूद जांच की अवधि में संबद्ध देश से आयातों की पूर्ण मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
- ख. आयातों में घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में 100 प्रतिशत सूचकांकों से 436 सूचकों तक तीव्र गति से वृद्धि हुई है।
- ग. संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में 100 सूचकांकों से 411 सूचकांकों तक बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।
- घ. ये आयात व्यापक तौर पर संबद्ध देश से हुए हैं और यह जांच की अवधि के दौरान भारत में कुल आयातों का 96 प्रतिशत हिस्सा होता है।

ज. 3.3. संबद्ध आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर इसका प्रभाव

104. कीमतों पर सब्सिडी प्राप्त आयातों के प्रभाव के संबंध में, इस तथ्य की जांच की जानी अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में सब्सिडी प्राप्त आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के सब्सिडी प्राप्त आयातों के प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक कीमतों पर दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाने वाली है जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती।

i. कीमत में कटौती

105. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, कीमत में कटौती का निर्धारण क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ आयातों की पहुंच कीमत से तुलना करते हुए किया गया है। कीमत में कटौती का व्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वार्षिकीकृत	वास्तविक
आयात की पहुंच कीमत	₹/मी. ट.	129,246	151,086	165,616	144,295	144,295
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	128	112	112
निवल बिक्री कीमत	₹/मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	134	118	118

कीमत में कटौती	₹/मी. ट.	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	वार्षिकीकृत	(100)	(59)	(46)	(25)	(25)
कीमत में कटौती	%	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक

106. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कीमत में कटौती जांच की अवधि सहित क्षति की पूरी अवधि के दौरान नकारात्मक है।

ii. कम कीमत पर बिक्री

107. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत (एन आई पी) तय की है और उसकी तुलना कम कीमत पर बिक्री की सीमा तय करने के लिए आयात की गई वस्तुओं की पहुंच मूल्य से की गई है जो नीचे दिया गया है :

विवरण	इकाई	राशि
आयातों की पहुंच कीमत	₹/मी.ट .	144,295
एन आई पी	₹/मी.ट .	***
कीमत पर बिक्री	₹/मी.ट .	***
कीमत पर बिक्री	%	***
कीमत पर बिक्री	रेंज	10-20

108. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कम कीमत पर बिक्री जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक है।

iii. कीमत ह्रास/ न्यूनीकरण

109. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या सबसिडी प्राप्त आयातों के कारण घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ रहा है अथवा वे कम हो रही हैं, क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों पर विचार किया गया है। यह स्थिति नीचे तालिका में दर्शायी गई है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वार्षिकीकृत	वास्तविक
बिक्री की लागत	₹/मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	125	115	115
बिक्री की कीमत	₹/मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	134	118	118
आयातों की पहुंच कीमत	₹/मी. ट.	129,246	151,086	165,616	144,295	144,295
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	128	112	112

110. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयातों की पहुंच कीमत 2016-17, 2018-19 और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम है। जांच की अवधि के दौरान, बिक्री की लागत में 2018-19 की तुलना में 10 सूचकांकों तक गिरावट आई है। दूसरी ओर, उसी अवधि के दौरान बिक्री की कीमत में 16 सूचकांकों तक गिरावट आई है। संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है।

ज. 3.4 घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंड

111. सब्सिडीरोधी नियमावली में यह अपेक्षित है कि क्षति का निर्धारण भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर सब्सिडी प्राप्त आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल करेगा।
112. समान उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर सब्सिडी प्राप्त आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, सब्सिडीरोधी नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग के आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जिसका इस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट शामिल है; घरेलू कीमतों, नकद प्रभाव, माल सूचियों, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कारकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार, घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन की जांच क्षति की अवधि के दौरान की गई है।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग और बिक्री

113. उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग और घरेलू बिक्री के संबंध में क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति नीचे दी गई है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वार्षिकीकृत	वास्तविक
क्षमता	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	84	84	84
उत्पादन	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	105	89	89
क्षमता का उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	124	106	106
घरेलू बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	105	86	86

114. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि :

- क. घरेलू उद्योग की क्षमता में जांच की अवधि में गिरावट आई है। क्षमता में यह गिरावट इसलिए है कि बाल्कों ने विचाराधीन उत्पाद की अपनी दो उत्पादन लाइनों को बंद कर दिया है।
- ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में आधार वर्ष तथा पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में गिरावट आई है।
- ग. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में गिरावट आई है जो भारतीय बाजार में मांग में गिरावट से अधिक है।
- घ. क्षमता के उपयोग में 2018-19 तक वृद्धि हुई है और जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में गिरावट आई है।

ii. बाजार का हिस्सा

115. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा और आयात नीचे दिया गया है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	%	100	97	94	91
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***

प्रवृत्ति	%	100	95	90	94
संबद्ध आयात – मलेशिया	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	%	100	181	312	411
अन्य आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	%	100	155	156	23
कुल मांग	%	100	100	100	100

116. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की पूरी अवधि के दौरान हालांकि मामूली रूप से गिरावट आई है जबकि संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में उसी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

iii. लाभ/ हानि, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर आय

117. लाभ/ हानि, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति नीचे दी गई है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वार्षिकीकृत	वास्तविक
बिक्री की लागत	₹/ मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	125	115	115
बिक्री की कीमत	₹/ मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	134	118	118
लाभ/ हानि	₹/ मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(10)	(35)	(89)	(89)
लाभ/ हानि	₹ लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(11)	(37)	(76)	(76)
पी बी आई टी	₹ लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	376	347	156	156
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	127	35	(89)	(89)
लगाई गई पूंजी पर लाभ	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	360	364	201	201

118. उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है कि :

- क. घरेलू उद्योग को क्षति की पूरी अवधि के दौरान हानि होती रही है। घरेलू उद्योग को हानि जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान वृद्धि हुई है।
- ख. नकद लाभ की वही प्रवृत्ति है जो लाभ की है। घरेलू उद्योग के नकद लाभ में जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक स्तरों पर गिरावट आई है।
- ग. लगाई गई पूंजी पर लाभ में, 2018-19 तक सुधार हुआ लेकिन जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में गिरावट आई।

iv. माल सूची

119. संबद्ध वस्तुओं की माल सूची का आंकड़ा नीचे दिये गये अनुसार है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
माल सूची - औसत	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	162	208	1,911

120. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूचियों में क्षति की अवधि के दौरान और आगे जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।

v. रोजगार, उत्पादकता एवं मजदूरी

121. क्षति की अवधि के दौरान रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वार्षिकीकृत	वास्तविक
मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	61	71	54	54
कर्मचारी	सं.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	74	65	65
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	141	136	136

122. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रोजगार और मजदूरी में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है। उत्पादकता में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि ये मानदंड घरेलू उद्योग पर सन्निधि प्राप्त आयातों के प्रभाव के सूचक नहीं हैं।

vi. वृद्धि

123. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वृद्धि संबंधी मानदंडों की जांच नीचे दर्शायी गई है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
उत्पादन	%	-	7.08	(2.38)	(15.11)
घरेलू बिक्री	%	-	7.66	(2.49)	(18.17)
लाभ/ हानि	%	-	88.90	(229.53)	(108.38)
नकद लाभ	%	-	226.87	(72.80)	(356.53)
लगाई गई पूंजी पर आय	%	-	260.19	0.93	(44.84)

124. यह नोट किया जाता है कि वृद्धि उत्पादन, घरेलू बिक्री, लाभ, नकद लाभ और लगाई पूंजी पर आय के संबंध में जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में नकारात्मक रही है। सभी प्रमुख कीमत संबंधी मानदंड, जैसे लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर आय में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट दर्शाया है।

vii. नए निवेश जुटाने की क्षमता

125. घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक हानि हुई है जिसने बाद में घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को कमजोर किया है।

ज. 3.5 कारणात्मक संबंध

126. इस तथ्य की जांच की गई है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

127. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा न्यूनतम स्तरों पर है।

ख. मांग में संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

128. विचाराधीन उत्पाद के लिये मांग में जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में गिरावट आई है। देश में मांग में गिरावट के बावजूद, संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। खपत के पैटर्न में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

ग. विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियां और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

129. ऐसी कोई ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धति नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकती थी।

घ. प्रौद्योगिकी का विकास

130. हितबद्ध पक्षकारों में से किसी ने प्रौद्योगिकी में परिवर्तन जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी, को दर्शाने के लिये कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

ङ. घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन

131. यह नोट किया जाता है कि क्षति का विश्लेषण घरेलू कार्यनिष्पादन पर आधारित है। इस कारण से क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात कार्यनिष्पादन के कारण नहीं हुई है।

च. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन

132. प्राधिकारी ने केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में आंकड़ों पर विचार किया है।

ज. 3.6. कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक

133. निम्नलिखित कारक सब्सिडी प्राप्त आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करते हैं।

क. संबद्ध देश सब्सिडी प्राप्त आयातों में स्वतंत्र रूप में और भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में वृद्धि हुई है।

ख. सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रास/न्यूनीकरण हो रहा है।

ग. घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता के उपयोग में जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान कमी आई है।

घ. जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान लाभ, लगाई गई पूंजी पर लाभ और नकद लाभ में गिरावट आई है।

ज. 3.7. क्षति मार्जिन का परिमाण

134. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत, जिसका निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है, की तुलना जांच की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिये संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है। इस प्रकार से निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दिये गये अनुसार है :

क्षति मार्जिन

क्र. सं.	देश	उत्पादक	एन आई पी	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज %
1.	मलेशिया	(i) प्रेस मेटल बिंदूल एसडीएन. बीएचडी.	***	***	***	***	10-20

		(ii) प्रेस मेटल एल्यूमिनियम रॉड्स एसडीएन. बीएचडी.					
2.	मलेशिया	अन्य सभी	***	***	***	***	10-20

135. क्षति मार्जिन का स्तर जैसा कि निर्धारित किया गया है बहुत अधिक है।

झ. प्रकटन पश्चात् टिप्पणियां

136. प्राधिकारी ने इस मामले के आवश्यक तथ्यों को प्रकट करते हुए और हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए दिनांक 18 जून, 2021 को एक प्रकटन विवरण जारी किया। प्रकटन पश्चात् अनुरोध हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हो गये हैं। प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियों में उठाये गये अधिकांश मुद्दों का पूर्व में भी उठाया गया है और उसका समाधान भी उपयुक्त रूप से किया गया है। अतिरिक्त अनुरोधों की जांच उस सीमा तक की गई है जिस सीमा तक उन्हें संगत माना गया है और वे नीचे दिये गये अनुसार हैं :

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- उत्तर देने वाले उत्पादकों/ निर्यातकों के द्वारा प्रस्तुत की गई पूरक सूचना का परिचालन नहीं किये जाने के संबंध में अनुरोधों का समाधान प्रकटन विवरण में नहीं किया गया है।
- विचाराधीन उत्पाद “क्वाइल रूप में एल्यूमिनियम तार/ क्वाइल रूप में रॉड” होना चाहिए। पी एम बी टी यू और पी एम ए आर क्वाइल रूप में एल्यूमिनियम तार और/ रॉड का उत्पादन करता है, जिसे तकनीकी, वाणिज्यिक और सीमा शुल्क बातचीत में “तार रॉड” के रूप में जाना जाता है।
- घरेलू उद्योग क्वाइल रूप में केवल तार रॉड का उत्पादन करता है। यह रॉड अथवा तार रॉड जो क्वाइल रूप में नहीं है का उत्पादन नहीं करता है। एल्यूमिनियम तार रॉड जो क्वाइल रूप में नहीं है; एल्यूमिनियम जो क्वाइल रूप में नहीं है और एल्यूमिनियम तार जो क्वाइल रूप में है और जो 7 मिमी. त्रिज्या से कम की हो, को इस याचिका में घरेलू उद्योग द्वारा बाहर नहीं किया गया था।
- चूंकि विचाराधीन उत्पाद का आयात विभिन्न कोड्स के अंतर्गत किया जाता है, अतः प्राधिकारी शुल्क तालिका में इन कोडों को दर्शा सकते हैं और यह उल्लेख कर सकते हैं कि वह केवल सांकेतिक है।
- पी एम बी टी यू और पी एम ए आर +/- 0.76 मिमी. की सहनशीलता के साथ 9.52 मिमी. त्रिज्या के उत्पाद का उत्पादन करता है। इसी उत्पाद का निर्यात 9 मिमी. त्रिज्या से कम पर किया जा सकता है। इस कारण से 9 मिमी. और 12.5 मिमी. के बीच इस उत्पाद का प्रतिबंध उपयुक्त नहीं है। पी एम बी टी यू और पी एम आर 7.6 मिमी. तक कम आकार किये गये त्रिज्या वाले उत्पाद का निर्यात कर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क से प्रवंचना कर सकते हैं। घरेलू उद्योग 7 मिमी. त्रिज्या से ऊपर और 12.5 मिमी. त्रिज्या से ऊपर के उत्पाद का उत्पादन करने में सक्षम हैं। इस उत्पाद के विवरण में मलेशिया से आयात किये गये उत्पाद और वह उत्पाद जिसका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा किया जाता है, शामिल होना चाहिए।
- यह निर्यात और मलेशिया सरकार की जिम्मेदारी है कि वे अतिरिक्त सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में सूचना उपलब्ध करायें। इस चरण में जिसकी कोई सीमा नहीं है जिस पर सब्सिडी के संबंध में नई सूचना प्राधिकारी के ध्यान में लायी जा सकती है। सब्सिडी के संबंध में नई सूचना की भी जांच प्राधिकारी द्वारा “फाइबर बोर्ड” संबंधी पिछली सी वी डी जांच में की गई थी। घरेलू उद्योग पर साक्ष्य संबंधी जिम्मेदारी केवल उन्हें तर्कसंगत रूप से उपलब्ध सूचना उपलब्ध कराने की है।
- पी एम बी टी यू और पी एम ए आर ने ए यू एल अवधि के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

- कार्यक्रम सं. 11 और 12 अनुचित अनुपात में उन उद्योगों को लाभ पहुंचाता है जिनका बहुत अधिक पूंजी खर्च है। इन कार्यक्रमों को प्राधिकारी द्वारा पूर्व में प्रतिसंतुलनकारणीय माना गया था।
- कार्यक्रम सं. 15 में प्राधिकारी को इस कार्यक्रम के अंतर्गत भी उपलब्ध कराए गए बिक्री कर को वापस लेने की जांच करनी चाहिए।
- कार्यक्रम सं. 16 में, प्राधिकारी को इस कार्यक्रम के अंतर्गत भी उपलब्ध कराये गये बिक्री कर से छूट की जांच करनी चाहिए।
- कार्यक्रम सं. 23 – एल टी ए आर पर बिजली का प्रावधान में, पी एम बी टी यू द्वारा किये गये खर्च की कटौती लाभ से नहीं की जानी चाहिए। पी एम बी टी यू के बिजली लाभ के लिए मात्रा के निर्धारण संबंधी पद्धति पर फिर से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि अंतिम मील कनेक्शन के लिए खर्च पीपीए के अंतर्गत किया जाता है और मानक नियमों को इस कार्यक्रम के साथ अनन्य रूप से जोड़ा नहीं जाता है।
- प्राधिकारी को एल टी ए आर पर टी एन बी द्वारा पी एम ए आर को बिजली के प्रावधान के संबंध में पूर्व में किये गये घरेलू उद्योग के अनुरोधों पर फिर से विचार करना चाहिए।
- कार्यक्रम सं. 23 – एल टी ए आर पर भूमि के प्रावधान में प्राधिकारी ने इस पर विचार नहीं किया है कि जिस भूमि पर लगान लगाया गया है वह बाजार के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है और समुचित पारिश्रमिक से कम है। पी एम ए आर द्वारा प्राप्त किया गया भूमि पर लाभ के संबंध में प्राधिकारी को पी एम ए आर के लिए लागू प्रीमियम राशि और पट्टा लगान की जांच करनी चाहिए।
- घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है जिसका सब्सिडी प्राप्त संबद्ध आयातों से कारणात्मक संबंध है।
- पी एम आर ए एक 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है जिसका स्वामित्व पी एम बी टी यू के पास और इस कारण से पी एम बी टी यू के लिए तय किये गये सभी सब्सिडी मार्जिन को पी एम ए आर में जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि पी एम ए आर अपना 100 प्रतिशत मूल कच्चा माल पी एम बी टी यू से प्राप्त करता है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

- प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में संशोधन के आलोक में आयात संबंधी आंकड़ों का फिर से जांच करनी चाहिए। आयात संबंधी आंकड़े जिस पर आरंभ में विचार किया गया था में 7 मिमी. त्रिज्या से ऊपर का त्रिज्या वाला विचाराधीन उत्पाद शामिल था। प्राधिकारी को अपने क्षति संबंधी विश्लेषण में 9 मिमी. से 12.5 मिमी. के त्रिज्या वाले विचाराधीन उत्पाद के आयात आंकड़ों पर विचार करना चाहिए।
- घरेलू उद्योग के आधार को स्थापित नहीं किया गया है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन में वेदांता इंडस्ट्रीज लिमि. और बाल्को के सही सही प्रतिशत हिस्से के बारे में नहीं बताया गया है। ऐसा कोई स्पष्टीकरण भी नहीं है कि क्यों अन्य प्रमुख उत्पादकों – हिंडाल्को और नाल्को ने संबद्ध जांच में भाग नहीं लिया है। प्राधिकारी को संबद्ध जांच में घरेलू उद्योग के प्रतिनिधित्व की फिर से जांच करनी चाहिए।
- प्रकटन विवरण (1) क्या वेदांता लिमि. ने क्षति की अवधि के दौरान किसी अन्य देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है; (2) क्या एस पी टी एल ने क्षति की अवधि के दौरान मलेशिया अथवा किसी अन्य देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, का समाधान नहीं करता है।
- अग्रणी दर्जा कार्यक्रम विशिष्ट नहीं है क्योंकि यह कंपनी के स्वामित्व चाहे वह स्थानीय हो अथवा विदेशी स्वामित्व हो, पर विचार किये बिना लघु और मध्यम उपक्रमों से लेकर बड़े उपक्रमों वाली कंपनियों के व्यापक सीमा तक उपलब्ध है। अग्रणी दर्जा कंपनी मलेशिया के किसी भी राज्य में, या तो प्राथमिक, अनेक उद्योगों तक फैले हुए निर्माण अथवा सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनी के रूप में स्थित हो सकती है।

- प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के नियम 11 के अंतर्गत अपेक्षा को पूरा नहीं किया गया है क्योंकि अग्रणी दर्जा कार्यक्रम यह देखते हुए किसी उपक्रम अथवा उपक्रम समूह अथवा किसी उद्योग अथवा उद्योग समूह के लिये विशिष्ट नहीं है कि पात्र संवर्धित क्रियाकलाप बहुत अधिक व्यापक, विविध, उदार और बहुत अधिक स्थान तक फैला हुआ है।
- अग्रणी दर्जे के लिए ये श्रेणियों, उद्योग, क्षेत्रों, उत्पादों अथवा क्रियाकलापों की संख्या इतनी विविध है कि उन पर उद्योगों के एक समूह के रूप में विचार नहीं किया जा सकता।
- कार्यक्रम सं. 5 और 8 क्षेत्र, प्रक्षेत्र, उपक्रम आदि पर विचार किये बिना सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध आयकर रियायतों की प्रकृति की है। ये लाभ क्षैतिज आधार पर उपलब्ध हैं और वस्तुनिष्ठ मानदंड का अनुसरण करते हैं।
- पी एम ए आर ने जांच की अवधि के दौरान कार्यक्रम सं. 17 का लाभ नहीं उठाया, इसका उपयोग नहीं किया और उसे इससे लाभ प्राप्त नहीं हुआ। पी एम ए आर द्वारा उपयोग की गई मशीनरी और उपकरण के आयात के लिए बिक्री कर से अंतिम बार छूट का अनुमोदन 2014 में किया गया था और इसका लाभ 2015 में लिया गया था। पी एम ए आर ने 2016-2019 में इस कार्यक्रम का लाभ नहीं उठाया, इसका उपयोग नहीं किया अथवा इससे उसे लाभ नहीं हुआ।
- प्राधिकारी को 2016-2019 के बीच पी एम ए आर द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत छूट का उपयोग नहीं किये जाने पर विचार करना चाहिए और यह कि पी एम ए आर को जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत माप किये जाने योग्य कोई लाभ नहीं मिला है जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।
- पी एम बी टी यू और एस ई बी के बीच विद्युत खरीद करार (पी पी ए) का प्राधिकारी द्वारा आकलन पूर्ण नहीं है। प्राधिकारी को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वे सभी उपभोक्ता जिन्हें 5 मेगावाट के अधिक बिजली की जरूरत है, पी पी ए सुविधा के लिए पात्र हैं और लागू मानदंड वस्तुनिष्ठ प्रकृति के हैं।
- पी पी ए पी एम बी टी यू और एस ई बी के बीच एक वाणिज्यिक संविदा है जिसे बिना किसी प्रभाव के तय किया जाता है। सारावक में थोक बिजली की बिक्री के लिये कोई कार्यक्रम नहीं है। एस ई बी इच्छुक क्रेता और इच्छुक विक्रेता के आधार पर स्वतंत्र वाणिज्यिक मोल भाव के माध्यम से बिजली की बिक्री करता है। इस कारण से पी पी ए के अंतर्गत निर्धारित प्रशुल्क दर के लिए कोई पूर्व परिभाषित दिशानिर्देश नहीं हो सकते हैं।
- वर्ष 2019 में प्रति यूनिट बिजली की बिक्री की एस ई बी लागत एस ई बी की वित्तीय विवरणी के अनुसार दी गई है और इसकी तुलना पी पी ए के अंतर्गत प्रशुल्क से की जानी चाहिए। पी पी ए के अंतर्गत एस ई बी द्वारा वसूली गई कीमतें लाभप्रद नहीं हैं क्योंकि एस ई बी बिजली की बिक्री उस कीमत पर करती है जो इसकी लागत की कीमत से अधिक होती है।
- पी पी ए की दरें एस ई बी द्वारा निर्धारित प्रकाशित प्रशुल्क दरों से कम हैं क्योंकि (1) वे ग्राहक जो पी पी ए से संबद्ध नहीं हैं एस ई बी के बिजली वितरण नेटवर्क से बिजली प्राप्त करते हैं। वितरण नेटवर्क की लागत बिजली के उत्पादन और बिक्री की कुल लागत का एक तिहाई होता है; (2) पी पी ए ग्राहक एस ई बी के बिजली वितरण नेटवर्क का उपयोग नहीं करते हैं; (3) वे ग्राहक जो पी पी ए से संबद्ध नहीं हैं की कोई न्यूनतम खपत प्रतिबद्धता नहीं होती है; (4) पी पी ए ग्राहकों को यह प्रतिबद्धता अवश्य करनी चाहिए कि वे प्रतिबद्ध मात्रा की कम से कम 95 प्रतिशत की खपत करें अन्यथा उन्हें 95 प्रतिशत उपयोग की न्यूनतम प्रतिबद्धता के लिए भुगतान करना होता है; (5) पी पी ए ग्राहक 10-25 वर्षों की अवधि के लिए दीर्घावधि आधार पर थोक मात्राओं में खरीद करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं।
- एस ई बी एक लाभप्रद व्यापार उद्यम है। 2018 में, एस ई बी की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी ने एम वाई आर 1.28 बिलियन का निवल लाभ दर्ज किया। यदि एस ई बी किसी अलाभप्रद कारोबार में शामिल हो रहे होते तब इसे बहुत अधिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ होता।

- पी एम बी टी यू, एस ई बी से थोक में बिजली खरीदता है। एस ई बी की बिजली की अधिकांश खरीद (70 प्रतिशत) थोक ग्राहकों जैसे पी एम बी टी यू से होती है। यह दर्शाता है कि एस ई बी का अधिकांश लाभ भी पी एम बी टी यू जैसे थोक उपभोक्ताओं के कारण होता है। इस कारण से एस ई बी को ग्राहकों से पी पी ए के अंतर्गत लाभप्रद कीमत वसूलता है और ऐसी बिक्री से लाभ अर्जित करता है।
- प्राधिकारी द्वारा जिस बैंच मार्क प्रशुल्क दर का चयन अपने सब्सिडी मार्जिन के निर्धारण में किया जाता है वह एक तुलनीय बैंच मार्क नहीं है क्योंकि यह बिजली की खुदरा बिक्री पर आधारित है। एस सी एम करार के अनुच्छेद 14(घ) में यह अपेक्षित है कि लाभ की समुचितता का निर्धारण खरीद और बिक्री की शर्तों सहित बाजार की मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर किया जाये। प्राधिकारी को एस ई बी द्वारा पी एम बी टी यू को बिक्री के संबंध में बैंच मार्क कीमत की तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए बैंच मार्क कीमत तक नीचे की ओर समायोजन करना चाहिए।
- बैंच मार्क प्रशुल्क दर जिसका चयन प्राधिकारी द्वारा अपने सब्सिडी मार्जिन के निर्धारण में किया गया है, भी एक तुलनीय बैंच मार्क नहीं है क्योंकि यह पी एम बी टी यू द्वारा बिजली की सामान्य घंटों की दौरान खपत नहीं है। पी एम बी टी यू एक दिन में 24 घंटे, एक वर्ष में 365 दिन कार्य करता है। इसकी सामान्य घंटों के दौरान बिजली की बहुत अधिक खपत है। इस कारण से प्राधिकारी को बी एम बी टी यू द्वारा सामान्य घंटों के दौरान बिजली की खपत पर विचार करते हुए एक उपयुक्त बैंच मार्क अपनाना चाहिए।
- पी एम बी टी यू और पी एम ए आर ने यह प्रस्ताव किया है कि प्राधिकारी को सब्सिडी मार्जिन के निर्धारण में तुलनीय बैंच मार्क के रूप में भारत में हाइड्रो पावर प्रशुल्क दर का विकल्प अपनाना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि एस ई बी का 70 प्रतिशत बिजली उत्पादन हाइड्रो पावर से होता है।
- एल टी ए आर पर भूमि का प्रावधान एक प्रतिसंतुलनकारीय सब्सिडी कार्यक्रम नहीं है। बी एम बी टी यू द्वारा प्राप्त किया गया भूमि के प्रीमियम पर छूट सारावक के भूमि और सर्वेक्षण विभाग ("एल एस डी एस") द्वारा निर्धारित वस्तुनिष्ठ शर्तों के अनुसार है। पी एम बी टी यू 5 वर्षों के भीतर अनुमोदित औद्योगिक क्रियाकलाप का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने और भवन के निर्माण कार्य को पूरा करने में सफल रहा और इस कारण से एल एस डी एस ने प्रीमियम की चौथी किस्त को वापस किये जान और प्रीमियम की 5वीं किस्त माफ किये जाने के लिये पी एम बी टी यू के आवेदन को अनुमति दी। यदि एल एस डी एस द्वारा निर्धारित वस्तुनिष्ठ मानदंडों को पूरा किया जाता है तब इस प्रकार की छूट औद्योगिक भूमि के सभी पट्टेदारों पर लागू होता है।
- एल टी ए आर पर भूमि के प्रावधान के लिए मलेशिया की सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जाता है और भूमि के प्रीमियम पर छूट के लिये एल एस डी एस द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड वस्तुनिष्ठ हैं।
- कार्यक्रम सं. 5, 8, 17 और 23 में प्राधिकारी द्वारा सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण एस सी एम करार के अनुच्छेद 15.5 के अनुसार नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा कथित सब्सिडी प्राप्त आयातों और इसको हुई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- प्राधिकारी ने एस सी एम करार के अनुच्छेद 12.8 के विपरीत प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां उपलब्ध कराने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त समय और अवसर नहीं दिये।
- भारत में विचाराधीन उत्पाद का कुल आयात जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का कुल भारतीय उत्पादन का केवल 14-15 प्रतिशत है। दूसरी ओर, समग्र रूप में लिये गये घरेलू उत्पादक जांच की अवधि में 87 प्रतिशत से अधिक हिस्से के साथ बाजार पर हावी हैं।
- घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में क्षति की अवधि में बिक्री की लागत में वृद्धि और गिरावट के अनुरूप वृद्धि हुई और गिरावट आई। घरेलू बिक्री कीमतें आयातों की पहुंच कीमतों से अप्रभावित रही हैं। इस प्रकार जैसा कि प्राधिकारी द्वारा अनुमान लगाया गया है कीमत में कोई ह्रास अथवा न्यूनीकरण नहीं हुआ है।

- बिक्री की लागत में समानुपातिक गिरावट के बिना जांच की अवधि के दौरान घरेलू बिक्री कीमत में गिरावट के लिये आयातों से कीमत पर बने दबाव को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत में भी उसी अवधि के दौरान समानुपातिक रूप से गिरावट आई है।
- 2017-18 में घरेलू उद्योग को लाभ हुआ जबकि कीमत में कटौती नकारात्मक थी। 2018-19 में घरेलू उद्योग को कीमत में कटौती के नकारात्मक बने रहने के बावजूद हानि हुई। इस कारण से आयातों तथा घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन के बीच लाभ के संबंध में कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री घरेलू मांग को बहुत निकटता से दर्शा रहा है। क्षति की जांच की अवधि के दौरान बिक्री में गिरावट के लिये मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद के आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- कीमत में प्रतिस्पर्धा पर घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हुई हो अन्य देशों से आयातों के कारण हुई है। अन्य देशों से प्रति यूनिट आयात कीमत वर्ष 2017-18, 2018-19 और जांच की अवधि के दौरान मलेशिया से आयात की कीमत की तुलना में बहुत अधिक कम थी।
- प्राधिकारी ने यह टिप्पणी की है कि घरेलू उद्योग की क्षमता में बाल्को द्वारा विचाराधीन उत्पाद के अपने दो उत्पादन लाइनों को बंद किये जाने के कारण जांच की अवधि में गिरावट आई है। प्रकटन विवरण जारी किये जाने के पूर्व किसी भी समय इस तथ्य को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के ध्यान में नहीं लाया गया है।
- प्राधिकारी ने पूर्व में किये गये इस अनुरोध पर विचार नहीं किया है कि घरेलू उद्योग व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धति में शामिल है जहां इसके द्वारा प्रयोक्ता उद्योग से वसूली जाने वाली कीमतें तदर्थ और अपरिवर्तनशील हैं क्योंकि वे लंदन मेटल एक्सचेंज द्वारा दर्शायी गई कीमतों के अनुपात में नहीं है। दूसरी ओर, मलेशिया के उत्पादकों द्वारा वसूली जाने वाली कीमतें लंदन मेटल एक्सचेंज द्वारा दर्शायी गई कीमतों के समानुपातिक रूप में चलती है।
- यदि प्राधिकारी यह निर्धारण करते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की सिफारिश की जानी चाहिए, प्राधिकारी को प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की संदर्भ कीमत रूप की सिफारिश करनी चाहिए। शुल्क दर का यथामूल्य रूप विचाराधीन उत्पाद की प्रकृति को देखते हुए उपयुक्त नहीं होगा।

प्राधिकारी द्वारा जांच

137. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अधिकांश अनुरोध को बार-बार दोहराया गया है और उनका पहले ही समाधान प्रकटन विवरण में कर दिया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच उस सीमा तक की है जिस सीमा तक उन्हें संगत माना गया और उनका अन्य किसी स्थान पर समाधान नहीं किया गया था।
- जहां तक उत्तर देने वाले उत्पादकों/ निर्यातकों के द्वारा प्रस्तुत की गई पूरक सूचना को परिचालित नहीं किये जाने के संबंध में अनुरोध का प्रश्न है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मलेशिया के उत्तर देने वाले उत्पादकों/ निर्यातकों अथवा मलेशिया सरकार को कोई पूरक प्रश्नावली जारी नहीं की गई थी। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन कार्य किये जाने के दौरान उत्तर देने वाले उत्पादकों/ निर्यातकों तथा मलेशिया सरकार से समर्थन करने वाली सूचना/ बैकअप दस्तावेज के लिये अनुरोध किया। प्राधिकारी की घरेलू उद्योग को विदेशी उत्पादकों/ निर्यातकों के द्वारा और विदेशी उत्पादकों/ निर्यातकों को घरेलू उद्योग द्वारा सत्यापन कार्य के दौरान प्रस्तुत की गई सूचना को प्रकट नहीं करने की निरंतर कार्यपद्धति है।
 - जहां तक विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में अनुरोध का प्रश्न है, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में घरेलू उद्योग के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अंतिम तौर पर इस तथ्य का निर्धारण किया है कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “9 मिमि. से 13 मिमि. तक के व्यास वाले क्वॉयल रूप में एल्युमिनियम वॉयर/ क्वॉयल रूप में वॉयर रॉड” है।

- जहां तक 9 मिमि. से कम के व्यास और 12.5 मिमि. से अधिक के व्यास वाले उत्पाद को शामिल करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र का विस्तार करने हेतु अनुरोध का प्रश्न है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस मामले में यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान 9 मिमि. से कम के व्यास वाले क्वॉयल रूप में एल्युमिनियम वॉयर/ वॉयर रॉड का उत्पादन और उसकी बिक्री नहीं की है। प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में, घरेलू उद्योग ने इस साक्ष्य को प्रस्तुत किया है कि इसने जांच की अवधि के दौरान 13 मिमि. व्यास वाले क्वॉयल रूप में एल्युमिनियम वॉयर/ क्वॉयल रूप में वॉयर रॉड का उत्पादन और बिक्री नहीं की है। अतः प्राधिकारी इसे उपयुक्त मानते हैं कि 9 मिमि. व्यास से 13 मिमि. व्यास तक के विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को प्रतिबंधित किया जाए।
- जहां तक अतिरिक्त सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने वास्तव में उन सभी अतिरिक्त सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच की है जिसके लिए घरेलू उद्योग द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई थी।
- जहां तक घरेलू उद्योग के इस दावे का प्रश्न है कि पी एम बी टी यू और पी एम ए आर ने सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए ए यू एल अवधि के वास्ते सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्तर देने वाले उत्पादकों/ निर्यातकों ने जहां कहीं भी लागू हो, ए यू एल अवधि के लिए सूचना उपलब्ध कराई है।
- जहां तक घरेलू उद्योग के इस अनुरोध का प्रश्न है कि कार्यक्रम सं. 11, 12, 15 और 16 प्रतिसंतुलनकारणीय हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम सं. 11 और 12 प्रतिसंतुलनकारणीय नहीं हैं क्योंकि इन कार्यक्रमों में क्रमशः भवन और संयंत्र एवं मशीनरी पर ह्रास की सामान्य कटौती का प्रावधान है और इस कारण से इसके फलस्वरूप अन्य प्रकार से देय राजस्व का परित्याग नहीं होता है। प्राधिकारी ने इस तथ्य का निर्धारण किया है कि कार्यक्रम सं. 15 और 16 के लिये कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि कच्चे माल पर आयात शुल्क से छूट पर कार्यक्रम सं. 18 के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया गया है।
- जहां तक आयात आंकड़ों की सटीकता सके संबंध में अनुरोध का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने अपने क्षति संबंधी विश्लेषण में विचाराधीन उत्पाद के आयात आंकड़ों पर विचार किया है।
- जहां तक घरेलू उद्योग के आधार का प्रश्न है, प्राधिकारी ने यह निर्धारण किया है कि वेदांता लिमि. और बाल्को का उत्पादन सी वी डी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का बहुत बड़ा अनुपात है। सी वी डी जांच में घरेलू उद्योग के संघटकों के रूप में सभी घरेलू उत्पादकों के भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि घरेलू उत्पादक जिनके पास भारतीय उत्पादन का बहुत बड़ा अनुपात है, ने घरेलू उत्पादक के संघटक के रूप में इस जांच में भाग लिया हो तो यह पर्याप्त है।
- जहां तक वेदांता लिमि. और एस पी टी एल द्वारा किये गये आयातों के संबंध में अनुरोध का प्रश्न है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि न तो वेदांता लिमि. और न ही एस पी टी एल ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश अथवा किसी अन्य देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है।
- जहां तक कार्यक्रम सं. 5, अग्रणी दर्जा कार्यक्रम पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने की योग्यता का प्रश्न है, प्राधिकारी ने यह निर्धारण किया है कि इस कार्यक्रम में आयकर से छूट के रूप में कर प्रोत्साहन का प्रावधान है और यह परित्यक्त राजस्व जो अन्य प्रकार से देय हो, के रूप में वित्तीय अंशदान हो जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उन कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो अग्रणी दर्जा वाली कंपनी होने के लिए पात्रता के मानदंड को पूरा करते हैं।
- जहां तक कार्यक्रम सं. 17 पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने की योग्यता का प्रश्न है, पी एम ए आर ने ए यू एल अवधि के दौरान अपनी पूंजीगत वस्तुओं पर लाभ प्राप्त किया है। इस कारण से प्राधिकारी ने इस तथ्य का निर्धारण किया है कि जांच की अवधि के दौरान हुए लाभ के लिए पी एम ए आर के वास्ते इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

- जहां तक कार्यक्रम सं. 23, विशेष रूप से एल टी ए आर पर बिजली के प्रावधान पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने की योग्यता का प्रश्न है, प्राधिकारी इस तथ्य का निर्धारण करते हैं कि पी पी ए के माध्यम से एस ई बी द्वारा बिजली की बिक्री के लिए अधिमान्य प्रशुल्क दर उचित पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं/ सेवा के प्रावधान के रूप में सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान है। प्राधिकारी ने पी एम बी टी यू के लिए इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने का निर्णय लिया है। सी बी डी नियमावली के अनुबंध IV के साथ पठित नियम 12 के अनुसार, प्राधिकारी ने लाभ की राशि की गणना करते समय क्षति की अवधि को आवंटित पी पी ए के अनुसरण में पी एम बी टी यू द्वारा अंतिम मील कनेक्शन के लिए अतिरिक्त संस्थापना पर खर्च की गई लागत के प्रति व्यय में कटौती की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पी एम बी टी यू ने पी पी ए के अंतर्गत अपने दायित्वों के कारण वास्तविक व्यय और न कि सामान्य व्यय के रूप में खर्च किया है।
- जहां तक इस अनुरोध का प्रश्न है पी एम बी टी यू अधिकतम और सामान्य घंटों दोनों के दौरान बिजली की खपत करता है और इस कारण से बेंचमार्क दर में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पी एम बी टी यू द्वारा किये गये अनुरोध में दम है। प्राधिकारी ने तदनुसार एल टी ए आर पर बिजली के प्रावधान से संबंधित कार्यक्रम सं. 23 के अंतर्गत लाभ के निर्धारण के लिये विचार किये गये बेंचमार्क दर में संशोधन किया है। प्राधिकारी ने तुलनीय बेंचमार्क प्रशुल्क दर के बारे में निर्णय करते समय एस ई बी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये अधिकतम और सामान्य दोनों बिजली प्रशुल्क पर विचार किया है। यह नोट किया जाता है कि पी एम बी टी यू ने अपनी कुल खपत में बिजली की सामान्य खपत के सही सही हिस्से का उल्लेख नहीं किया है। प्राधिकारी ने इस तथ्य पर विचार करते हुए बेंचमार्क दर का निर्धारण किया है कि पी एम बी टी यू द्वारा खपत की गई बिजली की एक तिहाई सामान्य घंटों के दौरान है और शेष दो तिहाई खपत अधिकतम घंटे के दौरान है।
- इस दावे के संबंध में कि एस ई बी द्वारा आपूर्ति की गई बिजली लाभप्रद कीमतों और बिजली की बिक्री की प्रति यूनिट लागत से अधिक है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मलेशिया सरकार द्वारा बिजली के उत्पादन की लागत के संबंध में दी गई सूचना पूर्ण नहीं है और केवल एक साधारण तालिकाबद्ध सूचना उत्पादन की इस प्रकार की लागत की गणना के बारे में बिना किसी विस्तृत पद्धति और साक्ष्य के उपलब्ध कराया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि लागत से संबंधित सूचना मलेशिया की सरकार/ एस ई बी द्वारा प्रकटन विवरण जारी किये जाने के बाद ही उपलब्ध कराया गया है। प्राधिकारी के लिये यह संभव नहीं है कि वे ऐसे विलंबित चरण में लागत से संबंधित सूचना की सत्यता का सत्यापन करें। प्राधिकारी अब भी यह मानते हैं कि पी पी ए के अंतर्गत पी एम बी टी यू से एस ई बी (अथवा इसके पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के द्वारा वसूले जाने वाले प्रशुल्क पर सब्सिडी दी गई है।
- प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आशियान और ईस्ट एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान की (ई आर आई ए) अनुसंधान परियोजना रिपोर्ट 2015 जिसका शीर्षक "मलेशिया में उर्जा सब्सिडी समाप्त करने का आर्थिक प्रभाव" में मलेशिया में बिजली पर सब्सिडी विशेष रूप से बिजली की आपूर्ति में सब्सिडी के होने को नोट किया है। इस रिपोर्ट में यह भी नोट किया गया है कि उर्जा की मांग व्यापक तौर पर स्थायी आर्थिक विकास और जानबूझकर बिजली पर उर्जा सब्सिडी नीति के कारण कम उर्जा कीमतों से प्रभावित होती हैं। रिपोर्ट में आगे यह नोट किया गया है कि यद्यपि बिजली और परिवहन ईंधन सब्सिडी का हिस्सा इस समय कम हो रहा है फिर भी 2010 में मलेशिया में उर्जा सब्सिडी कुल सकल घरेलू उत्पाद का 4.1 प्रतिशत था जिसमें प्रति व्यक्ति सब्सिडी 200 यू एस डॉलर थी (आई ई ए 2015)।
- जहां तक इस दावे का प्रश्न है कि एस ई बी द्वारा अधिकांश उत्पादित बिजली (70 प्रतिशत) हाइड्रो पावर के द्वारा है और इस कारण से बेंचमार्क दर का निर्धारण भारत में हाइड्रो पावर प्रशुल्क के आधार पर किया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जब देश में बेंचमार्क आसानी से उपलब्ध है तब बाहरी/ देश से बाहर के बेंचमार्क को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

- जहां तक इस दावे का प्रश्न है कि एल टी ए आर पर भूमि का प्रावधान एक विशिष्ट सब्सिडी नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसने वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के सब्सिडी खंड में एल टी ए आर पर भूमि के प्रावधान के संबंध में सब्सिडी कार्यक्रम की विस्तार से जांच की है।
- जहां तक इस अनुरोध का प्रश्न है कि पी एम बी टी यू के लिए तय किया गया सब्सिडी मार्जिन को पी एम ए आर में जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि पी एम ए आर को पी एम बी टी यू से 100 प्रतिशत मूल कच्चा माल प्राप्त होता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पी एम ए आर मूल कच्चे माल (एल्यूमिनियम इनगोट) की खरीद पी एम बी टी यू से करता है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, एल्यूमिनियम इनगोट के लिए 75-80 प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति आयातों के द्वारा की जाती है और एल्यूमिनियम इनगोट की केवल शेष 20-25 प्रतिशत आवश्यकता पूरा करने के लिए पी एम बी टी यू से खरीद की गई थी। प्राधिकारी ने उन कीमतों की भी तुलना की है जिन पर पी एम ए आर ने एल्यूमिनियम इनगोट की आयात कीमत के साथ पी एम बी टी यू से एल्यूमिनियम इनगोट की खरीद की और यह नोट किया कि पी एम बी टी यू से खरीद कीमत वास्तव में आयात कीमत से अधिक थी।
- जहां तक इस अनुरोध का प्रश्न है कि अन्य देशों से आयात कीमत मलेशिया से आयात कीमत की तुलना में कम है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अन्य देशों से आयात की मात्रा जांच की अवधि के दौरान (वार्षिकीकृत) मलेशिया से आयातों की तुलना में (भारत में कुल आयातों के 5 प्रतिशत से कम) बहुत अधिक हद तक कम है। इस कारण से, अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाने में सक्षम नहीं हैं।
- जहां तक घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और आयातों के बीच वास्तविक क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये सभी अन्य अनुरोधों का प्रश्न है, प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच के संबंध में इस खण्ड में सभी मुद्दों की जांच की है।
- जहां तक इस दावे का प्रश्न है कि प्रकटन विवरण के लिए उत्तर देने के वास्ते पर्याप्त समय नहीं दिया गया था, प्राधिकारी यह नोट करते हैं इन्होंने प्रकटन विवरण के उत्तर में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त समय दिया है। वास्तव में, सभी हितबद्ध पक्षकारों ने विस्तृत और व्यापक अनुरोध प्रस्तुत किये हैं तथा उस पर वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में विधिवत विचार किया गया है।
- जहां तक इस अनुरोध का प्रश्न है कि घरेलू उद्योग एक ऐसे व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धति में शामिल हैं जहां प्रयोक्ता उद्योग से इसके द्वारा वसूली जाने वाली कीमतें तदर्थ, अपरिवर्तनशील और लंदन मेटल एक्सचेंज द्वारा दर्शायी की कीमतों के समानुपात में नहीं है और यह कि घरेलू उद्योग की कीमतें लंदन मेटल एक्सचेंज पर दर्शायी गई कीमतों से अधिक हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच है जिसमें प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या संबद्ध देश से भारत में आयात पर सब्सिडी की गई है अथवा नहीं और क्या इसके कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है अथवा नहीं।
- जहां तक बेंचमार्क कीमत पर आधारित शुल्क के अनुरोध का प्रश्न है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शुल्क के इस रूप में बारे में निर्णय प्राधिकारी द्वारा किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर लिया जाता है। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले की तथ्यात्मक मैट्रिक के आधार पर वर्तमान मामले में शुल्क के उपयुक्त रूप के बारे में निर्णय लिया है।

अ. भारतीय उद्योग के हित

138. प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने से भारत में इस उत्पाद की कीमत के स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने से कमी नहीं आयेगी। इसके विपरीत, प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों को लगाये जाने से सब्सिडी के द्वारा पाटन प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त किया जायेगा और घरेलू उद्योग की गिरावट रुक जायेगी और संबद्ध वस्तुओं के

उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाये रखने में मदद मिलेगी। प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का उद्देश्य सामान्य तौर पर घरेलू उद्योग को सब्सिडी दिये जाने की अनुचित व्यापार कार्यपद्धतियों के द्वारा हुई क्षति को समाप्त करना है जिससे कि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। इस कारण से प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने से किसी भी तरीके से संबद्ध देश से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

ट. निष्कर्ष

139. दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों जिसे उपर्युक्त जांच परिणामों में रिकार्ड किया गया है, पर विचार करते हुए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि :

- I. वेदांता लिमि. और बाल्को सी वी डी नियमावली के नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग है।
- II. विचाराधीन उत्पाद '9 मिमि. से 13 मिमि. तक के व्यास वाले क्वॉयल रूप में एल्युमिनियम वॉयर/ क्वॉयल रूप में वॉयर रॉड' है।
- III. विचाराधीन उत्पाद का आयात मलेशिया से भारत में सब्सिडी प्राप्त दरों पर किया जाता है।
- IV. मलेशिया सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी के स्तर पर विचार करते हुए, सब्सिडी के मार्जिन न्यूनतम से ऊपर और बहुत अधिक है।
- V. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इन आयातों में पूर्ण रूप में तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है।
- VI. उत्तर देने वाले उत्पादकों/ निर्यातकों की कम कीमत पर बिक्री/ क्षति मार्जिन भी सकारात्मक और बहुत अधिक है।
- VII. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों जैसे उत्पादन, बिक्री, बाजार का हिस्सा, लाभ में क्षति के अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट आई है।
- VIII. घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से सब्सिडी प्राप्त उत्पाद के आयातों के कारण क्षति हुई है।

ठ. सिफारिश

140. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच की शुरुआत की गई थी और इसे मलेशिया सरकार सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों को सब्सिडी दिये जाने, क्षति और कारणात्मक संबद्ध के पहलुओं पर सूचना/ साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। निर्धारित नियमावली के संबंध में सब्सिडी दिये जाने, क्षति और कारणात्मक संबद्ध की जांच शुरू करने और उसे पूरा करने के बाद तथा इस प्रकार के सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति तथा सकारात्मक सब्सिडी सिद्ध किये जाने के बाद, प्राधिकारी का यह मत है कि निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना सब्सिडी दिये जाने और क्षति के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए अपेक्षित है। इस कारण से प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं कि नीचे दिये गये रूप में तथा तरीके से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की जाये।
141. इस नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 19(I) (ख) में निहित प्रावधानों के संबंध में, प्राधिकारी सब्सिडी के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से कमतर के बराबर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त की जा सके। प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किये जाने वाली अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिये संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये शुल्क तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित उत्पादों के सभी आयातों पर नीचे दी गई तालिका के कॉलम 7 में दर्शायी गई राशि के बराबर निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष/ उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	उद्गम देश	निर्यात करने वाला देश	उत्पादक	सी आई एफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में शुल्क राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	76011040, 76012040, 76041010, 76042920, 76051100 और 76052100	9 मिमि. से 13 मिमि. तक के व्यास वाले क्वॉयल रूप में एल्युमिनियम वायर/ क्वॉयल रूप में वायर रॉड	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	प्रेस मेटल बिंटूल एसडीएनझ बीएचडी.	6.8669%
2.	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	प्रेस मेटल एल्युमिनियम रॉड एसडीएन बीएचडी.	6.8669%
3.	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	ऊपर में क्र. सं. 1 और 2 में उल्लिखित उत्पादकों को छोड़कर कोई भी उत्पादक	16.4874%
4.	-वही-	-वही-	मलेशिया को छोड़कर कोई भी देश	मलेशिया	कोई भी	16.4874%

142. केंद्र सरकार के इस आदेश के विरुद्ध अपील जो इन अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना के कारण हो सकती है, सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जायेगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 28th June, 2021

Case No. CVD-04/2020

Subject : Anti-subsidy investigation concerning imports of 'Aluminium Wire/Wire Rods above 7mm dia' originating in or exported from Malaysia.

F. No. 6/23/2020–DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as 'the Rules' or 'CVD Rules') thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Vedanta Limited and Bharat Aluminium Company Limited (hereinafter also referred to as the "Applicants" or "domestic industry" or "DI") jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority"), on behalf of domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as 'the Rules' or 'CVD Rules') for initiation of anti-subsidy investigation concerning imports of "Aluminium Wire/Wire Rods above 7 mm dia" (hereinafter also referred to as "subject goods" or "product under consideration" or "PUC"), originating in or exported from Malaysia (hereinafter also referred to as the "subject country").
2. Based on the duly substantiated application with prima facie evidence filed by the Applicants, the Authority initiated an anti-subsidy investigation vide Notification No. 6/3/2020 – DGTR dated 30th June, 2020, published in the Gazette of India, in accordance with Rule 6 of the Rules to determine existence, degree and effect of alleged subsidy and to recommend amount of anti-subsidy/countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed by the Authority with regard to the investigation:
 - i. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 6 supra.
 - ii. Consultation was held on 29th June 2020 and was attended by the officials of the Government of Malaysia. The Government of Malaysia denied existence/ applicability of certain programs and non-availment of some of the programs by producers/exporters of the product under consideration. Accordingly, program nos. 14, 20 and 22 were taken out from the purview of the investigation.
 - iii. The Authority issued a Notification dated 30 June 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-subsidy investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
 - iv. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 30 days from the receipt of notice in accordance with Rule 7(4) of the Rules.

- v. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, known importers and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 7(3) of the Rules. Also, in view of the global pandemic and physical inaccessibility, request was made to all the interested parties to share the non-confidential version of their submissions with other interested parties via email.
- vi. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from the subject country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
- vii. The Authority also sent questionnaire to the Government of the subject country in order to seek relevant facts/information with regard to various schemes/programs where countervailable benefit have been conferred by the Government. The Government of Malaysia filed a questionnaire response, which has also been taken into account.
- viii. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/ exporters in the subject country, whose details were made available by the applicants, to elicit relevant information in accordance with Rule 7(4) of the Rules:
 - a. M/s. Press Metal Sarawak Sdn. Bhd.
 - b. M/s. Press Metal Bintulu Sdn. Bhd.
- ix. The following producers/exporters from the subject countries filed exporter's questionnaire response:
 - a. M/s. Press Metal Bintulu Sdn. Bhd. ("PMBTU")
 - b. M/s. Press Metal Aluminium Rods Sdn. Bhd. ("PMAR")
- x. Pursuant to the initiation notification, apart from the abovementioned producers/exporters from the subject country, the Government of Malaysia has also filed questionnaire response.
- xi. The Authority forwarded a copy of the Initiation Notification to the following known importers/users/user associations, whose names and addresses were made available to the authority, of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 7(4):
 - a. M/s Polycab India Pvt. Ltd.
 - b. M/s. Prem Cables Private Limited
 - c. M/s. Electrolead (PUNE) Private Limited
 - d. M/s. KEI Industries Limited
 - e. M/s. Dynamic Cables Limited
 - f. M/s. Oswal Cables Private Limited
 - g. M/s. Anvil Cables Private Limited
 - h. M/s. Neccon Power & Infra Limited
 - i. Aluminium Association of India
 - j. All India Non-Ferrous Metal Exim Association
 - k. Indian Electrical & Electronics Manufacturers' Association
- xii. The following importers/users/user associations have filed submissions or questionnaire responses in the present investigation.
 - a. M/s. Lumino Industries Limited
 - b. M/s. Oswal Cables Private Limited
 - c. M/s. Prem Cables Private Limited
 - d. M/s. Dynamic Cables Limited
 - e. Indian Electrical and Electronics Manufacturers Association ("IEEMA")

- xiii. Exporters, foreign producers and other interested parties who have not responded to the Authority, or not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.
- xiv. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xv. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Later on, due to inaccessibility of hard copy of public file in the wake of the COVID-19 global pandemic, all interested parties were asked to share the non-confidential versions of all their submissions with all other interested parties via emails.
- xvi. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present investigation has been considered from April 2019 to December 2019 (9 months). The injury investigation period will, however, cover the periods 2016-17, 2017-18, 2018-19 and the POI. The period of investigation proposed by the applicants was considered appropriate in the present case in view of increase in imports, decline in the import price, and consequent adverse effect on the domestic industry during the period.
- xvii. Verification of the data provided by the domestic industry and producers/exporters was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- xviii. The Non-Injurious Price (NIP) is based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-dumping Rules. It has been worked out so as to ascertain whether countervailing duty lower than the subsidy margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xix. Information obtained from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) on transaction-wise import data for the past three years, and the period of investigation has been adopted for determination of volume and value of imports of product concerned into India.
- xx. In accordance with Rule 7(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing conducted via video conference on 24th May, 2021. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.
- xxi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in these final findings.
- xxii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded these final findings on the basis of the facts available.
- xxiii. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 18th June, 2021 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.
- xxiv. *** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxv. The exchange rate adopted by the Authority during the POI for the subject investigation is 1 US\$= ₹71.24.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. The product under consideration in the present investigation was defined in the notice of initiation as "Aluminium "Wire/Wire Rods above 7 mm dia". The scope of the product under consideration includes both alloyed and non-alloyed wire/wire rods. The major raw material used for manufacturing the product under consideration is alumina. The product under consideration is produced and obtained by casting primary aluminium hot metal obtained from smelting of alumina. Wire/ Wire rods can also be produced by melting of scrap. Wire rod produced through scrap is beyond the scope of the product under consideration.
5. The product under consideration is primarily used in electrical industry, steel industry and others. The product is classified under the Chapter 76 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under customs heading 76011040, 76012040, 76041010, 76042920, 76051100 and 76052100. The Customs classification is only indicative and not binding on the scope of this investigation.

C.1. Submissions made by the Domestic Industry

6. The domestic industry has submitted as follows with regard to product under consideration and like article:
 - i. The product under consideration includes alloyed and non-alloyed Aluminium wire rod in coil form having cross sectional diameter exceeding 7 mm, Aluminium wire having cross sectional diameter exceeding 7 mm, and Aluminium Rod in coil form having cross sectional diameter exceeding 7 mm.
 - ii. The product under consideration excludes Aluminium Wire rod not in coil form, i.e., wire rod in bar/straight form, Aluminium rod not in coil form, i.e., rod in bar/straight form, and Aluminium wire in coil form having cross sectional diameter below 7 mm.
 - iii. There is no difference in the subject goods produced by the petitioning domestic industry and exported from subject country.
 - iv. The product manufactured by domestic industry is like article to the product imported from subject country.

C.2. Submissions made by the other interested parties

7. The following submissions have been made by other interested parties with regard to the product under consideration and like article:
 - i. The PUC in the petition is stated as "Aluminum wire rods" which is classified under Custom Tariff Headings 7604 and 7601. But in the Initiation Notification the PUC is changed to add "Aluminum wire above 7mm dia" under the Customs Tariff heading 7605.
 - ii. The tariff classifications and the definitions under the relevant chapters show they are different products.
 - iii. As per information on the website of the Applicants, the Domestic Industry only produces Aluminum wire from 9 mm to 12.5 mm dia. Hence, the wire of less than 9 mm and more than 12.5 mm should be excluded from the scope of PUC. The import volumes of PUC into India should also include Aluminum wire of dia 9 mm to 12.5 mm only. Para 3.10 of the Manual of Operating Practices supports the same. This was also consistently observed in several ADD investigations.
 - iv. Wire rods produced through scrap was intended to be kept beyond the scope of PUC.
 - v. Aluminium wire and Aluminium wire rods are two different product types in the sense that bars and rods are not in coils while wires are in coils, as can be seen from customs tariff classifications.
 - vi. Aluminium wire and wire rods differ in production process, form, flexibility, end-uses, diameter and length, and thus not technically and commercially interchangeable.
 - vii. Aluminium wires are suitable for manufacturing cables and conductors while wire rods are not.
 - viii. Scope of product under consideration should exclude Aluminium wire with a diameter less than 7.6 mm as the petitioner has excluded them in import data analysis.
 - ix. Products not manufactured by domestic industry should be excluded from product under consideration and practice followed in anti-dumping investigations is equally applicable to

countervailing duty investigations as well. Reference has been made to Oxo Alcohols Industries Association v. Designated Authority where Hon'ble CESTAT held that products not manufactured by DI cannot be PUC as no injury can be caused.

- x. In case of inclusion of wire rods, the PUC must be separated into two different categories and revised data should be called for.

C.3. Examination by the Authority

8. The Authority has noted submissions made by various interested parties with regard to scope of the product under consideration and like article offered by the domestic industry. The very first step in an investigation is to identify the product under consideration. The product under consideration is the imported product which is allegedly causing injury to the domestic industry. On the basis of submissions made by various interested parties and the examination of import statistics, the Authority notes that the subject goods have been imported in coil form only from subject country. Accordingly, the Authority holds that the product under consideration in the present investigation is "Aluminium Wire in coil form/Wire Rod in coil form having diameter ranging from 9 mm to 13 mm". The product under consideration includes both alloyed and non-alloyed aluminium wire. The major raw material used for manufacturing the product under consideration is alumina. The product under consideration is produced and obtained by casting primary aluminium hot metal obtained from smelting of alumina. Aluminium wire can also be produced by melting of scrap. Aluminium wire produced through scrap is beyond the scope of the product under consideration.
9. The product is classified under the Chapter 76 of the Customs Tariff Act, 1975 under customs tariff heading 76011040, 76012040, 76041010, 76042920, 76051100 and 76052100. The customs classification is indicative only and in no way binding upon the product scope. Aluminium Wire produced by the domestic industry is a like article to the Aluminium Wire imported from the subject country. The Authority holds that there is no difference in the subject goods produced by the domestic industry and that exported from the subject country. Subject goods produced by the domestic industry and imported from subject country are comparable, collectively and cumulatively, in terms of product characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The Authority holds that product under consideration produced by the applicant domestic industry is like article to the subject product under consideration imported from subject country in accordance with the Anti-Subsidy Rules.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1. Submissions made by the Domestic Industry

10. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing and scope of the domestic industry:
 - i. The Applicants account for "a major proportion" of Indian production of PUC and satisfy the requirement of standing and constitute "Domestic Industry" within the meaning of the Rules.
 - ii. Sterlite Power Transmission Limited ("SPTL") has not imported the product under consideration during the period of investigation from the subject country or any other country.
 - iii. The Applicants are not related to the exporters of the alleged subsidized article, or like article from other countries or are themselves importers.

D.2. Submissions made by other interested parties

11. The following submissions have been made by other interested parties with regard to the standing and scope of the domestic industry:
 - i. The Authority is requested to examine if Vedanta Ltd. and BALCO are domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the CVD Rules.
 - ii. If the PUC is "Aluminium wire above 7mm dia" then the standing of Vedanta Ltd. And BALCO as "domestic industry" should be assessed afresh.
 - iii. A vague estimate of the production of other domestic producers is unreliable. The Authority should request information from other two big producers and examine if the DI's share is more than 50% (after excluding SEZ unit of Vedanta from the total production).

- iv. The Authority is requested to examine the reasons due to which Hindalco and NALCO, who are major producers of the PUC have not supported the petition.
- v. In the Appellate Body report in *US-Lamb*, the need for ‘representativeness’ of domestic industry considering requirement of ‘major proportion’ under Safeguards Agreement was explained. Domestic industry under Article 4(c) of Safeguard Agreement is *pari materia* with domestic industry under Article 16.1 of the ASCM. Hence, the need to ensure representativeness is applicable in CVD investigations as well.
- vi. Non-participation by major producers in India led to the termination of ADD investigation on seamless tubes, pipes and hollow profiles of iron, alloy or non-alloy steel.
- vii. Vedanta Limited is related to an importer, namely, SPTL. The petition is silent about imports by Vedanta from other countries, imports by SPTL from Malaysia or any other country during the injury period.
- viii. The petition does not clarify whether the Domestic Industry or SPTL (related importer of Vedanta) imported the PUC from any other country during the injury investigation period including the POI. In case there are imports, such domestic producer should be excluded from the scope of the domestic industry. Complete information regarding the same should be provided.
- ix. The petition does not disclose the total production or the exact share of the petitioners, and neither has range been provided.
- x. Imports of product under consideration from Malaysia by SPTL could also have resulted in shielding the domestic industry from any ill-effects of the alleged subsidies by benefitting from the purchase, use and sale of the allegedly subsidized goods.

D.3. Examination by the Authority

12. The application has been filed by Vedanta Limited and Bharat Aluminium Company Limited (hereinafter also referred to as “BALCO”).
13. As per the evidence available on record, production of the Applicants account for ***% of the total domestic production. Further, as per the available information, it is noted that:
 - a. The Applicants have not imported the subject goods from subject country or any other country
 - b. The Applicants are not related to any producer/exporter of subject goods in subject country or any other country
 - c. The Applicants are not related to any importer in India who has imported the subject goods from any country
 - d. SPTL, which is related to Vedanta Limited, has not imported the subject goods from any country in the POI.
14. Considering the information on record, the Authority holds that the production of the Applicants account for a major proportion of the domestic production of the like article and the applicants are eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules. The application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 6(3) of the Rules.
15. With regard to the claim that two major producers of the subject product, Hindalco Industries Ltd. and National Aluminium Co. Ltd., have not participated in the investigation and have not provided any information, the Authority notes that there is no requirement for all domestic producers to participate as constituents of domestic industry in an anti-subsidy investigation. In accordance with Rule 2(b) of the Rules, the domestic producers constituting major proportion in the total domestic production can be considered as domestic industry. In the present case, production of the Applicants account for ***% of the total domestic production and accordingly they satisfy the requirement of major proportion under Rule 2(b) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions made by the domestic industry

16. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality:

- i. Questionnaire responses filed by the users are in gross violation of the trade notice as information has been claimed confidential without even providing a reasonable summary or disclosing reasons for withholding information available in the public domain.
- ii. The domestic industry was not informed about the supplementary information requested by the Authority. The responding producers/exporters should not be allowed to submit a deficient questionnaire response and then subsequently fill up the deficiencies confidentially, since it would be prejudicial to the interests of the Domestic Industry.
- iii. All supplementary information filed by the exporters should be rejected, if the exporters prefer to not file NCV of the same.
- iv. Press Metal Bintulu Sdn Bhd (PMBTU) has claimed confidentiality regarding channel of distribution, volume and value of raw materials purchased from domestic sources and program 23. Press Metal Aluminium Rods Sdn Bhd (PMAR) has claimed confidentiality regarding history of company ownership and channel of distribution. Format C and production process of PMAR's response violates Trade Notice 10/2018.

E.2. Submissions made by other interested parties

17. Following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality-

- i. Domestic industry has disregarded trade notices and failed to show any good cause for such excessive confidentiality. The computation of NIP and the final NIP has been claimed confidential deliberately as the import price is higher than NIP. Hence, DI must produce revised petition with necessary information.

E.3. Examination by the Authority

18. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of the CVD Rules provides as follows:

A.1.1.1 *“Confidential information-*

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), (2), (3) and (7) of rule 7, sub-rule (2) of rule 14, sub-rule (4) of rule 17 and sub-rule (3) of rule 19 copies of applications received under sub-rule (1) of rule 6 or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof in sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the confidential information and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority, is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.”

19. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to ongoing global pandemic.
20. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. The Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was duly examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been

considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions made by the domestic industry

21. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- i. Questionnaire response filed by the Government of Malaysia (GOM) is incomplete and inadequate and calls into question the level of cooperation that can be expected from GOM. GOM should be directed to submit replies to the entire questionnaire, and if not, the response should be rejected.
- ii. The GOM has only responded to Program No. 5 (Pioneer Status), Program No. 8 (Accelerated Capital Allowance), Program No. 11 (Industrial Building Allowance), Program No. 12 (Allowance for Plants and Machinery), and Program No. 23 (Less Than Adequate Remuneration for Land & Electricity).
- iii. GOM has not replied to the standard questionnaire response and the relevant annexures for the exemption on sales tax, despite two determinations by the Authority in the past establishing such exemption where the producer benefits twice – exemption on raw material purchased and exemption on sales made, and is also relevant in the present case as the exporting producers have benefitted from the program.
- iv. The obligation lies on the GOM to disclose any programs in force even if they consider the program to be non-countervailable and to respond fully to the questionnaire.
- v. GOM has restricted its response only to the responding producers/exporters and not country wide producers/exporters of the subject goods.
- vi. The Authority should ensure that the information regarding acquisition of capital assets provided by the GOM and exporters is for the entire useful life (AUL) period and whether any such benefits are flowing into the period of investigation. An AUL of 15 years for plant and machinery may be considered as per Schedule II (section 123) of the Companies Act, 2013.
- vii. Information for AUL period should be called for Program Nos. 8: Accelerated Capital Allowance, Program No. 11: Allowance Industrial Building/ Industrial Building Allowance (IBA), Program No. 12: Allowance for Plants and Machinery, Program No. 17: Exemption from Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment and Program No. 18: Exemption from Import Duty on Raw Materials/Components, and any failure to provide such data should be considered non-cooperative.
- viii. The questionnaire responses filed by producers/exporters are insufficient.
- ix. A substantial amount of benefit is received at the stage of smelting. PMAR does not have an integrated plant for smelting and thus either purchases inputs from PMBTU or Press Metal Sarawak Sdn. Bhd (PMS). Any benefit received by PMS should also be included in the product. PMS is non-cooperative in the present investigation and therefore, the response of PMAR should also be rejected.
- x. Duty exemption on all machinery and other components imported by PMBTU during the AUL period should be quantified and any subsidy received during POI should be quantified.
- xi. PMAR has disclosed that they were approved for benefit under Program 17 (Exemption on import duty and sales tax on machinery and equipment) in 2014 and availed it on 2015, thereby extending it to the POI. The Authority should ascertain why such benefit has only been disclosed by one group company. As PMS would also have received the benefit but did not co-operate, facts available should be applied for quantification.
- xii. Neither PMBTU nor PMAR has provided information on any programs other than those enlisted by the Applicants in the Application, despite having the obligation to do so, thereby showing their lack of willingness to cooperate fully with the Authority. The interested parties have resorted to hiding facts.

- xiii. The GOM has not provided information regarding annexures to the questionnaire response, functioning and objectives of government institutions providing financial contribution to companies.
- xiv. No reason for availing program 1, 3, 4, 10, 15-18 has been provided by PMBTU and PMAR. No reply has been provided to standard questions annexures for programs 1-4, 6-7, 9-10 and 13-22. No allocation annexures have been provided for program 5 and information for AUL period has not been provided for programs 8, 11 and 12.
- xv. Raw material consumed is not available in the exhibit. No reason for availing programs 1-7, 10 and 15 has been provided. No reply has been provided for programs 8, 11 and 12 and to standard questions annexures for programs 1-7, 9-10, 13-16, and 19-23. Information for AUL period has not been provided for programs 8, 11, 12 and 17.

F.2. Submissions by other interested parties

22. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:
- a. Authority has not requested information regarding the AUL period for any of the programs.
 - b. Information for AUL period is required only for the programs for which one time benefit is received and such benefit is required to be allocated over the AUL period. Information is provided in the questionnaire response of PMBTU and PMAR regarding the AUL period, wherever applicable.
 - c. Domestic industry has assumed that information is not provided regarding the programs for AUL period when PMAR and PMBTU has not admitted that they have received benefit. Domestic industry has not indicated what evidence can be provided to support claim regarding non-use of subsidy programs. It is not possible to provide evidence regarding non-use of subsidy programs in all cases.
 - d. PMS is not engaged in manufacturing or exporting PUC. PMBTU and PMAR do not procure any raw material from PMS for manufacturing PUC.
 - e. PMAR and PMBTU has provided information regarding import duty exemption, if any, on all machinery and components imported by PMBTU and PMAR during the AUL period.
 - f. GOM has provided complete information in response to the questionnaire. Absence of information in the questionnaire response of GOM is not relevant as PMAR and PMBTU have provided full information regarding the legal basis and also the amount of benefit received under the programs, if any.

F.3. Examination by the Authority

23. The Authority has noted all the arguments and counterarguments of the interested parties and has examined all aspects of the submissions made.
- a. As regards the claim concerning specific subsidy programs, the Authority has noted its examination while examining each subsidy program.
 - b. As regards the claim concerning inadequate information for all alleged subsidy programs by Government of Malaysia, Authority notes that Government of Malaysia provided information in the questionnaire response regarding the legal basis of the programs used by the participating producers/exporters from Malaysia and the same has been taken into consideration while examining each subsidy program. Authority has relied on the information provided by the domestic industry regarding the legal basis of programs for which no information was provided by Government of Malaysia.
 - c. As regards claim concerning information for AUL period, the Authority has information from the responding producers/exporters for AUL period for the relevant programs. Authority notes that information for AUL period is not required for Program Nos. 8: Accelerated Capital Allowance, Program No. 11: Allowance Industrial Building/ Industrial Building Allowance (IBA), Program No. 12: Allowance for Plants and Machinery and Program No. 18: Exemption from Import Duty on Raw Materials/Components because the programs are recurring in nature.
 - d. As regards claim concerning absence of information from producers/exporters about other subsidy programs not alleged in the Petition, Authority notes that it has examined additional subsidy

programs alleged by the domestic industry based on the information provided by the domestic industry in its written submission, even though such information was provided by the domestic industry belatedly and was not supported by relevant legal and factual details. Authority has also taken into consideration information provided by other interested parties, the provisions of the WTO SCM Agreement, the Act and the Rules while examining these subsidy programs in these final findings.

- e. As regards the claim concerning non-participation of related party (PMS) of participating producers/exporters, Authority notes that PMS is not engaged in manufacturing of PUC. Also, it is noted that PMBTU and PMAR do not procure any raw material from PMS for manufacturing PUC. Therefore, there is no requirement for PMS to file exporters questionnaire response in the present investigation.

F. EXAMINATION OF SUBSIDY PROGRAMS

F.1. Program No. 1 – The Market Development Grant

24. Submissions by the domestic industry

- a. The Petitioners submitted that the scheme is administered by Ministry of Finance, Malaysia, Ministry of International Trade and Industry, and Malaysia External Trade Development Corporation. The scheme offers grants to Malaysian SMEs for participating in export promotional activities, such as international trade fairs. The maximum grant for an SME under the MDG program is RM 200,000. The scheme identifies three types of eligible entities: (1) The SME should have been incorporated under the Companies Act, 2016 with at least 60% Malaysian equity ownership and exporting products made in Malaysia; (2) Professional service providers incorporated under the Registration of Business Act (1956) or registered under respective statutory bodies for professional service providers, should have at least 60% Malaysian equity ownership and exporting Malaysian services; and (3) Trade and industry Associations should be registered with the Registrar of Society or Associated Professional Authority.
- b. The evidence and the legal basis are Guidelines for Market Development Grants -2020 as well as the determination by the Authority in anti-subsidy investigation concerning imports of Continuous Cast Copper Wire Rods.

25. Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

- a. Neither PMAR, nor PMBTU availed, used, or benefitted from Program No. 1 during the POI.
- b. Petitioners have not given any evidence of benefit conferred on PMAR or PMBTU during POI.

26. Examination by the Authority

- a. The Authority notes that Market Development Grant (MDG) is intended to increase participation of SMEs in export promotional activities. The MDG provides SMEs a reimbursable grant up to RM 2,00,000 for their participation in export promotional activities such as International Trade Fairs, Trade & Investment Missions /Export Acceleration Missions, International Conferences Overseas and Listing Fees for Made-Malaysia Products in supermarkets, hypermarkets or retails centers overseas.
- b. The subsidy program provides for financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred to the recipient. The subsidy program is also specific because it is contingent on exports.
- c. PMAR and PMBTU, the two participating producers/exporters from subject country did not benefit from this program. Thus, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program for PMAR and PMBTU. However, Authority notes that the benefit under this subsidy program can be availed by other producers/exporters of subject product in Malaysia. Therefore, Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program for all other producers/exporters from Malaysia.

F.2. Program No. 2 – Business/Industry Excellence Award

27. Submissions by the domestic industry

- a. The Petitioners submitted that the award is administered by the Ministry of International Trade and Industry (MITI) to recognize outstanding Malaysian companies and to encourage continuous

improvement in products and services rendered. The company should be incorporated in Malaysia under the Companies Act, 1956; be in operation for at least 3 years continuously; and submit audited financial statements for past 3 consecutive financial years.

- b. The award includes cash prizes, training programs, consideration of financing, and access to design activities, among other benefits, depending upon the categorization of manufacturing and service sector.

28. Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

- a. PMAR and PMBTU, the two participating producers/exporters from subject country did not avail, use, or benefit from the Industry Excellence Award during the POI.
- b. Petitioners have not given any evidence of benefit conferred on PMAR or PMBTU during POI.

29. Examination by the Authority

- a. The Authority notes that Business/Industry Excellence Award is granted to Malaysian companies by MITI to recognize their improvement in the quality of products/services offered. The award is in the form of cash prizes, training programs, access to design activities etc.
- b. The subsidy program provides for financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred to the recipient. The subsidy program is also specific because it is limited to certain enterprises that fulfill the eligibility criteria.
- c. PMAR and PMBTU, the two participating producers/exporters from subject country did not benefit from this program. Thus, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program for PMAR and PMBTU. However, Authority notes that the benefit under this subsidy program can be availed by other producers/exporters of subject product in Malaysia. Therefore, Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program for all other producers/exporters from Malaysia.

F.3. Program No. 3 – Export Credit Refinancing

30. Submissions by the domestic industry

- a. Petitioners submitted that the ECR scheme is administered by the Malaysia Industrial Development Authority, Central Bank of Malaysia and Export-Import Bank of Malaysia Berhad, and provides short-term pre- and post-shipment financing to direct or indirect exporters. Malaysian enterprises engaged in manufacturing and/or trading and exporting goods can avail export credit, and the exporters can obtain financing up to 95% of the value of their export order.

31. Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

- a. Neither PMAR nor PMBTU availed, used, or benefitted from this program.
- b. Petitioners have not given any evidence of benefit conferred on PMAR or PMBTU during POI.

32. Examination by the Authority

- a. The Authority notes that the program is administered by Export-Import Bank of Malaysia (EXIM Bank). Export credit refinancing program provides loan to enterprise to finance export of products. The program is governed by Export Credit Refinancing guideline issued by the Bank, which provides for eligibility criteria including eligibility of product (negative list of products which is maintained by bank) for the purpose of the program. The subsidy program is not restricted to any particular sector and is available to all companies incorporated in Malaysia.
- b. EXIM Bank is a government-owned development financial institution. It is a wholly owned subsidiary of the Minister of Finance Incorporated (Inc.). As an agency under the purview of the Ministry of Finance, EXIM Bank's mandated role is specified by the Government. It is to provide credit facilities to finance and support exports and imports of goods, services and overseas projects with emphasis on non-traditional markets providing export credit insurance services, export-financing insurance, overseas investments insurance and guarantee facilities.
- c. The Authority determines that EXIM Bank is a public body because it is owned by Government and is vested with the Government Authority to carry out governmental functions. Accordingly, the loan

provided by EXIM Banks are financial contribution in the form of direct transfer of funds by a public body. The benefit conferred on the recipient is in the form of difference between the amount of interest charged by the EXIM bank and the amount of interest charged on a comparable commercial loan. The program is also specific because it is contingent on export.

- d. PMAR and PMBTU, the two participating producers/exporters from subject country did not benefit from this program. Thus, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program for PMAR and PMBTU. However, Authority notes that the benefit under this subsidy program can be availed by other producers/exporters of subject product in Malaysia. Therefore, Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program for all other producers/exporters from Malaysia.

F.4. Program No. 4 – Buyer Credit Guarantee

33. Submissions by the domestic industry

- a. The Petitioners submitted that under this program the overseas buyers are backed by EXIM Bank's unconditional and irrevocable guarantee in which lending bank is guaranteed repayment of due and interest amount. Malaysian exporter can help the overseas buyer to have a cash contract, whilst the overseas buyer has time to pay the contract through financing secured from the lender which is backed by EXIM Bank's guarantee. The evidence given is Buyer Credit Insurance by EXIM Bank. The loan amount under this program must be minimum value of RM 2 million in support of a cash contract and the repayment period should be at least 2 years and maximum 15 years.

34. Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

- a. Neither PMAR nor PMBTU availed, used, or benefitted from this program.
- b. Petitioners have not given any evidence of benefit conferred on PMAR or PMBTU during POI.

35. Examination by the Authority

- a. The Authority notes that the program is administered by EXIM Bank. There is no law or legal regulation governing the program.
- b. The Authority has already determined that EXIM Bank is a public body. Under this program, EXIM Bank provides guarantee to financial institutions against risk of non-payment by their exporters (customers) because of default arising from overseas buyers. The program provides for financial contribution in the form of potential direct transfer of funds and benefit is thereby conferred. The benefit conferred on the recipient is equivalent to (i) the difference between the fee paid by the recipient for availing guarantee from EXIM Bank and the fee that would have been paid to any other commercial bank for such guarantee and (ii) the difference between the loan repayment to the lending bank in question (owing to less than normal commercial interest rate because of EXIM bank guarantee) and the amount that would have been payable in absence of such guarantee (based on normal commercial interest rate). The subsidy program is also specific because it is contingent on export.
- c. PMAR and PMBTU, the two participating producers/exporters from subject country did not benefit from this program. Thus, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program for PMAR and PMBTU. However, Authority notes that the benefit under this subsidy program can be availed by other producers/exporters of subject product in Malaysia. Therefore, Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program for all other producers/exporters from Malaysia.

F.5. Program No. 5 – Pioneer Status

36. Submissions by the domestic industry

- a. The Petitioners submitted that a company granted Pioneer Status will enjoy tax exemption from corporate income tax. The program encourages investments in promoted activities/products which are of national and strategic importance to Malaysia. It applies to both local and foreign investors for approved promoted products/activities in the manufacturing sector. Five-year partial exemption is provided from payment of income tax. A company pays tax on 30% of its statutory income, with exemption period commencing from its production day. Unabsorbed capital allowances and

accumulated losses incurred during the pioneer period can be carried forward and deducted from post-pioneer income of company. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on:

- i. Promotion of Investment Act 1986
- ii. Promotion of Investments (Promoted Activities and Promoted Products) Order 2012
- iii. Anti-subsidy investigation concerning imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods”.
- iv. New and full notification pursuant to Article XVI:1 of the GATT 1994 and Article 25 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures – Malaysia dated 5th October 2017 [WT/TPR/S/292]
- v. <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
- vi. <https://www.treasury.gov.my/index.php/en/tax/item/1160-promotion-of-investment-act-1986.html>
- vii. US Extruded Rubber through Malaysia and US-Certain Frozen Warmwater Shrimp
- viii. Annual Report, Press Metal, Pioneer Status, Page 164

37. Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

- a. Pioneer Status may be granted to any company intending to participate in a promoted activity or to produce a promoted product which are determined by Minister of Finance and Minister of International Trade and Industry. The promoted products and activities cover all sectors including manufacturing, agricultural and services. The major tax incentives for companies investing in the agricultural and manufacturing sectors are the Pioneer Status and Investment Tax Allowance. Companies can enjoy either one of the incentives as these incentives are mutually exclusive.
- b. Article 11.2 of the SCM Agreement requires sufficient evidence on existence of a subsidy. Petitioners have not fulfilled the requirements of Article 11.2 and other relevant provisions of the SCM Agreement. The evidence provided by Petitioners is also irrelevant to the Pioneer Status program.
- c. The assistance under the Pioneer Status program is in the form of exemption from taxes owed. If a company is in a tax loss situation, the losses can be carried forward.
- d. Pioneer Status program is not specific to any enterprise or group of enterprises, or to any industry or group of industry because the eligible promoted products or activities are too wide, diverse, broad and widespread to be considered specific. Pioneer Status program is also not limited to any geographical area within Malaysia.
- e. Industries should produce sufficiently similar products in order to be considered as a group of industries (US-Softwood Lumber IV). The number of categories, industries, sectors, products or activities eligible for Pioneer Status program are too diverse to be considered a “group of industries”. Industries should be definite and specific to certain industries to be considered as limited number of persons engaged in production.
- f. If subsidy is broadly available and widely used throughout the economy, then it is not specific (US-Upland Cotton).
- g. PMAR did not avail, use or benefit from this program. PMBTU was awarded pioneer status in 2013, which entitled PMBTU to a tax exemption for a period of 5 years from 1 January 2013 to 31 December 2017. An additional 5 years exemption was granted upon expiry of the first 5 years. In December 2017, PMBTU had applied for the 5-year extension till 31 December 2022.
- h. Pioneer Status program offers income tax exemption between 70% to 100% of statutory income for a tax relief period between 5 to 15 years.
- i. Rule 11 of CVD Rules requires the Authority to examine if subsidy has been conferred on a limited number of persons, engaged in manufacturing, producing or exporting the article. Annexure II, Paragraph (1)(a) & (b) of the CVD Rules provides that subsidy is considered as being conferred on a limited number of persons engaged in the manufacture or production of an article when granting authority either explicitly limits or in fact limits access to a subsidy to certain enterprises.

- j. Pioneer Status company can be fully for domestic, fully for export or a combination of both. It can be located within any state in Malaysia, operating in either the primary, manufacturing or services sector spread out across multiple industries. In fact, within the manufacturing sector, Pioneer Status is available to 11 out of 13 manufacturing industries listed under the Ministry of International Trade and Industry's website.

38. Examination by the Authority

- a. The Authority notes that Sections 5 to 25 of the Promotion of Investment Act 1986 provide for Pioneer Status program. The program provides for tax incentives in the form of exemption from income tax. Losses incurred during the exemption period can be carried forward for subsequent years to offset taxable income/net profit. The program is available for pre-specified list of promoted products/activities.
- b. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due, and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is available to promoted activity/product mentioned in the eligibility list. Questionnaire response filed by PMBTU shows that benefit has been received by them under this program (100% of income tax exemption) during the POI. Therefore, Authority holds that countervailing duty should be imposed against this subsidy program for PMBTU. PMAR has not availed, used or benefitted from this program during the POI. Thus, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program for PMAR. Authority also holds that countervailing duty should be imposed against this program for all other producers/exporters from Malaysia except PMAR.

F.6. Program No. 6 – Investment Tax Policies/Allowances

39. Submissions by the domestic industry

- a. The Petitioners submitted that a company granted Investment Tax Allowance (ITA) is entitled to offset this allowance against the statutory income for each year of assessment. The program encourages investments in promoted activities/products in the manufacturing sector, that can contribute to development and growth of economy. It applies to both local and foreign investors for approved promoted products/activities in the manufacturing sector. An allowance of 60% on its qualifying capital expenditure incurred within 5 years from the date the first qualifying capital expenditure incurred is given. Company can offset this allowance against 70% of its statutory income for each year of assessment. Remaining 30% of its statutory income will be taxed at the prevailing company tax rate. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on:
- i. Promotion of Investment Act, 1986
 - ii. New and full notification pursuant to article xvi:1 of the GATT 1994 and Article 25 of the Agreement on Subsidies and Countervailing measures Malaysia dt. 5 October 2017
 - iii. <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
 - iv. List of promoted activities and products which are eligible for consideration of pioneer status and investment tax allowance under the Promotion of Investment act, 1986

40. Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

- a. Neither PMAR, nor PMBTU availed, used, or benefitted from this program.
- b. Petitioners have not given any evidence of benefit conferred on PMAR or PMBTU during POI.

41. Examination by the Authority

- a. Authority notes that Sections 26 to 29 of the Promotion of Investments Act 1986 provide for Investment Tax Allowance program. Promoted activities and promoted products are granted capital allowance. Value addition and technological requirements are also to be fulfilled. Out of the total capital expenditure, 60% of the capital expenditure is granted as allowance and can be deducted against 70% of statutory income for 5 years. Remaining income can be taxed at normal income tax rate. Even for companies that meet the listed criteria of promoted activity, value addition and level of technology, Malaysian government retains discretion to reject the applicant seeking benefit under this program.

- b. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The program is also specific since it is limited to certain enterprises, which meet the criteria of promoted product/activity and are approved by the Authority. A company that has received income tax exemption from Pioneer Status cannot avail benefit under this program. PMAR and PMBTU, the two participating producers/exporters from subject country did not benefit from this program. Thus, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program for PMAR and PMBTU. The Authority also notes that it has already countervail the Pioneer Status program for all other producers/exporters from Malaysia. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed against this subsidy program for all other producers/exporters from Malaysia.

F.7. Program 7: Reinvestment Allowance

42. Submissions made by the domestic industry

- a. The Petitioners submitted that under this program, Reinvestment Allowance (RA) is given to existing companies in manufacturing activities that reinvest for the purposes of expansion, automation, modernization or diversification of its existing business into any related products within the same industry on condition that such companies have been in operation for at least 36 months effective from the Year of Assessment 2009.
- b. A company or a person resident in Malaysia is granted RA if the business has been in operation for not less than thirty-six months; or the company or person has incurred in the basis period for a year of assessment, capital expenditure on a factory, plant or machinery used in Malaysia for the purposes of a qualifying project. RA is given at the rate of 60% on the qualifying capital expenditure incurred by the company and can be offset against 70% of its statutory income for the year of assessment. Any unutilized allowance can be carried forward to subsequent years until fully utilized. A company can offset RA against 100% its statutory income for the year of assessment if the company attains a productivity level exceeding the level determined by Ministry of Finance. The RA will be given for a period of 15 consecutive years beginning from the year the first reinvestment is made.
- c. As evidence of existence of program, the Petitioners have relied on:
- i. Promotion of Investment Act, 1986
 - ii. Income Tax Act 1967
 - iii. Anti-subsidy investigation concerning imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods”
 - iv. <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
 - v. Annual Report, Investment Tax Allowance, Page 163

43. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

- a. Neither PMAR, nor PMBTU availed, used or benefitted from this program.
- b. Petitioners have not given any evidence of benefit conferred on PMAR or PMBTU during POI.

44. Examination by the Authority

- a. Authority notes that a company or a person resident in Malaysia is granted Reinvestment Allowance if the company is in operation for 3 years and has incurred capital expenditure on factory, plant and machinery for qualifying project. Deduction is granted from 70% of statutory income for 60% of such capital expenditure. Re-investment allowance can be claimed for 15 years beginning from the year of assessment in which a claim is made. Inland Revenue Board is responsible for administration of this program.
- b. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due, and benefit is thereby conferred. Even though the subsidy program is not limited to promoted activity, the subsidy program is also specific because it is available to enterprise that has been in operation for at-least 3 years and are undertaking qualifying project (expanding, modernizing or automating its existing business in respect of manufacturing). The Authority has recommended in program nos. 5 & 8 that income tax exemption and deduction from statutory income by way of allowance is countervailable. Therefore, the Authority holds that no additional countervailing duty is required to be imposed against this subsidy program.

F.8.Program 8: Accelerated Capital Allowance**45. Submissions by the domestic industry**

- a. Accelerated Capital Allowance (ACA) provides allowances to write off the capital expenditure within two years, i.e., an initial allowance of 20 percent in the first year and an annual allowance of 40 percent. After the 15-year period of eligibility for Reinvestment Allowance, companies that reinvest in the manufacture of promoted products are eligible to apply for ACA. Applications have to be submitted to the IRB accompanied by a letter from MIDA certifying that the companies are manufacturing promoted activities or products.
- b. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on:
 - i. Promotion of Investment Act, 1986
 - ii. Public Ruling No. 4/2013
 - iii. Anti-subsidy investigation concerning Continuous Cast Copper Wire Rods
 - iv. <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts>

46. Submissions by Government of Malaysia/ other interested parties

- a. ACA provides allowances to write-off the capital expenditure within four years, i.e. an initial allowance of 20 percent in the first year and an annual allowance of 20 percent thereafter. All companies that meet the eligibility criteria can claim the ACA. This program is available to all companies and the Inland Revenue Board applies objective criteria in granting ACA. Thus, this program does not constitute a countervailable subsidy because it is not linked to export conditions, not specific and it is generally available. Further, the amount of ACA is part of the Capital Allowance claimed by any company.
- b. The allowance can be carried forward. Generally, to be eligible for ACA, a person must meet the following conditions:
 - They were carrying on a business during the basis period
 - They have incurred qualifying expenditure in the basis period
 - The asset was used for purposes of a business, and
 - At the end of the basis period, he was the owner of the asset and the asset was in use
- c. The claiming of capital allowances, including ACA is mandatory under relevant tax law.
- d. The program covers capital expenditure incurred by a Malaysian resident in the basis period for a year of assessment from a source consisting of his business in relation to (i) the purchase of any information and communication technology equipment as listed in the Schedule of PU(A)156/2018, and (ii) the development cost for customized computer software as defined in PU(A)274/2019, used for the purpose of that business.
- e. The deductions permitted are not more than the actual expense. The timing of claiming is accelerated when compared to the normal timing of capital allowances. This is a form of tax depreciation.

47. Examination by the Authority

- a. Authority notes that the program provides for capital allowance i.e. deduction of capital expenditure from statutory income to promoted activity after the expiry of 15 years of re-investment allowance period. Authority notes that program provides for writing-off the capital expenditure within five years, i.e. an initial allowance of 20 percent in the first year and an annual allowance of 20 percent thereafter.
- b. Authority notes that the program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is available to certain enterprise incurring expenditure towards specified capital expenditure. Benefit under this program is equivalent to the amount of interest accrued on the tax saved by deducting expenditure at an accelerated rate. PMAR and PMBTU have availed, used and benefitted from this program during POI. Therefore, Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

F.9. Program 9: Group Relief**48. Submissions by the domestic industry**

- a. Group Relief is available to all locally incorporated resident companies subject to the terms and conditions as provided under Section 44A of Income Tax Act 1967. The provision of Group Relief allows a company in group to surrender (referred to as surrendering company) a maximum of 70% of its adjusted loss in the basis period for a year of assessment to one or more related companies (referred to as claimant company) within the same group. Effective from the year of assessment 2009, Group Relief was increased from 50% to 70% of the current year's unabsorbed losses to be offset against the income of another company within the same group.
- b. The claimant and the surrendering companies each have a paid-up capital of ordinary shares exceeding RM 2.5 million. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on:
 - Section 44A, Income Tax Act 1967
 - Promotion of Investment Act, 1986
 - Anti-subsidy investigation concerning imports of "Continuous Cast Copper Wire Rods"

49. Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

- a. During the POI, none of the companies under investigation applied for, accrued or received benefit under the Group Relief program.
- b. Petitioners have not given any evidence of benefit conferred on PMAR or PMBTU during POI.

50. Examination by the Authority

- a. Authority notes that the program is governed by Section 44A of the Income Tax Act. The subsidy program allows to set off not more than 70% of its loss incurred by a company in a group against profit of one or more related companies within the same group. All companies that meet the eligibility criteria can claim the Group Relief.
- b. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due, and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is limited to enterprise having related companies. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against subsidy program granting exemption up to 100% from income tax under Pioneer Status Program. The Authority therefore holds that no additional countervailing duty to be imposed for this subsidy program.

F.10. Program 10: Tariff Related Incentives**51. Submissions by the domestic industry**

- a. The program provides for full exemption from import duty on raw materials/components, regardless of whether the finished products are meant for the export or domestic market. To qualify for the exemption, the raw materials/components are not locally available and used directly in the production of the finished product at the approved manufacturer's premise(s).
- b. Where the finished products are for the export market, full exemption from import duty on raw materials/components is normally granted, provided the raw materials/components are not produced locally, or where they are produced locally, are not of acceptable quality and price.
- c. As evidence of evidence of the existence of program, Petitioners have relied on:
 - Section 14(2) of Customs Act 1967
 - Anti-subsidy investigation concerning imports of "Continuous Cast Copper Wire Rods"
 - Malaysian Investment Development Authority, Incentives in Manufacturing Industry available at <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>

52. Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

- a. During the POI, none of the companies under investigation applied for, accrued or received benefit under the Tariff Related Incentives program.
- b. Petitioners have not given any evidence of benefit conferred on PMAR or PMBTU during POI.

53. Examination by the Authority

- a. The Authority notes that the program is administered by Director General of Customs. The program provides import duty exemption on raw material / component to qualified manufacturer. Exemption is granted when the raw materials / components are not locally available and used directly in the production of the finished product at the approved manufacturer's premise(s).
- b. The Authority notes that the program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due. The program does not qualify to be permissible duty remission program because it provides exemption from import duty for raw material used in all kinds of manufacturing activities and not only for raw materials used in exported products, as provided in footnote 1 of the SCN Agreement and Section 9B(b) of the Customs Tariff Act. The program is specific because it is limited to enterprise that use raw materials that are not available locally. The Authority holds to countervail this subsidy program.
- c. PMAR and PMBTU, the two participating producers/exporters from subject country did not benefit from this program. Thus, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program for PMAR and PMBTU. Authority has determined that exemption from import duty on raw material is countervailable under program No. 18. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed against this subsidy program while working out subsidy margin for residual category.

F.11. Program 11: Allowance for Industrial Building/Industrial Building Allowance (IBA)**54. Submissions by the domestic industry**

- a. IBA is available to a person who has incurred capital expenditure on the construction or purchase of an industrial building which is used for the purpose of the business of that person. IBA is deducted against adjusted income to arrive at statutory income. IBA is generally available to all companies, both resident and non-resident companies; and unincorporated businesses such as sole proprietorships. The initial allowance under the program is 10% and an allowance is 3%. The expenditure can be written off in 30 years.
- b. IBA is granted to companies incurring capital expenditure on the construction or purchase of an industrial building that is used for specific purpose carried on by the company, including manufacturing, agriculture, mining etc.
- c. The evidence of the program relied upon by Petitioners are:
 - Schedule 3 of the Income Tax Act, 1967
 - Anti-subsidy investigation concerning imports of "Continuous Cast Copper Wire Rods"
 - Malaysian Investment Development Authority, Incentives in Manufacturing Industry, available at <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
 - Inland Revenue Board of Malaysia, Qualifying Expenditure and Computation of IBA, Public Ruling No. 3/2018

55. Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

- a. IBA is available to a person who has incurred capital expenditure on construction or purchase of an industrial building which is used for the purpose of the business of that person. IBA is a one-time benefit in the form of tax depreciation.
- b. IBA is a capital allowance given for expenses incurred on industrial building under Schedule 3 Income Tax Act 1967. IBA comprises of Initial Allowance (IA) and Annual Allowance (AA) or AA only at the rate prescribed for each type of industrial building. In general, the rate for IA is given at 10% of the qualifying business expenditure (QBE) and the rate of AA is 3% of QBE unless it is states specifically at a different rate.
- c. Export is not a criterion for granting IBA. IBA is granted to all buildings notwithstanding the use of the building. As such, IBA is also applicable to buildings which are used as warehouses for storage of goods for export or for storage of imported goods which are to be processed and distributed or re-exported.

- d. All companies that meet the eligibility criteria can claim the deductions. This program is available to all companies and the Inland Revenue Board applies objective criteria in granting IBA. Thus, this program does not constitute a countervailable subsidy because it is not specific.
- e. PMAR has used and benefitted from IBA. QBE is incurred by PMAR on the construction/purchase of building used as industrial building for the purposes of the business which made it eligible to claim IBA as deduction to reduce its taxable income over a period of 30 years.
- f. PMBTU has also used and benefitted from IBA. PMBTU is eligible to claim IBA as deduction to reduce taxable income over a period of 30 years on 100% of QBE incurred by PMBTU on construction/purchase of building used as industrial building for the purpose of its business.

56. Examination by the Authority

- a. Authority notes that industrial building allowance (IBA) is available to an entity which has incurred capital expenditure on the construction or purchase of an industrial building which is used for the purpose of the business of that entity. IBA is deducted against adjusted income to arrive at statutory income.
- b. Authority notes that the program does not provide any countervailable benefit because it provides for normal deduction of depreciation on building to all enterprises. Therefore, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program

F.12. Program 12: Allowance of Plant and Machinery

57. Submissions by the domestic industry

- a. Capital Allowance (CA) is a deduction for qualifying expenditure on machinery or plant i.e. relief for wear and tear of fixed assets for business. CA is given only in respect of a business source and the person who incurs the qualifying expenditure and hence is eligible to claim the allowance. CA is calculated for a year of assessment and is deducted from the adjusted income from the business in arriving at the statutory income. Initial allowance is fixed at 20% based on the cost of asset at the time when the capital expenditure is incurred. Annual allowance is a flat rate given every year based on the original cost of the asset and varies accordingly.
- b. The evidence relied upon by Petitioners includes:
 - Schedule 3 of the Income Tax Act, 1967
 - Anti-subsidy investigation concerning imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods”
- c. Following is the eligibility to receive benefits:
 - i. Carry on a business
 - ii. Incurs capital expenditure on plant and machinery
 - iii. The plant and machinery must be used in that business
 - iv. Owner of the plant and machinery at the end of the basis period

58. Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

- a. Neither PMAR, nor PMBTU have applied for, used or benefitted from this program.
- b. There is no Allowance for Plant and Machinery under Income Tax Act. Instead, allowance in the form of CA is given for plant and machinery under Schedule 3 of Income Tax Act.
- c. All companies that meet the eligibility criteria can claim the CA. CA is calculated for a year of assessment and is deducted from the adjusted income from the business in arriving at the statutory income. It is calculated on a straight-line method on the basis of a prescribed rate of allowance.
- d. The IRB applies an objective criterion in granting CA. Thus, this program does not constitute a countervailable subsidy because it is not linked to export conditions, not specific and is generally available.
- e. PMAR and PMBTU had used and benefitted from the program for Allowance for Plant and Machinery/CA. CA is a form of tax depreciation (i.e. deduction of qualifying capital expenditure incurred by PMAR and PMBTU from their taxable incomes). It is a one-time benefit.

- f. The qualifying expenditure incurred by PMAR on capital expenditure for the purposes of the business which made it eligible for PMAR and PMBTU to claim CA as deduction to reduce taxable income over a period of between 4 to 8 years.

59. Examination by the Authority

- a. Authority notes that the allowance for plant and machinery provides deductions for qualifying expenditure on machinery or plant. It is given to enterprise that incurs the qualifying expenditure. It is calculated for a year of assessment and is deducted from the adjusted income from the business in arriving at the statutory income. It is calculated on a straight-line method on the basis of a prescribed rate of allowance.
- b. Responding producers/exporters PMBTU and PMAR have claimed allowance on plant and machinery.
- c. Authority notes that the program does not provide any countervailable benefit because it provides for normal deduction of depreciation on plant and machinery as per straight-line method to all enterprises. Therefore, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

F.13. Program 13: Double deduction for promotion of exports

60. Submissions by the domestic industry

- a. The Petitioners submitted that under this program, expenditure incurred on advertising local brand products domestically is allowed double deduction (expenses incurred on certain activities can be set off twice against taxable profits).
- b. To be eligible, the local brand must satisfy the following criteria:
 - i. The company must be owned more than 50% by registered proprietor of Malaysian brand name
 - ii. The deduction can only be claimed by one company in a year of assessment
 - iii. Brand name is owned by a company which is locally incorporated with at least 70% Malaysian owned
 - iv. Brand name is registered in Malaysia or overseas
 - v. Brand name product must achieve export quality standards
 - vi. Expenditure incurred in advertising must be incurred in Malaysia
 - vii. Expenditure incurred on professional fees must be incurred in Malaysia.
- c. The benefit under this program is export specific, in that the incentives available to manufacturing and agricultural companies producing 'promoted products' or engaged in 'promoted activities.' As evidence of the existence of program, Petitioners have relied on:
 - Section 41, Promotion of Investment Act 1986
 - Rule 4(2) of Income Tax (Promotion of Exports)
 - Anti-subsidy investigation concerning imports of "Continuous Cast Copper Wire Rods"
 - WTO-Notification -G/SCM/N/3/MYS/1986
 - US Carbon Steel Wire Rod from Malaysia
 - WT/TPR/292

61. Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

- a. The correct legal basis of the program is:
 - Income Tax (Deduction for Advertising Expenditure on Malaysian Brand Name Goods) Rules 2002 as amended by Income Tax (Deduction for Advertising Expenditure on Malaysian Brand Name Goods) (Amendment) Rules 2007
 - Section 33 Income Tax Act 1967 (Revised 1971)

- b. Neither PMAR, nor PMBTU has availed, used or benefitted from this program during POI.
- c. Petitioners have not given any evidence of benefit conferred on PMAR or PMBTU during POI.

62. Examination by the Authority

- a. Authority notes that the program is governed by Section 41 of the Promotion of Investments Act (PIA) 1986 (Act 327) & Rule 4(2) of the Income Tax (Promotion of Exports) Rules 1986. Under this program, double deduction from income to enterprise involved in manufacturing, trading and agricultural activities is available for expenses incurred for promotion of export. Expenses incurred by a company for increasing demand for exports are allowed for double deduction.
- b. The Authority notes that the program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due, and benefit is thereby conferred.
- c. The benefit is the difference between the amount of income tax paid after double deduction and the amount income tax that would have been payable in absence of such double deduction. The program is also specific because it is contingent on export performance and is limited to enterprise engaged in export promotion activity. PMAR and PMBTU, the two participating producers/exporters from subject country did not benefit from this program. Thus, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program for PMAR and PMBTU. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against subsidy program granting exemption from income tax. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed for this subsidy program for all other producers/exporters.

F.14. Program 14: Incentives for manufacturing and manufacturing related services in East Coast Economic Corridor

- a. As mentioned in the initiation notice, the program no. 14 has been taken out from the purview of this investigation. Accordingly, this program is not being examined.

F.15. Program 15: Drawback on import duty, sales tax and excise duty

63. Submissions by the domestic industry

- a. The Petitioners submitted that drawback on import duty, sales tax and excise duty that have been paid may be claimed by a manufacturer if the parts, raw materials or packaging materials are used in the manufacture of goods for export within a year based on conditions stipulated in the acts.
- b. Legal basis relied upon by the Petitioners include:
 - Sections 93, 95, 99 of Customs Act 1967
 - Section 29, Sales Tax Act 1972
 - Section 19 and 19A of Excise Act 1976
 - Findings of the Authority in anti-subsidy investigation concerning imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods”

64. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

- a. Neither PMAR nor PMBTU used or benefitted from the program.

65. Examination by Authority

- a. Authority notes that the program is administered by the Royal Malaysian Customs Department. The program provides for refund of import duty levied on inputs that are used in manufacture of goods exported. .
- b. PMAR and PMBTU, the two participating producers/exporters from subject country did not benefit from this program. Thus, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program for PMAR and PMBTU. Authority has determined that exemption from import duty on raw material is countervailable under program No. 18. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed against this subsidy program while working out subsidy margin for residual category.

F.16. Program 16: Exemption from import duty and sales tax for outsourcing manufacturing activities**66. Submissions by the domestic industry**

- a. The Petitioners submitted that this program involves evaluating import duty exemptions on raw materials, components and/or semi-finished products for outsourcing manufacturing activities. This program exists to reduce the cost of doing business and enhance competitiveness for owners of Malaysian brand with at least 60% Malaysian equity ownership who outsource manufacturing activities for certain benefits. Import duty and sales tax exemption on raw materials and components used in manufacturing of finished products by their contractual manufacturers locally/abroad and import duty and sales tax exemption on semi-finished goods from their contract manufacturers abroad are available.
- b. Petitioners relied on Section 14(2) of Customs Act, 1967 and anti-subsidy investigation concerning imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods”

67. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

- a. Neither PMAR nor PMBTU used or benefitted from the program.

68. Examination by Authority

- a. Authority notes that Section 14(2) Customs Act 1967 governs the administration of the program. The program is administered by Malaysian Investment Development Authority. The program provides import duty exemption on raw materials, components and/or semi-finished products for outsourcing manufacturing activities. Raw materials which are used in the production of exported product and semi-finished goods which are imported from contract manufacturers for use by local manufacturers qualify for this exemption.
- b. PMAR and PMBTU, the two participating producers/exporters from subject country did not benefit from this program. Thus, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program for PMAR and PMBTU. Authority has determined that exemption from import duty on raw material is countervailable under program No. 18. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed against this subsidy program while working out subsidy margin for residual category.

F.17. Program 17: Exemption from import duty and sales tax on machinery and equipment**69. Submissions by the domestic industry**

- a. This program involves evaluating import duty exemption on machinery and equipment to qualified manufacturer. To qualify for the exemption, the machinery and equipment must be new, unused and directly used in manufacturing process of finished product at the approved manufacturer's premise(s). In cases where the imported machinery and equipment are taxable but not available locally, full exemption is given on import duty and sales tax. For locally purchased machinery and equipment, full exemption is given on sales tax. The Petitioners relied on Customs Duties (Exemption) Order 2017.

70. Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

- a. The last duty exemption on importation of raw materials used by PMAR was approved in April 2016 and was valid for 3 years until March 2019. Apart from this exemption, PMAR did not avail, use or benefit from this program, including during the POI.
- b. PMBTU did not avail benefit from this program.

71. Examination by Authority

- a. Authority notes that the program is governed by Customs Duties (Exemption) Order 2017. It provides for import duty exemption on new and unused machinery and equipment to qualified manufacturer. There is no exemption from sales tax during the POI because Sales Tax Act 1972 [Act 64] was repealed with the enactment of the Goods and Services Tax Act 2014 [Act 762] entered into force 1 July 2014. The program is administered by Malaysian Investment Development Authority.

- b. Responding producer/exporter PMAR has reported the details of capital goods on which benefit under this program has been availed during the AUL period. The program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due, and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is limited to certain enterprises that import new machinery and equipment for manufacturing activity. The Authority holds that countervailing duty should be imposed against this subsidy program for PMAR. Responding producer/exporter PMBTU has not received any benefit under this program during the AUL period.

F.18. Program 18: Exemption from import duty on raw materials/components

72. Submissions by the domestic industry

- a. Under this program, where finished products are for the export market, full exemption from import duty on raw materials/components is normally granted, provided the raw materials/components are not produced locally, or where they are produced locally, are not of acceptable price and quality. Where the finished products are for the domestic market, full exemption from import duty on raw materials/components that are not produced locally can be considered. Full exemption can also be considered if the finished products made from dutiable raw materials/components are not subject to any import duty. Petitioners relied on Section 14(2) Customs Act 1947 as the legal basis for this program.

73. Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

- a. This program is an exemption from payment of customs duties and sales tax. Raw materials imported by PMAR were zero rated imports and therefore PMAR was not required to apply for duty exemption. PMAR did not apply, use or benefit from this program during POI. PMBTU did not apply for, use, or benefit from the program.

74. Examination by the Authority

- a. Authority notes that the program is governed by Section 14(2) of Customs Act 1967. The program provides for import duty exemption to the qualified manufacturer on raw materials/components that are not locally available. Benefit under this program has not been availed by the participating producers PMAR and PMBTU. Thus, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program for PMAR and PMBTU.
- b. The program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due, and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is limited to an enterprise that uses raw materials that are not locally available.
- c. Therefore, Authority holds to impose countervailing duty against this program for all other producers/exporters from subject countries.

F.19. Program 19: Double deduction for promotion of exports

- a. This program is similar to program No. 13, which has already been examined by the Authority.

F.20. Program 20: Double deduction for promotion of export cargo

- a. As mentioned in the initiation notice, program no. 20 has been taken out from the purview of this investigation. Accordingly, this program is not being examined.

F.21. Program 21: Allowance for increased export

75. Submissions by the domestic industry

- a. Petitioners submit that this program is in the form of a tax incentive granted to companies under Section 154(1) of Income Tax Act 1967 and Rule 3 Income Tax (Allowance for increased exports) Rules 1999 and Income Tax (Allowance for increased exports) (Amendment) Rules 2003 whereby an exporter can avail 70% tax deduction from taxable income for increased exports.
- b. The allowance will be determined as follows:

Manufactured products

- i. 10% of the value of increased exports of the manufactured products of the company where the products exported attained at least 30% of value added;

- ii. 15% of the value of increased exports of manufactured products where products exported attained at least 50% of value added

Agricultural products

- i. 10% of value of increased exports of agricultural produce by the company

76. Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

- a. Neither of the Respondents availed or benefitted from the program. Income Tax (Exemption) (No. 6) Order 2019 mandates the qualifying company to be at least 60% held directly by Malaysian citizen. PMAR is held by PMBTU which is a company, not an individual.

77. Examination by the Authority

- a. Authority notes that a resident manufacturing company or agricultural company that exports manufactured products or agricultural produce is to be given an allowance for increased exports. The allowance is equivalent to 10% or 15% of the value of increased exports of the manufactured products by the company. Allowance will be given against 70% of the statutory business income.
- b. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due. The program is also specific because it is contingent on export performance. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against subsidy program granting exemption from income tax. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty should be imposed against this program.

F.22. Program 22: Tax exemptions for exporters in Free Trade Zones

78. In the initiation notice, the Authority has noted that program no. 22 has been taken out from the purview of this investigation. Accordingly, this program is not being considered in the present case.

F.23. Program 23: Less than adequate remuneration for land and electricity

79. Submissions by the domestic industry

- a. The Petitioners submitted that the Group secured a long-term power purchase agreement at a less than adequate remuneration. Unlike smelters which are dependent on coal-fired or gas-fired power plants, the Group is not subjected to coal and gas price fluctuations. A company can avail special additional incentives for manufacturing projects based in Sarawak. The incentives can be availed by submitting applications to Ministry of Industrial Development.
- b. The Petitioners relied upon the following as evidence of the program:
 - Sarawak Government, Investment Incentives available at https://www.sarawak.gov.my/web/home/article_view/214/229/
 - Sarawak Industrial Estate Development by MID: https://www.sarawak.gov.my/web/home/article_view/213/228/
 - Annual Report, Page 9 available at http://disclosure.bursamalaysia.com/FileAccess/apbursaweb/download?id=193979&name=EA_DS_ATTACHMENTS
 - News Report, available at <https://www.nst.com.my/business/2019/07/508803/press-metal-secures-more-power-expansion>
- c. PMBTU is in Samalaju Industrial Park. As per the official portal of Sarawak, industries which are located in that region enjoy 30% discount for land premium if the project is completed and operations commence within 36 months from the date of land alienation.

80. Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

- a. There is no program for sale of bulk power in Sarawak. Sarawak Energy Berhad (SEB) sells power through arms-length commercial negotiations on a willing buyer, willing seller basis. The relevant

contract is known as ‘Power Purchase Agreement’ (PPA). The sale of electricity to bulk users in Sarawak is conducted on a contractual basis governed by Malaysian law.

- b. SEB is a corporation, governed by an independent Board of Directors and professionally managed by expert staff. Management is mandated to negotiate PPAs with bulk power customers from power intensive industries, including, but not limited to, aluminium. Demand for bulk power typically exceeds SEB’s capacity to supply and power is allocated to those customers that offer the greatest commercial and strategic advantage to SEB.
- c. SEB has also entered into PPA negotiations with potential foreign customers in Sarawak, eg. Japan, Korea, China, Australia, India, among others and with diverse industries (including aluminium, ferro-alloys, polysilicon, copper film etc.) and export of power to neighboring jurisdictions like Indonesian Kalimantan, Brunei and Sabah.
- d. The electricity providers across Malaysia are:

States	Sole Electricity Provider
Peninsular Malaysia (11 states)	Tenaga Nasional Berhad (TNB)
State of Sabah (located in East Malaysia)	Sabah Electricity Sdn. Bhd.
State of Sarawak (located in East Malaysia)	Sarawak Energy Berhad (SEB)

- e. SEB is the sole electricity supplier in Sarawak and the alleged subsidy is available to any person who requires electricity load greater than 5 MW throughout the state of Sarawak. The review of the following terms of PPA indicates that there is no provision of electricity at less than adequate remuneration:
 - i. PMBTU contracted for a long-term commitment of 25 years to purchase electricity from SEB at a certain committed level of consumption;
 - ii. The terms of the purchase of electricity include, inter alia, a ‘take or pay’ term where PMBTU is obliged to consume or pay (even if not consumed) 90% of the committed consumption level;
 - iii. SEB has the right to increase the tariff by way of a Commodity Price Adjustment clause subject to the price of aluminium published in the London Metal Exchange;
 - iv. SEB has escalation clause to enable SEB to increase its tariff by 1.5% on an annual basis. This has also been exercised in fact;
 - v. PMBTU is not entitled to any rebate from SEB in the event the consumption exceeded the committed level;
 - vi. In event of power outage caused by SEB, PMBTU has the right to claim liquidated damages from SEB;
 - vii. PMBTU has borne the cost of constructing the towers and power transmission lines of approximately 7 kilometres outside the premises of PMBTU for last mile connection from SEB’s substation;
 - viii. In the event of termination, the party at default will have to pay the other party liquidated damages.
- f. There is no preferential rate of electricity prescribed for any region or industry by Government of Malaysia.
- g. Regarding allegation of supply of electricity to PMAR at less than adequate remuneration, it is submitted that there is no separate agreement by PMAR with TNB for supply of electricity. Electricity tariff prescribed for industrial units by TNB based on consumption is applicable to PMAR.
- h. There is no separate program of Government of Sarawak for provision of land at LTAR. PMBTU is located in Sarawak region. As PMBTU completed the erection of the building on the Land and

commenced operation of the approved industrial activity within 5 years, PMBTU got eligible for the refund/waiver of the 4th and 5th instalments of premium of the Land.

- i. Provision of land at LTAR is not specific because it is not limited to certain enterprise and eligibility is not discretionary. Eligibility is based on objective criteria which are neutral and horizontal in application.
- j. The alleged discount on land premium is applicable to all lessees of industrial land in Sarawak, provided that criteria such as commencement of operation or erection of buildings within stipulated time set by LSDS are met.
- k. PMBTU has entered into an agreement for provisional lease of state land with Land and Survey Department Sarawak (LSDS), under state of Sarawak from 2011 to 2071. Such discount is applicable to all lessees of industrial land, given the objective criteria set by LSDS are met.
- l. Any allegation on provision of land at LTAR does not even apply to PMAR. PMAR purchased land from private entities and not government entities or entities linked/related to the government.

81. Examination by Authority

- a. Authority notes that allegation of provision of electricity at less than adequate remuneration (LTAR) and provision of land at less than adequate remuneration are required to be examined separately.

Provision of electricity at LTAR

- b. Sarawak Energy Berhad (SEB) is an energy development company in the state of Sarawak. The company is a public limited liability company. The controlling shareholder of the company is State Financial Secretary, Sarawak, a statutory corporation established under State Financial Secretary (Incorporation) Ordinance of Sarawak. SEB is the sole electricity supplier in the Sarawak. SEB enters into Power Purchase Agreement (PPA) with entities in Sarawak with electricity load requirement greater than 5MW. Individual concessional tariff rates are negotiated for entities with load requirement greater than 5MW.
- c. SEB is wholly owned by the Sarawak state government through the State Financial Secretary and provides electricity to entities in Sarawak. SEB is a public body because it is owned by Government and is vested with the Government Authority to carry out governmental function.
- d. Upon review of PPA between PMBTU and SEB (or its wholly owned subsidiary), it is noted that the tariff charged under PPA is not market driven on account of following reasons:
 - i. Standard industrial tariff rates are prescribed by SEB for entities having consumption requirement of upto 5 MW. But, for entities with load requirement of more than 5 MW, SEB (or its wholly owned subsidiary) enters into a separate PPA with each such entity at substantially lower tariff.
 - ii. There are no defined guidelines for determination of tariff rate under PPA and there is no uniformity in the rates offered to various entities entering into PPA with SEB (or its wholly owned subsidiary).
 - iii. In the PPA entered into between PMBTU and SEB (or its wholly owned subsidiary), there is a pre-defined/fixed annual escalation clause. But this annual escalation is not linked to the movement in input prices and/or to the inflation, thereby implying that tariff rates under PPA are not market driven and element of subsidisation is built into such tariff.
 - iv. Government of Malaysia has, either directly or through SEB (or its wholly owned subsidiary), not provided any evidence to demonstrate that the prices charged by SEB (or its wholly owned subsidiary) under the PPA are remunerative i.e., permitting recovery of complete cost incurred.
- e. Authority also notes that Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Research Project Report 2015 titled “Economic Impact of Removing Energy Subsidies in Malaysia” has noted existence of energy subsidies in Malaysia, particularly in supply of electricity. The Report notes that energy demand is largely driven by the stable economic growth and the intentionally low energy prices due to the energy subsidy policy on electricity. The Report further notes that although the

share of electricity and transport fuel subsidy is currently declining, the energy subsidy in Malaysia in 2010 accounted for 4.1 percent of the total GDP, with per-capita subsidy amounted to US\$200 (IEA, 2015).

- f. Authority therefore notes that preferential tariff for electricity supplied by SEB (or its wholly owned subsidiary) through PPA is a financial contribution by the public body in the form of provision of goods or services at less than adequate remuneration. The amount of benefit is equal to the tariff rate charged under PPA and the normal tariff rate applied to other entities outside the PPA arrangement. Questionnaire response filed by PMBTU shows that PMBTU has received benefit under this program because it has entered into PPA with SEB (or its wholly owned subsidiary). The Authority holds to hold that countervailing duty should be imposed against this subsidy program for PMBTU. However, PMBTU is subject to several terms and conditions under the PPA for availing the applicable tariff including the need to incur additional cost for last mile connection. Expenditure incurred by PMBTU pursuant to PPA allocated to the POI is to be deducted while calculating the amount of benefit. Authority has considered both peak and off-peak electricity tariff provided on SEB website while deciding the comparable benchmark tariff rate. It is noted that PMBTU has not specified exact share of off-peak consumption of electricity in its total consumption. Authority has determined the benchmark rate by considering that one-third of electricity consumed by PMBTU is during off-peak hours and the remaining two-third consumption during peak hours.
- g. PMAR is not located in Sarawak and has not availed, used or benefitted from this program during the POI. PMAR has not entered into a separate Agreement/PPA with TNB for supply of electricity. Electricity tariff prescribed for all industries is applicable to PMAR. Thus, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program for PMAR. Authority also holds that countervailing duty should be imposed against this program for all other producers/exporters from Malaysia except PMAR.

Provision of land at LTAR

- h. Authority notes that alienation of land in the Sarawak including determination lease, premium payment, conditions of land use etc. falls within exclusive jurisdiction of the Sarawak State Government. Conditions and restrictions on land in Sarawak are imposed by the Land and Survey Department of Sarawak (LSDS). LSDS grants discount on land premium by way of refund of premium paid or waiver of premium payable upon any lessee meeting certain conditions stipulated in the land lease such as commencement of operation or erection of building/facilities/factories within a stipulated time frame.
- i. Waiver of premium by State Government of Sarawak amounts to financial contribution through provision of goods or services at less than adequate remuneration. The amount of benefit is equal to the difference between the land premium payable by entity and the land premium actually paid after discount/waiver of premium instalment.
- j. Questionnaire response filed by PMBTU shows that PMBTU benefitted from this program. The Authority holds that countervailing duty should be imposed against this subsidy program for PMBTU. PMAR has not availed, used or benefitted from this program during the POI. Thus, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program for PMAR. Authority also holds that countervailing duty should be imposed against this program for all other producers/exporters from Malaysia except PMAR.

G. ADDITIONAL SUBSIDY PROGRAMS CLAIMED BY DOMESTIC INDUSTRY DURING THE COURSE OF THE INVESTIGATION

G.1. Exemption on sales tax on raw material aluminium hydroxide or alumina

82. Submissions by the domestic industry

- a. Sales tax is normally levied on goods imported into Malaysia at a rate of 10%. An order was issued in Malaysia in 2018 exempting aluminium hydroxide or alumina from the levy of sales tax.
- b. Since aluminium hydroxide or alumina are inputs for the product under consideration, benefit is required to be countervailed. The product under consideration is produced in Malaysia after importing alumina without payment of sales tax.

- c. Petitioners are not aware of other inputs that have been imported by Press Metal Group under this scheme or any other scheme where similar benefit has been availed.

83. Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

- a. Sales Tax Order 2018 prescribes 0% sales tax on alumina and aluminium hydroxide. Sales tax is an indirect tax on the products. Rates of sales tax on products are decided by Government of Malaysia.
- b. Rate of 0% sales tax is not specific to any company or entity but on the products themselves. All entities procuring these raw materials will be subject to 0% rate. Deciding tax rates on products is an inherent and sovereign function of Governments in all countries. There is no requirement under the SCM Agreement that all products should be uniformly taxed at equal rates and if a product is taxed lower than other products, it amounts to subsidy for enterprise procuring goods subject to lower tax. This is also recognized in Article 2.2 of the SCM Agreement.

84. Examination by the Authority

- a. Authority notes that sales tax rate on alumina and aluminium hydroxide is prescribed at 0% vide Sales Tax Order 2018. The same rate is applicable on the products in Malaysia for all entities. The sales tax rate prescribed by Government of Malaysia is generally applicable to all entities requiring alumina and aluminium hydroxide. Tax rates prescribed by Government on import or procurement of product does not amount to subsidy because Article 2.2. of the SCM Agreement specifically provides that setting or change of generally applicable tax rates by all levels of government entitled to do so shall not be deemed to be a specific subsidy. Therefore, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program for producers/exporters from Malaysia.

G.2. Benefit of subsidised natural gas through state owned electricity suppliers

85. Submissions by the domestic industry

- a. Tenaga Nasional Berhad (TNB) is the sole supplier of electricity in Peninsular Malaysia and provides electricity to PMAR. TNB has 8 wholly owned power plants; 2 majority owned plants and 1 minority owned power plant operating on gas. SEB, which provides electricity to PMBTU, also owns 3 power plants operating on gas. Hence, both exporters are beneficiaries of subsidised natural gas.
- b. The prices of natural gas, which is the primary source of power in Malaysia, are statutorily regulated for electricity sector. Power is thus available to exporters at less than adequate remuneration. This program, therefore, provides financial contribution in the form of revenue foregone that is otherwise due and benefit is conferred.

86. Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

- a. There was no allegation of subsidy for electricity supplied by TNB in the Petition filed by domestic industry. No investigation can be initiated on such new subsidy allegations.
- b. For TNB, only 31% of electricity is generated using natural gas. There is no separate agreement by PMAR with TNB for supply of electricity.
- c. Even if gas prices in Malaysia are presumed to be subsidised, Petitioners have wrongly presumed pass-through of benefit of such subsidised prices to exporters. WTO Appellate Body in US-Softwood Lumber observed that when raw material supplier receiving the benefit of countervailable subsidies, supplies raw material to another unrelated entity, pass through of benefit of subsidies in favour of unrelated purchaser of raw material cannot be presumed without conducting pass-through analysis. TNB and SEB are not related to exporters and no presumption of pass through of benefit to exporters can be made.

87. Examination by the Authority

- a. Authority notes that TNB is the sole electricity provider in Peninsular Malaysia. Electricity is generated by TNB through natural gas as well as other sources including hydro power, coal etc. Majority of the electricity generated by TNB is through these other sources and not natural gas. PMAR is situated in Peninsular Malaysia and received electricity from TNB.

- b. Authority also notes subsidy program of provision of electricity at less than adequate remuneration has been examined by the Authority. Subsidization of natural gas and procurement of subsidized natural gas by electricity suppliers in Malaysia is not subsidy program under investigation. Even if the natural gas received by these entities is subsidized, there cannot be any presumption of pass through of benefit to entities receiving electricity is absence of further evidence. Authority notes that domestic industry raised new allegation regarding subsidy belatedly and also sufficient information was not provided to support the allegation that benefit of subsidized natural gas by Tenaga Nasional Berhad (TNB) is passed on to entities procuring electricity from TNB during the POI. Therefore, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program for producers/exporters from Malaysia.

G.3. Indirect subsidy on carbon anode received from Government of China PR

88. Submissions by the domestic industry

- a. Press Metal Group together with Sunstone Development Co. Ltd. established a joint venture in China, namely Shandong Sunstone & PMB Ltd. Co. (Sunstone). Sunstone is engaged in the production of pre-baked carbon anode which is a primary raw material for the production of the PUC. 50% requirement for carbon anode of Press Metal is met through imports from Sunstone.
- b. Sunstone has availed various subsidies provided by the Government of China PR to the tune of Yuan 8,645,896,50. These subsidies enabled Sunstone to produce carbon anode at subsidized rate, benefit of which has flown to PUC.

89. Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

- a. New subsidy allegations cannot be investigated by the Authority. PMAR does not use carbon anode for production of PUC.
- b. Subsidies, if any, received by Sunstone from Government of China PR are not subsidies by Government of Malaysia or any other state governments, which is the Government in the country producing and exporting PUC to India.
- c. There can be no presumption of subsidization in favour of Sunstone when China PR is not even included as a country under investigation and no questionnaire response was issued to the Government of China PR.

90. Examination by the Authority

- a. Authority notes that the allegation of subsidization of raw material carbon anode used for the production of PUC is against producers/exporters in China PR and Government of China PR. However, no evidence has been furnished to substantiate this claim. Therefore, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program for producers/exporters from Malaysia.

Producers/Exporters from Malaysia

Press Metal Aluminium Rods Sdn Bhd (“PMAR”) (producer/exporter) and Press Metal Bintulu Sdn Bhd (“PMBTU”) (producer/exporter)

91. PMAR is 100% owned by PMBTU. PMAR produces and sells the subject goods in Malaysia and other countries including India. PMBTU is a subsidiary of Press Metal Aluminium Holdings Berhad and Bunga Raya Aluminium Sdn Bhd is a minority shareholder in PMBTU. PMBTU produces and sells the subject goods in Malaysia and other countries including India.
92. Authority has verified the information provided by Press Metal Aluminium Rods Sdn Bhd and Press Metal Bintulu Sdn Bhd and determined subsidy margin for program nos. 5, 8, 17 & 23 for which benefit was received or accrued during the POI. Authority determined that the subsidy programs 5, 8, & 17 resulted in the provision of financial contribution in the form of revenue foregone which was otherwise due and benefit was thereby conferred. Authority determined that subsidy program 23 resulted in provision of financial contribution in the form of provision of goods or services at less than adequate remuneration by public body and benefit was thereby conferred.
93. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin.

PMAR

Program No.	Name of the program	Brief Description/Comment	Subsidy margin %	Subsidy Margin Range %
Program No. 5	Accelerated Capital Allowance	Accelerated deduction of capital expenditure from taxable income	***%	0-10%
Program No. 17	Exemption from Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment	Exemption on customs duty and sales tax on import of machinery and equipment	***%	0-10%
Total			***%	0-10%

PMBTU

Program No.	Name of the grant program	Brief Description/Comment	Subsidy margin %	Subsidy Margin Range %
Program No. 5	Accelerated Capital Allowance	Accelerated deduction of capital expenditure from taxable income	***%	0-10%
Program No. 8	Pioneer Status	Exemption from income tax	***%	0-10%
Program No. 23	Provision of Land at less than adequate remuneration	Discount on land premium	***%	0-10%
Program No. 23	Provision of Electricity at less than adequate remuneration	Purchase of electricity at lower rate from public body	***%	0-10%
Total			***%	5-15%

94. Subsidy margin determined for PMAR and PMBTU is substantial and above *de-minimis* level. Weighted average subsidy margin for PMAR and PMBTU is as below:

Particulars	Margin	Range
PMBTU	***%	5-15%
PMAR	***%	0-10%
Weighted Average	***%	0-10%

95. Subsidy margin determined for all other producers/exporters is as below:

All other producers/exporters from Malaysia

Program No.	Name of the grant program	Brief Description/Comment	Subsidy margin %	Subsidy Margin Range %
Program No. 1	Market Development Grant	Grant to SMEs for participation in export promotional activity	***	0-10%
Program No. 2	Business/Industry Excellence Award	Grant to Malaysian companies by MITI to recognize their improvement in the quality of products/services offered	***	0-10%

Program No.	Name of the grant program	Brief Description/Comment	Subsidy margin %	Subsidy Margin Range %
Program No. 3	Export Credit Re-financing	EXIM Bank provides loan to enterprise to finance export of products	***	0-10%
Program No. 4	Buyer Credit Guarantee	EXIM Bank provides guarantee to financial institutions against risk of non-payment by their exporters	***	0-10%
Program No. 5	Accelerated Capital Allowance	Accelerated deduction of capital expenditure from taxable income	***	0-10%
Program No. 8	Pioneer Status	Exemption from income tax	***	0-10%
Program No. 17	Exemption from Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment	Exemption on customs duty and sales tax on import of machinery and equipment	***	0-10
Program No. 18	Exemption from import duty on raw materials/components	Exemption on customs duty and sales tax on import of raw material	***	0-10
Program No. 23	Provision of Land at less than adequate remuneration	Discount on land premium	***	0-10%
Program No. 23	Provision of Electricity at less than adequate remuneration	Purchase of electricity at lower rate from public body	***	5-15%
Total			***	10-20%

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions by Domestic Industry

96. The submissions made by domestic industry are as follows:

- The domestic industry has suffered injury due to the presence of subsidized imports from the subject country.
- Volume of imports from subject country has increased significantly, both in absolute and relative terms, despite decline in demand.
- Imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry in the market.
- Capacity utilization has declined after 2017-18 and reached lowest level in the POI.
- Production and sales of the domestic industry have declined in 2018-19 and further in the POI. Though the demand declined by 5%, sales of the domestic industry declined by 14%.
- Market share of subject imports has increased over the injury period while that of the domestic industry declined.
- The domestic industry has been facing financial losses, cash losses and negative ROI in the POI.
- Inventories with the domestic industry have been increasing throughout the injury period.
- Number of employees and wages paid declined over the injury period. However, productivity per employee increased.
- Growth has been negative in almost all injury parameters in the POI.

- k. Price pressure being caused by the subsidized imports either prevented the domestic industry from increasing its prices to the extent of increase in costs or forced it to reduce the prices beyond the decline in costs.
- l. The price depression and suppression effect of subsidized imports from subject country has resulted in significant erosion in profits of the domestic industry.
- m. Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits are directly the result of subsidized imports.
- n. Increase in imports resulted in decline in domestic sales, and consequently decline in production and capacity utilization of the domestic industry.
- o. The export constitutes only ***% of the total sales of the domestic industry. Therefore, decline in export cannot be a factor for decline in production and capacity utilization.
- p. The domestic industry also offers LME based prices.
- q. It is submitted that around 85% of the product under consideration is consumed by electrical conductors manufacturing industry. Central and State electricity boards procure these final conductors for its transmission line requirements. The customers of domestic industry largely fix their prices based on average price of raw material (product under consideration) by Indian industry. Therefore, the users will have no impact of imposition of countervailing duties.

H.2. Submissions by other interested parties

97. The submissions made by other interested parties are as follows:

- a. POI in the present investigation is April 2019 to December 2019 i.e. 9 months, which is inappropriate. It has been the practice of the Authority not to select short period as POI to avoid risk of relying on some abnormality that may prevail during a short period. Therefore, POI should be 12 months or longer.
- b. If full period of 12 months was considered as the POI in the present investigation, the assessment of increase in imports in the POI would have shown that there is no consistent increase in imports during the injury investigation period.
- c. Imports of PUC from Malaysia is attracting 0% customs duty whereas MFN rate of Customs duty applicable on imports of PUC from other countries is 7.5%. The reason for increase in imports of PUC from Malaysia is the benefit of reduction in Customs duty to 0% as compared to other countries and not due to alleged subsidization.
- d. The import data relied by the Applicants is inaccurate due to reliance on annualized POI data. The actual import data of PUC available from DGFT database shows lower imports in 2019-20.
- e. Total imports of PUC into India are only ***% of total Indian production during POI. Import volume of PUC from Malaysia is so low that it cannot create any volume effect on DI.
- f. Price undercutting for imports of PUC from Malaysia has been negative for the last 3 years, including POI. Exports from Malaysia are based on LME prices and not artificially subsidized prices. There is no evidence of price suppression or depression being faced by DI due to PUC imports from Malaysia.
- g. The trend of net selling price and cost of sales of DI do not indicate any continuous price effect due to PUC imports.
- h. Decline in domestic selling price during POI without commensurate decline in cost of sales is not attributable to price pressure from imports as export price of DI has also dropped commensurately during the same period.
- i. There should be some correlation between import price and profit earned/loss incurred by DI to show causal link between imports and performance parameters of DI.

- j. There is no causal link between imports and performance of DI in terms of profits as losses have increased with negative price undercutting for the last 3 years, including POI. Hence, imports are not responsible for decline in profits.
- k. Imports were insignificant in 2016-17 and DI had still incurred losses during that period. Thus, no clear correlation exists between volume of imports and injury to DI.
- l. The DI has also sold subject goods to its related parties in India. The Authority is requested to examine sales made by DI to related parties separately.
- m. Decline in performance of DI, if any, is directly attributable to decline in demand of PUC.
- n. Import price per unit from other countries was substantially lower than import price from Malaysia during the years 2017-18, 2018-19 and POI. The Authority is also requested to examine if injury is due to inter-se competition with the 2 other major domestic producers.
- o. The fact that big producers such as Hindalco and NALCO have not participated, strongly suggests that these entities have deliberately not been included in the present investigation as these other entities may not be suffering any injury at all or injury, if any, is due to factors other than subject imports.
- p. The inclusion of injury information regarding products other than the like article risks distorting the actual injury faced by the domestic industry.
- q. The decline in export sales is a major factor for the decline in the Petitioner's production and capacity utilization.
- r. The flexible pricing policy followed internationally, including by the exporters from Malaysia, is commercially more attractive to and preferred by users. It is for this reason, that the users of the PUC who are not offered the prices linked to the LME spot prices prefer to import the subject goods from the subject country rather than purchase from the domestic industry.
- s. The basic customs duty on import of alumina into India is 10% and for other raw materials the BCD is 7.5%. However, the BCD on the import of the subject goods from Malaysia is 0%. As a result, this creates an inverted duty structure.
- t. The Authority should verify whether internal purchases of aluminium products by Vedanta including "Molten Aluminium Metal" and /or "Aluminium Ingots" within the conglomerate are at arm's length and there is no transfer of injury from other non-PUC segment to the PUC segment.

H.3. Examination by the Authority

98. In the light of above submissions made by the interested parties and the domestic industry, the Authority has examined injury to the domestic industry on account of imports from the subject country. The analysis undertaken by the Authority ipso facto takes into account the submissions made by the domestic industry and opposing interested parties.
99. Rule 13 of the Anti-subsidy Rules deals with the principles governing the determination of injury which provides as follows:

"13. Determination of injury

(1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall give a further finding that the import of such article into India causes or threatens material injury to any industry established in India, or materially retards the establishment of an industry in India.

(2) Except when a finding of injury is made under sub-rule (3), the designated authority shall determine the injury, threat of injury, material retardation to the establishment of an industry and the casual link between the subsidised import and the injury, taking into account inter alia, the principle laid down in Annexure I to the rule.

(3) The designated authority may, in exceptional cases, give a finding as to the existence of injury even where a substantial portion of the domestic industry is not injured if –

(i) there is a concentration of subsidised imports into an isolated market, and

(ii) the subsidised imports are causing injury to the producers of almost all of the production within such market.”

H.3.1. Volume Effect of subsidized imports and impact on domestic industry

i. Assessment of Demand

100. Demand or apparent consumption of product concerned in India is defined as the sum of the domestic sales of all Indian producers and imports from all other countries. The demand so assessed is as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Annualized	Actual
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>105</i>	<i>86</i>	<i>86</i>
Sales of other Indian producers	MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>106</i>	<i>101</i>	<i>89</i>	<i>89</i>
Imports from Subject Country – Malaysia	MT	18,813	37,772	65,904	72,983	54,737
Imports from other Countries	MT	15,623	26,913	27,274	3,419	2,564
Total Indian Demand	MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>111</i>	<i>112</i>	<i>95</i>	<i>95</i>

101. The Authority notes that the demand in India for the subject goods has increased till 2018-19 and thereafter declined during the POI(A).

H.3.2. Import volumes and share of imports from subject country

102. With regard to volume of the subject imports, it is required to be considered whether there has been a significant increase in subsidized imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The details relating to the imports are given below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Annualized	Actual
Subject country – Malaysia	MT	18,813	37,772	65,904	72,983	54,737
Other Countries	MT	15,623	26,913	27,274	3,419	2,564
Total Import Volume	MT	34,436	64,685	93,178	76,402	57,301
Imports from subject country in relation to						
Production	%	3.09	5.82	10.47	13.47	13.47
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>188</i>	<i>339</i>	<i>436</i>	<i>436</i>
Consumption	%	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>181</i>	<i>312</i>	<i>411</i>	<i>411</i>
Total imports	%	55	58	71	96	96

103. It is seen that:

- There has been a significant increase in the absolute volume of imports from subject country in the period of investigation despite decline in demand.
- The imports have increased sharply in relation to production of the domestic industry from 100 indexed points to 436 indexed points.
- The market share of subject imports has increased significantly from 100 indexed points to 411 indexed points.
- The imports are largely from the subject country accounting for 96% share in total imports into India during POI.

H.3.3. Price effect of subject imports and impact on the domestic industry

104. With regard to the effect of subsidized imports on prices, it is required to be examined whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such subsidized imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

i. Price undercutting

105. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the price undercutting has been worked out by comparing the landed price of imports with the selling price of the domestic industry during the injury period. The details of price undercutting are given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Annualized	Actual
Landed price of imports	₹/MT	129,246	151,086	165,616	144,295	144,295
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>117</i>	<i>128</i>	<i>112</i>	<i>112</i>
Net Selling Price	₹/MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>121</i>	<i>134</i>	<i>118</i>	<i>118</i>
Price Undercutting	₹/MT	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>(100)</i>	<i>(59)</i>	<i>(46)</i>	<i>(25)</i>	<i>(25)</i>
Price Undercutting	%	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>Negative</i>	<i>Negative</i>	<i>Negative</i>	<i>Negative</i>	<i>Negative</i>

106. The Authority notes that the price undercutting is negative throughout the injury period including the POI.

ii. Price underselling

107. The Authority has worked out non-injurious price (NIP) of the subject goods and compared the same with the landed value of the imported goods to arrive at the extent of price underselling as under:

Particulars	Unit	Amount
Landed price of imports	₹/MT	144,295
NIP	₹/MT	***
Price Underselling	₹/MT	***
Price Underselling	%	***
Price Underselling	<i>Range</i>	<i>10-20</i>

108. The Authority notes that the price underselling is significant during the POI.

iii. Price suppression/depression

109. In order to determine whether the subsidized imports are suppressing or depressing the domestic prices, the changes in the costs and prices over the injury period have been considered. The position is shown in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Annualized	Actual
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>125</i>	<i>115</i>	<i>115</i>
Selling price	₹/MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>121</i>	<i>134</i>	<i>118</i>	<i>118</i>
Landed price of imports	₹/MT	129,246	151,086	165,616	144,295	144,295
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>117</i>	<i>128</i>	<i>112</i>	<i>112</i>

110. The Authority notes that the landed price of imports is below the cost of sales of the domestic industry during 2016-17, 2018-19 and POI. During the POI, cost of sales has declined by 10 indexed points as compared to 2018-19. On the other hand, the selling price has declined by 16 indexed points during the same period. The imports from subject country are suppressing the price of the domestic industry.

H.3.4. Economic parameters relating to the domestic industry

111. The Anti-subsidy Rules require that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of subsidized imports on domestic producers of like article in India.

112. With regard to consequent impact of subsidized imports on domestic producers of like products, the Anti-subsidy Rules further provide that the examination of the impact of the imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, the performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

i. Production, capacity, capacity utilization and sales

113. The position of the domestic industry over the injury period with regard to production, capacity, capacity utilization and domestic sales is as under:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Annualized	Actual
Capacity	MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>84</i>	<i>84</i>	<i>84</i>
Production	MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>107</i>	<i>105</i>	<i>89</i>	<i>89</i>
Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>107</i>	<i>124</i>	<i>106</i>	<i>106</i>
Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>105</i>	<i>86</i>	<i>86</i>

114. It is noted from the above table that:

- The capacity of domestic industry has declined in the period of investigation. The decline in capacity is because BALCO has discontinued two of its production lines of product under consideration.
- The production and sales of the domestic industry has declined in the POI(A) as compared to base year and well as previous year.
- The production and sales of the domestic industry has declined in the POI(A) which more than the decline in demand in the Indian market.

d. The capacity utilization has increased till 2018-19 and declined in the POI(A).

ii. Market share

115. The market share of the domestic industry and imports over the injury period is as under:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Domestic industry	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	%	100	97	94	91
Other Indian producer(s)	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	%	100	95	90	94
Subject Imports – Malaysia	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	%	100	181	312	411
Other imports	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	%	100	155	156	23
Total Demand	%	100	100	100	100

116. It is seen that the market share of the domestic industry declined throughout the injury period, albeit marginally, whereas the market share of imports from subject country has increased during the same period.

iii. Profit/loss, cash profits, and return on capital employed

117. The position of the domestic industry in terms of profit/loss, cash profits and return on capital employed is as under:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Annualized	Actual
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	110	125	115	115
Selling price	₹/MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	121	134	118	118
Profit/Loss	₹/MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	(100)	(10)	(35)	(89)	(89)
Profit/Loss	₹ Lacs	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	(100)	(11)	(37)	(76)	(76)
PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	376	347	156	156
Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	(100)	127	35	(89)	(89)
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	360	364	201	201

118. It is seen from the above table that:

a. The domestic industry has been suffering losses throughout the injury period. The losses to the domestic industry have increased during the POI (A).

- b. The cash profits follow the same trend as profits. The cash profits of the domestic industry have declined to negative levels during the POI.
- c. The Return on capital employed improved till 2018-19 but declined in the POI (A).

iv. Inventories

119. The data relating to inventories of the subject goods is as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Inventory - Average	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>162</i>	<i>208</i>	<i>1,911</i>

120. It is noted that the average inventories with the domestic industry have increased substantially over the injury period and further in the POI.

v. Employment, productivity and wages

121. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity during the injury period is provided in the table as under:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Annualized	Actual
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>61</i>	<i>71</i>	<i>54</i>	<i>54</i>
Employees	Nos	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>77</i>	<i>74</i>	<i>65</i>	<i>65</i>
Productivity per Employee	MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>139</i>	<i>141</i>	<i>136</i>	<i>136</i>

122. The Authority notes that the employment and wages have declined over the injury period. Productivity has increased over the injury period. The domestic industry has submitted that these parameters are not reflective of the impact of subsidized imports on the domestic industry.

vi. Growth

123. Examination of growth parameters of the domestic industry during the injury period is shown below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (A)
Production	%	-	7.08	(2.38)	(15.11)
Domestic Sales	%	-	7.66	(2.49)	(18.17)
Profit/Loss	%	-	88.90	(229.53)	(108.38)
Cash profits	%	-	226.87	(72.80)	(356.53)
Return on capital employed	%	-	260.19	0.93	(44.84)

124. It is noted that growth has been negative in terms of production, domestic sales, profits, cash profits and return on capital employed in the POI(A). All major price parameters such as profits, cash profits and return on capital employed have also shown a significant decline over the injury period.

vii. Ability to raise fresh investment.

125. The domestic industry has suffered significant losses during the injury period and the period of investigation, which has in turn, weakened the ability of the domestic industry to raise capital investment.

H.3.5. Causal link

126. It has been examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry.

a. Volume and prices of imports from third countries

127. The Authority notes that the volume of imports of the product under consideration from other countries are at *de-minimis* levels.

b. Contraction of demand and changes in the pattern of consumption

128. The demand for the product under consideration has declined in the POI(A). Despite the decline in demand in the country, the volume of imports from subject country has increased. The pattern of consumption has not undergone any material change.

c. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

129. There is no known trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

d. Developments in technology

130. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate any change in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

e. Export performance of the domestic industry

131. It is noted that injury analysis is based on domestic performance. Hence, the injury is not on account of export performance of the domestic industry.

f. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry

132. The Authority has considered data only in relation to the product under consideration.

H.3.6. Factors relevant for causal link

133. The following factors establish causal link between the subsidized imports and the injury to the domestic industry:

- a. Subsidized imports from subject country have increased in absolute terms and in relation to production and consumption in India.
- b. The subsidized imports are causing price suppression/ depression on the prices of the domestic industry.
- c. The production, domestic sales and capacity utilization of the domestic industry has reduced during the POI(A).
- d. There has been deterioration in profits, return on capital employed and cash profits during the POI(A).

H.3.7. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

134. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed price of the imports from the subject country for determination of injury margin during the POI. The injury margin thus determined is as under:

Injury Margin

S.No	Country	Producer	NIP	Landed Value	Injury Margin	Injury Margin %	Injury Margin Range %
1.	Malaysia	(i) Press Metal Bintulu Sdn. Bhd. (ii) Press Metal Aluminium Rods Sdn. Bhd.	***	***	***	***	10-20
2.	Malaysia	All others	***	***	***	***	10-20

135. The level of injury margins as determined are significant.

H. Post-Disclosure Comments

136. The Authority issued a disclosure statement on 18 June 2021 disclosing essential facts of the case and inviting comments from interested parties. The post-disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised in the comments on disclosure statement have already been raised earlier and also addressed appropriately. Additional submissions to the extent deemed relevant have been examined as under:

Submissions made by the domestic industry

- Submissions regarding the non-circulation of supplementary information filed by the responding producers/exporters have not been addressed in the Disclosure Statement.
- Product under consideration should be “Aluminum wire in coil form/ rod in coil form”. PMBTU and PMAR produce Aluminum wire rod in coil form which is known as “wire rod” in technical, commercial and customs parlance.
- Domestic industry produces only wire rod in coil form. It does not produce rod or wire rod which is not in coil form. Aluminum wire rod not in coil form; aluminum rod not in coil form; and aluminum wire in coil form below 7mm dia was excluded by the domestic industry in the Petition.
- Since the product under consideration is imported under various codes, the Authority may indicate the codes in the duty table and specify that the same is indicative only.
- PMBTU and PMAR produce the product of 9.52 mm dia with a tolerance of +/- 0.76 mm. The same product can be exported at less than 9 mm dia. Therefore, the restriction of the product between 9 mm and 12.5 mm is not appropriate. PMBTU and PMAR can circumvent the countervailing duty by exporting the product with diameter downsized upto 7.6 mm. The domestic industry is capable of producing product above 7mm dia and above 12.5mm dia. The description of the product should include the product imported from Malaysia and that which is produced by domestic industry.
- It is the responsibility of exporters and Government of Malaysia to provide information on additional subsidy programs. There is no limitation on the stage at which new information on subsidies can be brought to the notice of the Authority. New information on subsidies was also investigated by the Authority in a previous CVD investigation on “fiberboard”. The evidentiary burden on the domestic industry is only to provide information reasonably available to them.
- PMBTU and PMAR have not provided any information for the AUL period.
- Program Nos. 11 and 12 disproportionately benefit those industries which have high capital expenditure. The programs were previously held countervailable by the Authority.
- In Program No. 15, Authority should examine drawback of sales tax provided under the program as well.

- In Program No. 16, Authority should examine sales tax exemption provided under the program as well.
- In Program No. 23 – Provision of Electricity at LTAR, the expenditure incurred by PMBTU should not be deducted from the benefit. The quantification methodology for PMBTU's electricity benefit should be reconsidered as expenditure for last mile connection is incurred under PPAs and standard terms are not exclusively tied to the program.
- Authority should reconsider the submissions of the domestic industry previously made in relation to provision of electricity by TNB to PMAR at LTAR.
- In Program No. 23 – Provision of Land at LTAR, Authority has not considered that land rent levied is not as per market principles and is less than adequate remuneration. On the land benefit availed by PMAR, the Authority should examine the premium amount and lease rent applicable to PMAR.
- Domestic industry has suffered material injury which has a causal link to the subsidized subject imports.
- PMAR is a 100% subsidiary owned by PMBTU and hence all the subsidy margin arrived for PMBTU should be added on to PMAR as PMAR gets its 100% basic raw material from PMBTU.

Submissions by other interested parties

- The Authority should reexamine import data in light of the revision in scope of product under consideration. Import data initially under consideration included PUC above 7 mm dia. Authority should consider import data of PUC having diameter 9 mm to 12.5 mm in its injury analysis.
- Standing of domestic industry is not established as exact percentage share of Vedanta Industries Ltd. and BALCO in the total production of product under consideration has not been disclosed. There is also no clarification why other major producers – Hindalco and NALCO have not participated in subject investigation. Authority should re-examine representativeness of domestic industry in subject investigation.
- Disclosure Statement does not address (1) whether Vedanta Ltd. imported PUC from any other country during injury period; (2) whether SPTL imported PUC from Malaysia or any other country during injury period.
- Pioneer Status program is not specific because it is available to a wide range of companies ranging from small and medium enterprises to large conglomerates regardless of ownership of company, whether local or foreign owned. A Pioneer Status company can be located within any state in Malaysia, operating in either the primary, manufacturing or services sector spread out across multiple industries.
- Requirement under Rule 11 of the CVD Rules is not met as the Pioneer Status program is not specific to any enterprise or group of enterprises, or to any industry or group of industry given that eligible promoted activities are too wide, diverse, broad and widespread.
- The number of categories, industries, sectors, products or activities eligible for Pioneer Status is too diverse to be considered as a group of industries.
- Program No. 5 and 8 are in the nature of income tax concessions available to all recipients irrespective of region, sector, enterprise etc. These benefits are available on a horizontal basis and follow objective criteria.
- PMAR did not avail, use or benefit from Program No. 17 during POI. The last sales tax exemption for importation of machinery and equipment used by PMAR was approved in 2014 and enjoyed in 2015. PMAR did not avail, use or benefit from this program in 2016-2019.
- Authority should take into account the non-use of the exemption under this program by PMAR between 2016-2019 and that no measurable benefit has accrued to PMAR under this program during the POI, to conclude that no countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

- Authority's assessment of the Power Purchase Agreement (PPA) between PMBTU and SEB is not complete. Authority should conclude that all consumers requiring electricity above 5 MW are eligible for PPA facility and the applicable criteria are objective in nature.
- PPA is a commercial contract negotiated at arm's length between PMBTU and SEB. There is no program for sale of bulk power in Sarawak. SEB sells power through arm's length commercial negotiation on a willing buyer, willing seller basis. Therefore, there cannot be any pre-defined guidelines for tariff rate fixed under PPA.
- SEB cost of sales of electricity per unit in the year 2019 has been provided as per financial statements of SEB and should be compared with the tariff under PPA. Prices charged by SEB under PPA are remunerative because SEB sells electricity at a price higher than its cost price.
- PPA rates are lower than published tariff rates set by SEB because (1) Non-PPA customers obtain electricity from SEB's electricity distribution networks. The cost of distribution networks account for 1/3rd of total cost of production and distribution of electricity; (2) PPA customers do not utilize SEB's electricity distribution networks; (3) Non-PPA customers have no minimum consumption commitment; (4) PPA customers must commit to consume at least 95% of committed quantity failing which they have to pay the minimum commitment of 95% usage; (5) PPA customers commit to purchase in bulk quantities on long term basis for 10-25 years period.
- SEB is a profitable business venture. In 2018, SEB's Audited Financial Statements recorded net profit of MYR 1.28 Billion. If SEB was engaging in any non-remunerative transactions, it would not have earned significant profits.
- PMBTU purchases electricity from SEB in bulk. Majority of SEB's sales of electricity (70%) are to bulk consumers, like PMBTU. This shows that majority of SEB's profits are also owing to bulk consumers like PMBTU. Hence, SEB charges remunerative price to bulk consumers under PPA and makes profits from such sales.
- Benchmark tariff rate chosen by Authority in its subsidy margin determination is not a comparable benchmark because it is based on retail sale of electricity. Article 14(d) of the SCM Agreement requires that adequacy of remuneration be determined based on prevailing market conditions including conditions of purchase and sale. Authority should make downward adjustment to benchmark price to ensure comparability of benchmark price in terms of bulk sale by SEB to PMBTU.
- Benchmark tariff rate chosen by Authority in its subsidy margin determination is also not a comparable benchmark because it does not account for off-peak consumption of electricity by PMBTU. PMBTU operates 24 hours a day, 365 days a year. It has a substantial off-peak consumption of electricity. Therefore, the Authority should adopt a suitable benchmark taking into account the off peak consumption of electricity by PMBTU.
- PMBTU and PMAR have proposed that the Authority should opt for hydropower tariff rate in India as the comparable benchmark in subsidy margin determination. This is because 70% of SEB's electricity generation is from hydropower.
- Provision of land at LTAR is not a countervailable subsidy program. The discount on land premium received by PMBTU is according to objective conditions set by Land and Survey Department of Sarawak ('LSDS'). PMBTU managed to complete erection of the building and commence operation of approved industrial activity within 5 years, and therefore, LSDS allowed PMBTU's application for refund of 4th instalment of premium and waiver of 5th instalment of premium. Such discount is applicable to all lessees of industrial land if the objective criteria set by LSDS are met.
- There is no program by Government of Malaysia for provision of land at LTAR as such; and the eligibility criteria set by LSDS for discount on land premium are objective.
- Determination of subsidy margins by Authority in Program No. 5, 8, 17 and 23 are inconsistent with Article 15.5 of the SCM Agreement as there is no causal link between alleged subsidized imports and injury suffered by domestic industry.

- Authority did not provide sufficient time and opportunity to interested parties to provide comments on Disclosure Statement, contrary to Article 12.8 of the SCM Agreement.
- Total imports of PUC in India are only 14-15% of total Indian production of PUC during POI and cannot cause injury to domestic industry. On the other hand, the domestic producers taken as a whole dominate the market with over 87% share in the POI.
- Domestic industry's selling price increased and decreased in tandem with the increase and decrease in cost of sales in the injury period. Domestic selling prices are uninfluenced by the landed prices of the imports. Thus, there is no price suppression or depression as inferred by the Authority.
- Decline in domestic selling price during POI without commensurate decline in cost of sales is not attributable to price pressure from imports as export price of domestic industry has also dropped commensurately during the same period.
- In 2017-18, domestic industry earned profit while price undercutting was negative. In 2018-19, domestic industry incurred losses even though price undercutting continued to stay negative. Hence, there is no causal link between imports and performance of domestic industry in terms of profits.
- Domestic sales of domestic industry are closely reflecting the domestic demand. Decline in sales over injury investigation period is not attributable to imports of PUC from Malaysia.
- Price competition and injury to domestic industry, if any, is due to imports from other countries. Import price per unit from other countries was substantially lower than import price from Malaysia during years 2017-18, 2018-19 and POI.
- Authority has observed that the capacity of domestic industry has declined in the POI on account of BALCO's discontinuation of two of its production lines of the PUC. At no point of time before the issue of the Disclosure Statement has this fact been brought to the attention of the other interested parties.
- Authority has not considered previous submission that domestic industry is engaged in a trade-restrictive practice where the prices charged by it to the user industry are ad hoc and inflexible as they are not commensurate to the prices indicated by the London Metal Exchange. The domestic industry's prices are higher than the prices on the London Metal Exchange. On the other hand, the prices charged by the producers from Malaysia move commensurate to the prices indicated by the London Metal Exchange.
- If Authority determines that countervailing duty should be recommended, Authority should recommend reference price form of countervailing duty. Ad-valorem form of duty rate will not be appropriate considering the nature of PUC.

Examination by the Authority

137. The Authority notes that most of the submissions made by interested parties are repetitive in nature and were already addressed earlier in the Disclosure Statement. The Authority has examined submissions of interested parties to the extent relevant and not addressed elsewhere.
- As regards the submission concerning non-circulation of supplementary information filed by the responding producers/exporters, Authority notes that no supplementary questionnaire was issued to the responding producers/exporters from Malaysia or the Government of Malaysia. The Authority requested for supporting information/backup documents from responding producers/exporters and Government of Malaysia during the desk verification exercise. It is the consistent practice of the Authority not to disclose the information submitted during verification exercise by foreign producers/exporters to domestic industry and vice-versa.
 - As regards submission concerning scope of product under consideration, the Authority after detailed deliberation with the domestic industry on the scope of PUC has finally determined that product under consideration in the present investigation is "Aluminium Wire in coil form/Wire Rod in coil form having diameter ranging from 9 mm to 13 mm".

- As regards submission to expand the scope of product under consideration to include less than 9 mm dia and more than 12.5 mm dia product, Authority notes that it is an admitted fact in this case that domestic industry has not produced and sold Aluminium Wire/Wire Rod in coil form of less than 9 mm dia during the POI. In the post disclosure comments, domestic industry has submitted evidence that it has produced and sold Aluminium Wire in coil form/Wire Rod in coil form having 13 mm dia during the POI. Therefore, the Authority deems it appropriate to restrict the scope of PUC ranging from 9mm dia to 13 mm dia.
- As regards the submission of the domestic industry regarding additional subsidy programs, it is noted that the Authority has in fact examined all additional subsidy programs for which information was provided by the domestic industry.
- As regards the claim of the domestic industry that PMBTU and PMAR have not provided information for AUL period for subsidy programs, Authority notes that the Responding producers/exporters have provided information for AUL period wherever applicable.
- As regard the submission of the domestic industry that Program Nos. 11, 12, 15 & 16 are countervailable, Authority notes that Program Nos. 11 and 12 are not countervailable because these programs provide for normal deduction of depreciation on building and plant & machinery respectively and hence does not result in foregoing of revenue otherwise due. Authority has determined that no additional countervailing duty should be imposed for Program Nos. 15 & 16 because exemption from import duty on raw material has been countervailed by Authority under program No. 18.
- As regards the submission regarding accuracy of import data, it is noted that the Authority has considered import data of PUC in its injury analysis.
- As regards standing of domestic industry, Authority has determined that production of Vedanta Ltd. and BALCO accounts for a major proportion of domestic production of like article in India as per Rule 2(b) of CVD Rules. There is no requirement for participation of all domestic producers as constituents of domestic industry in a CVD investigation. It is sufficient if the domestic producers having a major proportion in the Indian production have participated in the investigation as constituent of domestic industry.
- As regards submissions concerning imports made by Vedanta Limited and SPTL, Authority notes that neither Vedanta Limited nor SPTL have imported the subject goods from subject country or any other country during POI.
- As regards countervailability of Program No. 5, Pioneer Status program, Authority has determined that the program provides for tax incentive in the form of exemption from income tax and this amounts to a financial contribution in the form of revenue foregone that is otherwise due. The program is also specific as it is available to companies that qualify the eligibility criteria for being a pioneer status company.
- As regards countervailability of Program No. 17, PMAR has availed benefit on its capital goods during AUL period. Hence, Authority has determined that countervailing duty should be imposed against this subsidy program for PMAR for benefit accrued during the POI.
- As regards countervailability of Program No. 23, specifically, Provision of Electricity at LTAR, Authority determines that preferential tariff rate for sale of electricity by SEB through PPA is a financial contribution by public body in the form of provision of goods/service at less than adequate remuneration. Authority has decided to impose countervailing duty against this program for PMBTU. In accordance with Rule 12 read with Annexure IV of the CVD Rules, Authority has deducted expenditure towards additional installation cost for last mile connection incurred by PMBTU pursuant to PPA allocated to POI while calculating amount of benefit. The Authority notes that PMBTU has incurred actual expenditure owing to its obligations under the PPA and not as general expenditure.
- As regards the submission that PMBTU consumes electricity during both peak and off-peak hours and therefore benchmark rate should be suitably modified, Authority notes that there is merit in the submission made by PMBTU. Authority has accordingly modified the benchmark rate considered for determination of benefit under Program No. 23 relating to provision of electricity at LTAR. Authority has considered both peak and off-peak electricity tariff provided on SEB

website while deciding the comparable benchmark tariff rate. It is noted that PMBTU has not specified exact share of off-peak consumption of electricity in its total consumption. Authority has determined the benchmark rate by considering that one-third of electricity consumed by PMBTU is during off-peak hours and the remaining two-third consumption is during peak hours.

- Regarding the claim that electricity supplied by SEB is at remunerative prices and above per unit cost of sales of electricity, Authority notes that information submitted by Government of Malaysia regarding cost of production of electricity is not complete and only a simple tabulated information has been provided without any detailed methodology and evidence about calculation of such cost of production. Authority also notes that cost related information has been provided by Government of Malaysia/SEB only after the issuance of disclosure statement. It is not possible for the Authority to verify the correctness of cost related information at such belated stage. Authority continues to hold that tariff charged by SEB (or its wholly owned subsidiary) from PMBTU under PPA is subsidized.
- Authority also notes that Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Research Project Report 2015 titled “Economic Impact of Removing Energy Subsidies in Malaysia” has noted existence of energy subsidies in Malaysia, particularly in supply of electricity. The Report notes that energy demand is largely driven by the stable economic growth and the intentionally low energy prices due to the energy subsidy policy on electricity. The Report further notes that although the share of electricity and transport fuel subsidy is currently declining, the energy subsidy in Malaysia in 2010 accounted for 4.1 percent of the total GDP, with per-capita subsidy amounted to US\$200 (IEA, 2015).
- As regards the claim that that majority (70%) of electricity produced by SEB is through hydropower and therefore the benchmark rate should be determined based on hydropower tariff in India, Authority notes that there is no requirement to adopt external/out of country benchmark when in-country benchmark is readily available.
- As regards the claim that provision of land at LTAR is not a specific subsidy, Authority notes that it has examined in detail the subsidy program concerning provision of land at LTAR in the subsidy section of the present final findings.
- As regards the submission that subsidy margin arrived for PMBTU should be added on to PMAR as PMAR gets 100% basic raw materials from PMBTU, Authority notes that PMAR purchases basic raw material (Aluminium Ingot) from PMBTU. It is noted that during the POI, 75-80% requirement for Aluminium Ingot was met through imports and only the balance 20-25% requirement for Aluminium Ingot was purchased from PMBTU. The Authority also compared the prices at which PMAR purchased Aluminium Ingot from PMBTU with the import price of Aluminium Ingot and noted that the purchase price from PMBTU was in fact higher than the import price.
- As regards the submission that import price from other countries is lower than import price from Malaysia, Authority notes that import volumes from other countries are substantially lower (less than 5% of total imports into India) than imports from Malaysia during the POI (A). Therefore, imports from other countries are not capable of causing material injury to the domestic industry.
- As regards all other submissions raised by the interested parties regarding material injury and causal link between imports and material injury to the domestic industry, Authority has examined all the issues in the section concerning examination of injury and causal link in these final findings.
- As regards the claim that sufficient time was not provided for responding to disclosure statement, Authority notes that it has provided sufficient time to interested parties to submit their comments in response to disclosure statement. In fact, all interested parties have filed detailed and elaborate submissions and the same have been duly considered in the present final findings.
- As regards the submission that that domestic industry is engaged in a trade-restrictive practice where the prices charged by it to the user industry are ad hoc, inflexible, not commensurate to the prices indicated by the London Metal Exchange and that the domestic industry's prices are higher than the prices on the London Metal Exchange, the Authority notes that the present investigation is a countervailing duty investigation requiring Authority to examine whether or not the imports

into India from subject country are subsidized and causing material injury to the domestic industry.

- As regards the submission of benchmark price based duty, Authority notes that the form of duty is decided by the Authority based on the facts and circumstances of a particular case. The Authority has decided appropriate form of duty in the present case based on the factual matrix of the present case.

I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

138. The Authority recognizes that the imposition of countervailing duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of countervailing duty measures. On the contrary, imposition of countervailing duty measures would remove the unfair advantages gained by subsidization and will prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of countervailing duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of subsidization so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of countervailing duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the countervailing measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

J. CONCLUSION

139. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings, the Authority concludes that:

- Vedanta Ltd. and BALCO constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of CVD Rules.
- The PUC is "Aluminium Wire in coil form/Wire Rod in coil form having diameter ranging from 9 mm to 13 mm".
- The PUC is imported into India from Malaysia at subsidized prices.
- Considering the level of subsidies provided by the Government of Malaysia, the subsidy margin is above de-minimis and significant.
- The domestic industry has suffered material injury. The Authority notes that the imports have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India.
- The price underselling/injury margin of responding producers/exporters is also positive and significant.
- The economic parameters of domestic industry such as production, sales, market share, profit have declined significantly over the injury period.
- The domestic industry has not suffered injury due to other factors. The domestic industry has suffered injury due to imports of subsidized product from the subject country.

K. RECOMMENDATION

140. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties including Government of Malaysia, and adequate opportunity was given to all interested parties to provide information/evidence on the aspects of subsidization, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into subsidization, injury and causal link in terms of the Rules laid down and having established positive subsidy margin as well as material injury to the domestic industry caused by such subsidized imports, the Authority is of the view that imposition of definitive countervailing duty is required to offset subsidization and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive countervailing duty on the imports of the subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder.

141. In terms of provisions contained in Rule 4(d) and Rule 19(1)(b) of the Rules, the Authority recommends imposition of countervailing duty equal to the lesser of margin of subsidy and the margin of injury, so as to remove the injury to the Domestic Industry. The Authority recommends imposition of definitive countervailing duty equal to the amount indicated in Column 7 of table below on all imports of goods described in Column 3 of the duty table originating in or exported from subject country from the date of notification to be issued in this regard by the Central government for a period of 5 years.

DUTY TABLE

S.No.	Heading/ Subheading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount as a % of CIF Value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	76011040, 76012040, 76041010, 76042920, 76051100 and 76052100	Aluminium Wire in coil form/Wire Rod in coil form having diameter ranging from 9 mm to 13 mm	Malaysia	Any country including Malaysia	Press Metal Bintulu Sdn. Bhd.	6.8669%
2.	-do-	-do-	Malaysia	Any country including Malaysia	Press Metal Aluminium Rods Sdn. Bhd.	6.8669%
3.	-do-	-do-	Malaysia	Any country including Malaysia	Any producer other than producers mentioned in S. No. 1 and 2 above	16.4874%
4.	-do-	-do-	Any Country other than Malaysia	Malaysia	Any	16.4874%

L. FURTHER PROCEDURE

142. An appeal against the order of the Central Government that may arise out these Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority